सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

सप्तदश विधान सभा सोमवार, तिथि 17 मार्च, 2025 ई०
चतुर्दश सत्र 26 फाल्गुन, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, लगातार अररिया और मुंगेर में दरोगा की हत्या हो गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, समय पर उठाइयेगा । श्री प्रणव कुमार ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न सं0–''क''–427 (श्री प्रणव कुमार, मुंगेर)

श्री प्रणव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं ।

अध्यक्ष : प्रणव जी, आपका प्रश्न भवन निर्माण विभाग में ट्रांसफर हो गया है ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0–1128 (श्री विजय कुमार खेमका, पूर्णियां)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग (विशेष शाखा) के संकल्प ज्ञापांक–8778 दिनांक–19.09.2016 के तहत राज्य अन्तर्गत उन्हीं मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण किया जाता है, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित हो । प्रश्नगत मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी बात समय पर उठाइयेगा ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा तीन पूरक प्रश्न है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपनी बात समय पर उठाइयेगा, हम कहां कह रहे हैं कि नहीं उठाइयेगा, अब आपलोग बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि हिंदुओं के जो मंदिर हैं और जो काफी प्राचीन हैं और वहां पर काफी कार्यक्रम होते हैं । ऐसे मंदिरों की घेराबंदी के लिए धार्मिक न्यास विभाग से निबंधन जरूरी है । क्या कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए कोई ऐसा नियम है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्वैश्चन आपका नहीं है । प्रश्न से संबंधित बात पूछिए, जो प्रश्न आपका है उससे संबंधित प्रश्न पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित जो मंदिर हैं, उसके बाद भी ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन हैं जहां बारहों महीना धार्मिक आयोजन होता है, क्या ऐसे मंदिर को चिन्हित करके उसके लिए कोई नियम संशोधन सरकार करना चाहती है ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये ।)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । आप सभी लोग बैठ जाइये, समय पर अपनी बात उठाइयेगा ।

श्री बिजेंद्र पसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, धार्मिक न्यास परिषद् एक अलग संगठन है, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह उसमें अपना करवा लें और उसके बाद घेराबंदी की जायेगी ।

अध्यक्ष : पोस्टर हटा लिया जाय ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि ऐसे काफी प्राचीन मंदिर हैं और यह भी मंदिर है । इसको चिन्हित करके, अगर हम लिखकर दें.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको धार्मिक न्यास परिषद् में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा तब होगा, यही सरकार का निर्णय है । अब आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1129 (श्री अजय यादव, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1130 (श्री अजीत कुमार सिंह, डुमरांव)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : (क) आंशिक स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–524 दिनांक–15.07.2015 की कंडिका–'च' में निहित प्रावधान के तहत जे0पी0 आन्दोलन के दौरान भूमिगत रहे अथवा आन्दोलन में योगदान करने वाले व्यक्तियों को पेंशन देय नहीं है बल्कि विहित प्रक्रिया का अनुशरण करते हुए जिला प्रशासनिक समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मात्र प्रशस्ति पत्र एवं प्रतिक चिन्ह दिए जाने का प्रावधान है।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक–661 दिनांक–08.10.2024 द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को भूमिगत श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों/अभिलेख सलाहकार पर्षद कार्यालय से प्राप्त कर मामले में जिला प्रशासनिक समिति की अनुशंसा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए । आप सभी लोग बैठ जाइये, आपलोग अपनी बात समय पर उठाइयेगा, अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, यह बहुत भ्रमित करने वाला जवाब है । अध्यक्ष महोदय, यह जे0पी0 आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें आप सभी लोग जे0पी0 आंदोलन में जेल में रहें, लेकिन जे0पी0

आंदोलन के बहुत सारे ऐसे सेनानी रहें जो भूमिगत रहें, उनके बारे में कई बार सरकारी वायदे हुए लेकिन सरकार का जवाब है कि उन्हें सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा । हम यह पूछना चाहते हैं कि उन भूमिगत जे0पी0 सेनानियों को जिनके घर पर वारंट गया था जो किसी कारणवश जेल में नहीं जा पाये थे, उन्हें सरकार पेंशन देने का विचार रखती है अथवा नहीं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : उत्तर स्पष्ट है कि उनको देने का नहीं है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे और भी सेनानी हैं जो जेल में तो गये लेकिन वे जब जेल से बाहर निकले तो रजिस्टर पर उनका नाम अंकित नहीं हुआ, यह जेलर की गलती से नहीं हुआ । ऐसे बिहार में 74 लोग हैं, बक्सर में ऐसे दो लोग हैं सचिदानंद सिन्हा और नंद गोपाल जी, इन लोगों को भी पेंशन नहीं मिला । महोदय, लगातार कमेटियां बनती हैं और जिस कमेटी के बारे में कहा गया है, जिसकी रिपोर्ट आयी है, उस कमेटी ने बहुत पहले रिपोर्ट दे दी । बावजूद इसके न लोगों को पेंशन मिल रहा है और न ही इन सेनानियों को किसी प्रकार प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है । महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि इनको प्रशस्ति पत्र और शेष जो जेल में गये लेकिन उनके आने की सूची नहीं थी उनको पेंशन देने की व्यवस्था सरकार कब तक करेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पेंशन के लिए स्पष्ट नियम बने हुए हैं, उस नियम के तहत जो आते हैं उन्हीं को पेंशन दिया जाता है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे 74 लोग हैं, जिनकी सूची है उनको तो सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाना चाहिए, सरकार ने घोषणा भी की है, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है तो उनको पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है हम यह जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जो लोग 74 के आंदोलन में जेल गये लेकिन किसी कारणवश रिकॉर्ड में उनका, जेल कह रहा

है कि हमारे यहां उपलब्ध नहीं है, उनका क्या होगा ? माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये । अजीत जी, हमें अच्छा लगा कि आपने यह सवाल खड़ा किया है, आप जिस पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं तब भी आपने 74 आंदोलनकारियों का सवाल खड़ा किया, धन्यवाद, अब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0–1131 (श्री जितेंद्र कुमार, अस्थावां)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : (1) स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि सरमेरा थानार्न्तगत टाल क्षेत्र में कृषि उत्पाद की सुरक्षा हेतु ग्राम–इसुआ, सिंघौल, एवं चेरो में प्रत्येक में एक पुलिस पदाधिकारी एवं चार सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त हैं। साथ ही चार अश्वारोही दल टाल क्षेत्र के सिंघौल, इसुआ एवं चेरो में फसल उत्पादन की सुरक्षा हेतु भ्रमणशील रहते हैं।

(3) उपरोक्त के आलोक में ग्राम इसुआ में ओ0पी0 का निर्माण कराये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : जितेंद्र जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए । आप सभी लोग बैठ जाइये, आप सभी लोग समय पर अपनी बात उठाइयेगा । प्रश्नोत्तर काल का समय, सबका समय है । यह सभी माननीय सदस्यों का समय है, प्रश्नोत्तर काल हो रहा है, आप अपनी बात समय पर उठाइयेगा, आप सभी लोग बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड के ग्राम–इसुआ में हमने ओ0पी0 बनाने की मांग की है और सरमेरा से इसुआ की दूरी 7 किलोमीटर है और जिला का सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है और वहां पर टाल क्षेत्र है महोदय, हमेशा फसल की समस्या, विवाद और भूमि विवाद होता रहता है महोदय, तो क्या सरकार जनहित में, किसान हित में इसुआ में ओ0पी0 बनाने का विचार रखती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट दे दिया गया है कि ओ0पी0 बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कई बार लिखा है कि वहां पर जो समस्याएं रहती हैं, फसल संबंधी विवाद या भूमि विवाद या अन्य फसल लूट की समस्या रहती है तो कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने मेरे पास पत्र है । कई बार लिखा है कि इसुआ में ओ0पी0 बनाया जा सकता है इसकी अनुशंसा की है तो क्या प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो अनुशंसा उसके आलोक में ओ0पी0 बनाने का सरकार विचार रखती है ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट उत्तर है ओ0पी0 बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वहां पर पुलिस की टीम है जो फसल की सुरक्षा का काम देखती है ।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक पदाधिकारियों ने लिखा है, जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी ने लिखा है कि इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है । महोदय, मेरे पास पत्र है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पत्र को दे दीजिए, मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे । अब आप बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1132 (श्री संजीव कुमार, परबत्ता)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : (1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि औद्योगिक कलस्टर, बेगूसराय के अधीन खगड़िया जिलान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र परबत्ता के लिए दिसम्बर 2023 में बियाडा को 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण से प्राप्त हुई जिसमें से 20 एकड़ भूमि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने पर निर्णय लिया गया है परन्तु भूमि की प्रकृति (भूमि का गहरा होने) के कारण बी०पी०सी०एल० द्वारा अभिरूची नहीं ली गयी जिससे आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया गया।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) वस्तुस्थिति यह है की राज्य सरकार अपने स्तर से किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं करती है। इच्छुक निवेशक/उद्यमी

द्वारा संबंधित प्रक्षेत्र में उद्यम लगाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विहित प्रवधान के अनुरूप स्वीकृति एवं सहायता प्रदान की जाती है। यदि उद्यमियों को उद्यम के स्थापना हेतु भूमि के आवश्यकता होती है तो BIADA Land Allotment Policy 2022 के तहत् बियाडा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। प्राप्त आवेदन पर उक्त पॉलिसी में निहित प्रावधान एवं शर्तों के अनुरूप पात्र आवेदक को उद्यम के स्थापना हेतु भूमि आवंटित की जाती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, गलत जवाब आया है । जवाब में दिया गया है कि भूमि गहरा है जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग नहीं लग रहा है । एक्चुअल में अध्यक्ष महोदय वह भूमि नेचुरल है, वह गहरा नहीं है, सड़क ऊंची है । यहां पर उद्योग विभाग के पदाधिकारियों ने उल्टा जवाब दिया है और वहां पर खासकर हमारे खगड़िया में 100 एकड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि हमारे खगड़िया में सबसे ज्यादा मक्का पूरे भारत में होता है और यहां से मक्का हरियाणा, गुजरात और यू0पी0 जाता है, फिर कुरकुरे बनाकर के हमारे यहां बिहार बिकता है तो हमारे यहां थोड़ा सा जो इनलोगों का सिंग्ल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम है लेकिन वह इफेक्टिव एकदम नहीं है और रेट जो वहां पर रखा गया है, रेट एक–एक करोड़ रुपया से ज्यादा पर एकड़ रखा गया है जिससे उद्योगपति वहां पर आना नहीं चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न यह था कि वहां पर जो जमीन दी गयी है, वहां पर 30 एकड़ जमीन दी गयी है इंडियन ऑयल को तो इन्होंने बोला कि हां, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

अध्यक्ष : संजीव जी, आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय इसमें दो–तीन प्रश्न है, मक्का, केला, कपास, मखाना से जुड़े वहां पर उद्योग क्यों लग पा रहे हैं । यह जवाब ही गलत दिया गया है कि....

अध्यक्ष : संजीव जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए कि आप सरकार से क्या जानना चाहते हैं ।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने गलत जवाब दिया है कि वहां पर जमीन गड्ढे में है, जबकि जमीन का एकदम जो नेचुरल है वही जमीन है, रोड ऊंचा में है । कहीं भी 5, 7 फीट तो रोड से नीचे जमीन रहता ही है तो उसको बनाकर के, उसको डेवल्प करके उसको दिया जाये ताकि उद्योगपति वहां पर आयेंगे और उद्योग लगायेंगे ।

अध्यक्ष : संजीव जी, आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूछ ही रहा हूं कि वहां पर क्यों उद्योग नहीं लग रहा है ।

अध्यक्ष : ये तो जनरल बात हो गयी ।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जमीन का दाम कम करने के लिए मैं बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष : संजीव जी, क्या आप यह पूछना चाहते हैं कि सरकार उसको फिर से दिखवाना चाहती है या नहीं ।

श्री संजीव कुमार : जी सर ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी, जवाब दिया जाय ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर गलत नहीं है, वह माननीय विधायक जी की जो भावना है, सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है और माननीय सदस्य को मैं जानकारी दे दूं कि इसी सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री के तौर पर 3 मार्च को इन्होंने बजट प्रस्तुत किया, उसमें फुड प्रोसेसिंग की नई पॉलिसी बनाने की भी उन्होंने घोषणा की है तो जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वह फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो हमारी जब नई नीति आ जायेगी तो स्वाभाविक रूप से निवेशक आकर्षित होंगे ।

क्रमशः

टर्न–2 / यानपति / 17.03.2025

(क्रमशः)

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : महोदय, जो लैंड का इन्होंने विषय बताया है क्योंकि बियाडा जो हमारी ऑथोरिटी है, जो लैंड देती है वह एज इज, व्हेयर इज के बेसिस पर देती है कि जो भूमि जिस रूप में है उसी आधार पर हम देते हैं । 2023 के मंत्री परिषद् के निर्णय के बाद यह 100 एकड़ भूमि हस्तांतरित हुई है और बी0पी0सी0एल0 के द्वारा जो इच्छा व्यक्त की गई थी बाद में भी कि चाहे वह एन0एच0 ऊंचा है, सड़क ऊंचा है, या लो लैंड है उस पर भी हम निर्णय ले रहे हैं और जो बिहार बायो फ्यूल्स हम बनाने जा रहे हैं जिसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री जी ने भी की थी उसमें भी लैंड को सब्सिडाइज रेट पर देने का विभाग विचार कर रहा है । मंत्रिपरिषद् का निर्णय अभी बाकी है तो जो माननीय सदस्य की भावना है, हम इनको स्पष्ट करते हैं कि हमारी जो नई नीति आ जायेगी, साथ ही नई औद्योगिक नीति 2025 भी आनी है एक नया वातावरण बन रहा है तो निश्चित तौर पर जो निवेशक इच्छा व्यक्त करेंगे, जिस स्थान के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं वहां भी हम उद्योग स्थापित करेंगे ।

अध्यक्ष : आपका हो गया ।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, यह पूरे बिहार की बात है तो वहां पर है ही, यहां पर एस0आई0पी0 भी बना हुआ है लेकिन तेलंगाना और उड़ीसा की तर्ज पर काम नहीं हो रहा है, वहां टाइम बांड होता है कि आपको क्लीयरेंस सारा दे देना पड़ता है लेकिन यहां ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो रहता है उसके कारण क्लीयरेंस में ढाई तीन महीना लगता है, बहुत से उद्योगपति ऐसे ही चले जाते हैं...

अध्यक्ष : आपका प्रश्न केवल परवत्ता औद्योगिक क्षेत्र के बारे में है, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न करिए ।

श्री संजीव कुमार : उसी के बारे में है, हम हर समय इतनी तारीफ माननीय मंत्री जी की करते हैं कि मॉस्ट हैंडसम मिनिस्टर उसके बाद भी मेरा उद्योग नहीं लगवा रहे हैं, हर समय तारीफ करते हैं कि इतना स्मार्ट...

अध्यक्षः उन्होंने जवाब तो दे दिया है ।

श्री संजीव कुमार : अब लगवा दीजिए मंत्री जी, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1133 (श्री छत्रपति यादव, खगड़िया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, जवाब नहीं आया है, कंप्यूटर में गलत अपलोड हो गया है, दूसरे माननीय सदस्य का मेरे में आ गया है, गलत जवाब आ गया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है तो इस तरह का कोई प्रस्ताव संभव नहीं है...

अध्यक्ष : माइक पर बोलिये, आवाज नहीं आ रही है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : साफ–साफ लिख दिया गया है, संपूर्ण उत्तर को पूरा पढ़ लेने की जरूरत है, स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री छत्रपति यादव : माननीय मंत्री जी, मुझे जवाब ही नहीं मिला है तो क्या बतायें, माननीय सदस्य देवेश चंद्र जी का मेरे पास आ गया है, कंप्यूटर में । अध्यक्ष जी, जवाब देखा जाय, देवेश चंद्र जी का मेरे पास आ गया है, बता तो दें मंत्री जी पढ़कर के ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

(व्यवधान)

पूछ रहे हैं, हम उसको दिखवाएंगे ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मोरकारी थाना, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों जैसे माडर उत्तरी, माडर दक्षिणी, भदास उत्तरी एवं भदास दक्षिणी, पुरानी पंचायत कोठिया, कासिमपुर को हटाकर नवसृजित अलौली पुलिस अनुमंडल में समावेश किया गया है ।

क्या यह सही है कि भदास उत्तरी एवं भदास दक्षिणी पंचायत कोठिया पंचायत (पूर्व) मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ता था जिसकी दूरी 5 से 7 कि0मी0 थी जबकि उक्त पंचायतों को गंगौर थाना क्षेत्र में जोड़ दिया गया है जिसकी दूरी 10 से 12 कि0मी0 पड़ती है जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ता है । यह मेरा प्रश्न है, इसमें कोई जवाब ही नहीं आया है विभाग से तो क्या बतायें, जवाब तो पढ़ दें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्पष्ट उत्तर दे दिया गया कि जो माननीय सदस्य चाहते हैं वह संभव नहीं है ।

अध्यक्ष : संभव नहीं है ।

श्री छत्रपति यादव : नहीं–नहीं, संभव क्यों नहीं होगा अध्यक्ष जी, करना पड़ता है न । पहले जब विधि–व्यवस्था थी, जबसे वहां ट्रांसफर हुआ तबसे वहां रोज मर्डर हो रहा है, रोज घटना हो रही है, 12 कि0मी0 दूरी पर गंगौर पड़ता है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए । सरकार ने कहा है कि जो आपने प्रश्न पूछा है वह क्रियान्वित करना संभव नहीं है ।

श्री छत्रपति यादव : संभव तो सरकार को करना पड़ता है, हर चीज सरकार करती है प्रावधान बदल कर के, अचानक इसको किया गया है, अभी तक तो वही चल रहा था 2023 के पहले क्या है...

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री छत्रपति यादव : भदास उत्तरी एवं भदास दक्षिणी तथा बछौता पंचायत को मुफस्सिल थाना तथा पुरानी पंचायत कोठिया (अब नगर परिषद् खगड़िया) को नगर थाना क्षेत्र खगड़िया में जोड़ने का विचार रखती है, इस पर विचार करना है ।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा कि नहीं रखती है विचार । बैठ जाइये ।

श्री छत्रपति यादव : तो कैसे होगा, रोज घटना घट रही है ।

श्री अजय कुमार : सवाल यह है कि...

अध्यक्ष : छत्रपति जी, बैठिए ।

श्री अजय कुमार : मुफस्सिल थाना के नजदीक 3 कि0मी0 पर है और उसके आप 12 कि0मी0 दूर थाना गंगौर से जोड़ते हैं तो लॉ–एंड–ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है इसलिए कठिनाई क्या है, यह जानना चाहते हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पंचायत का डिवीजन करके अलग–अलग थाने में नहीं किया जा सकता है, यह संभव नहीं है इसीलिए स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री इजहारूल हुसैन ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुफस्सिल थाना से पहले जुड़ा हुआ था, उसको करने में व्यावहारिक दृष्टिकोण से क्या दिक्कत है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1134 (श्री इजहारूल हुसैन, किशनगंज)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए इजहारूल जी ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप महाप्रबंधक कृषि व्यवसाय इकाई, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति बिहार के पत्रांक–470, दिनांक–11.03.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त केंद्र पर प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नांकित बैंक सुविधा उपलब्ध पाई गई, दामलबाड़ी बाजार केंद्र पर भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के 10 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं ।

पोठिया बाजार केंद्र पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं बंधन बैंक की शाखा उपलब्ध है साथ ही केंद्र से 07 कि0मी0 की दूरी पर चनागमाना और 08 कि0मी0 की दूरी पर रतनपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा कार्यरत है । केंद्र पर भारतीय स्टेट बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के 07 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं । सत्तरगाछ बाजार केंद्र पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और बंधन बैंक की शाखा कार्यरत है । भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 07 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं । 06 कि0मी0 की दूरी पर आराबारी में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा और 05 कि0मी0 की दूरी पर बैंक आफ बड़ौदा की शाखा कार्यरत है । उक्त स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नई शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक की समीक्षा प्राधिकार है, मूलतः बैंक शाखा आउटलेट खोलने का निर्णय बैंक के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य एवं वाणिज्य अर्हता के आधार पर लिया जाता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री इजहारूल हुसैन : मेरा पूछना है, इनका उत्तर आया है कि दामलबाड़ी हाट में बैंक है, मैं कहता हूं कि बैंक नहीं है, वहीं का निवासी हूं सर, पैतृक पंचायत भी है लेकिन वहां कोई बैंक नहीं है, यह गलत रिपोर्ट आई है, वही बात, छत्तरगाछ और पोठिया बाजार की है, मैंने वहां स्टेट बैंक की मांग की है सर वहां, स्टेट बैंक दिया जाय और दामलबाड़ी पंचायत में कोई बैंक नहीं है, एक बैंक है जो बताया आपने ग्रामीण बैंक...

अध्यक्ष : सरकार ने कहा सेवा केंद्र है ।

श्री इजहारूल हुसैन : नहीं सर, वहां कुछ नहीं है । दूसरी बात, जहां बताया, वह बैंक ऑफ बड़ौदा, एक नदी है, लगभग वहां से 10 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है, नदी

पार होकर जाना पड़ता है और दामलबाड़ी, छत्तरगाछ, पोठिया एक व्यापारिक मंडी है और हर दिन...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री इजहारूल हुसैन : पूछता हूं सर । कब तक सरकार चाह रही है, लाखों का आदान–प्रदान होता है, लोग परेशान हैं, इस समय मैं पूछता हूं, कब तक बैंक दिया जायेगा ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट है और 10–10 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत है और 07 कि0मी0 के रेडियस में तीन बाजार है, तीनों में पर्याप्त बैंक की सुविधा है इसके बावजूद यदि माननीय विधायक और माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो मैं जरूर बैंकों को निर्देशित करूंगा कि समीक्षा जरूर कर ली जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1135 (श्री ललन कुमार, पीरपैंती)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री ललन कुमार : उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 स्वीकारात्मक ।

खंड–2 अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच तनाव की कोई स्थिति नहीं है ।

खंड–3, प्रश्नगत कब्रिस्तान जिलास्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है, कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि वहां मिश्रित आबादी है, काफी मिश्रित है और उसी कारण अक्सर विवाद होता रहता है एन्क्रोचमेंट को लेकर के, तो थोड़ा अपने से ध्यान रखकर के उसकी घेराबंदी करा दें तो वहां पर शांति बहाल हो सकेगी ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

टर्न–3/अंजली/17.03.2025

तारांकित प्रश्न सं0–1136 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, पिपरा, पूर्वी चंपारण)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : उप–महाप्रबंधक (कृषि व्यवसाय इकाई), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार के पत्रांक–468, दिनांक–11.03.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार संदर्भित केन्द्र के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक की 2 शाखाएँ, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, तेतरिया बाजार एवं बैंक आफ इंडिया, मधुआहा ब्रित कार्यरत है ।

इसके अलावे संदर्भित केन्द्र एवं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में भारतीय स्टेट बैंक का 4 ग्राहक सेवा केन्द्र, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं बैंक आफ इंडिया का 2–2 ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत है ।

उपरोक्त बैंक शाखा एवं ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से पूर्वी चम्पारण जिला के अंतर्गत तेतरिया बाजार के निवासियों को नगदी आहरण सहित अन्य आवश्यक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं ।

उक्त स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नई शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक ही सक्षम प्राधिकार है। मूलतः बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यवसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

अध्यक्ष : श्यामबाबू जी, पूरक पूछिये ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया गया है कि तेतरिया बाजार के 5 किलोमीटर के दायरे में दो बैंक है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह नहीं बताया गया है कि उस बैंक में कितने अकाउंट होल्डर हैं ? बैंक ऑफ इंडिया वहां बीच में है, ग्राहकों का बहुत ज्यादा दबाव है । वहां देखा जाएगा तो सैकड़ों की संख्या में लोग लाईन में लगे रहते हैं, वहां इतना ज्यादा दबाव है और वहां व्यवसायी भी हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर केंद्रीयकृत खोलवाने का प्रस्ताव सरकार भेजना चाहती है ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आवेदन लेकर उसको समीक्षा करवाता हूं कि वहां यदि आवश्यकता होगी तो जरूर कार्रवाई करेंगे ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–1137 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, आरा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में काफी संवेदनशील है । ऐसे तथ्यों पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार विशेष सतर्कता बरती जा रही है तथा निगरानी रखी जा रही है । कोई ऐसा मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई हेतु सभी जिलों में तथा 03 हवाई अड्डों पटना, गया एवं दरभंगा में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में मानव व्यापार निरोध इकाई का गठन किया गया है ।

2–उपर्युक्त कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

3–उपर्युक्त कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, जो जवाब प्राप्त हुआ है, मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही था कि सरकार इस प्रकार के अपराधों के प्रति कितना गंभीर है और यदि गंभीर है, तो उन्होंने क्या और कौन–सी कार्रवाई की है ? महोदय, उत्तर में ऐसा कुछ भी नहीं है ।

अध्यक्ष : बैठिये । आप प्रश्न पूछे तो माननीय मंत्री जी जवाब देंगे न ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय मंत्री जी अत्यंत ही वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्होंने जो जवाब दिया है वह सपाट और बिल्कुल नकारात्मक जवाब है ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । आप पूछ दिये न तो बैठ जाइए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अमरेन्द्र बाबू का जो उत्तर है वह लगता है पता नहीं क्या है ? वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में काफी संवेदनशील है । ऐसे तथ्यों पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार विशेष सतर्कता बरती जा रही है तथा निगरानी रखी जा रही है । कोई ऐसा मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई हेतु सभी जिलों में तथा 03 हवाई अड्डों पटना, गया एवं दरभंगा में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में मानव व्यापार निरोध इकाई का गठन किया गया है । अब इसमें क्या कंफ्यूजन है कि कार्रवाई नहीं हो रही है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, प्रश्न तो उसी में से न खड़ा है । मेरा तो यही जानना था कि...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मेरा यही पूरक है कि आपने कौन–सी कार्रवाई की है ? मानव व्यापार निरोध इकाई का गठन किया तो कब किया है और इसकी उपलब्धि क्या है, इसने काम किया है, कितना काम किया है ? महोदय, गरीब बच्चों को उठाकर के और उनको इस अपराध में झोंका जाता है तो वे छोटे बच्चे बड़े होकर बड़े अपराधी बन रहे हैं, क्या दशा होगी इस पर गंभीरता से और यह बात उठनी चाहिए । महोदय, मैंने दैनिक जागरण का जो समाचार है उसके कटिंग को दिया है और उसमें भी जो जानकारी प्राप्त है अखबार को उसमें भी उल्लेख है कि झारखंड के और पश्चिम बंगाल के और अपराधियों को पकड़ा गया है उन सरगनों को, तो तीनों राज्यों की पुलिस मिलकर इस प्रकार की क्या कोई योजना बना रही है ? महोदय, यह भी हमारा प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी । बोलिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : यदि कोई योजना है तो माननीय मंत्री जी बता दें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्पष्ट उत्तर मैंने दिया है कि सभी जिला में गठन किया गया है, अब हवाई अड्डे पर भी हो रहा है और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि क्या कार्रवाई हुई है, उसके लिए अलग से प्रश्न पूछें कि क्या–क्या हुआ है उसको दिया जाएगा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, ये उत्तर है ?

अध्यक्ष : सरकार सजग है । सरकार पूरी तरह सजग है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं । महोदय, आप संरक्षक हैं, उत्तर दिलवा दीजिए । संतुष्ट तो कर दीजिए हमको ।

अध्यक्ष : आपकी भावनाओं को माननीय मंत्री जी ने सुना है और उसका ध्यान रखेंगे।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1138 (श्री अखतरूल ईमान, अमौर)</u>

अध्यक्ष : श्री अखतरूल ईमान जी, पूरक पूछिये ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हस्तांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ट्रांसफर हुआ है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, चूंकि मसला गृह विभाग का है ।

अध्यक्ष : आएगा ।

श्री अखतरूल ईमान : अब कब आएगा महोदय ?

अध्यक्ष : अभी दस दिन हाउस है । बैठिये ।

श्री अखतरूल ईमान : वहां सी0एम0 सेक्रेटेरियट का जो विष्णु कुमार है वह जमीन पर कब्जा किया हुआ है । इन्हीं के विभाग का मसला है महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये । श्रीमती निक्की हेम्ब्रम ।

तारांकित प्रश्न सं0–1139 (श्रीमती निक्की हेम्ब्रम, कटोरिया)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1140 (श्री भाई वीरेन्द्र, मनेर)

अध्यक्ष : आपका प्रश्न शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हुआ है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अगली बार में आएगा । पहला नंबर पर आ जाएगा उसमें क्या है ?

तारांकित प्रश्न सं0–1141 (श्री अरूण सिंह, काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक । उप–महाप्रबंधक (वित्तीय समावेशन), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार के पत्रांक–462, दिनांक–06.03.2025 से

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वैशाली जिलान्तर्गत प्रखंड–पातेपुर में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की एक–एक शाखा कार्यरत है ।

2– वैशाली जिलान्तर्गत प्रखंड–पातेपुर के बाजार पातेपुर के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकों के शाखा के अतिरिक्त निम्न बुनियादी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है–

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पातेपुर से लिंक 5 ग्राहक सेवा केन्द्र एवं 1 एटीम, बैंक आफ इंडिया, बाजितपुर शाखा से लिंक 1 एटीम, स्टेट बैंक आफ इंडिया, मालपुर शाखा से लिंक 4 ग्राहक सेवा केन्द्र, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, पातेपुर शाखा से लिंक 5 ग्राहक सेवा केन्द्र।

इसके अलावे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 4 केन्द्र भी संदर्भित स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद है ।

उपरोक्त बैंक शाखा एवं ग्राहक सेवा केन्द्रों के माध्यम से यहाँ के निवासियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

3– बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक ही सक्षम प्राधिकार है । मूलतः बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यवसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

अध्यक्ष : अरूण बाबू, पूरक पूछिये ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि पातेपुर में एक राष्ट्रीयकृत बैंक खोला जाए । वहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक है लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर सप्ताह में एक दिन पासबुक अपडेट होता है, एक ही दिन पैसा जमा होता है, तो मेरा मांग था कि एक और बैंक वहां खोला जाय लेकिन अब जो ग्राहक केंद्र खोला गया है वहां ग्राहक केंद्र में मात्र 10 हजार रुपया निकलता है, 5 हजार रुपया निकलता है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ? पूरक पूछिये ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, हमारा प्रश्न है कि वहां एक और राष्ट्रीयकृत बैंक खोला जाय।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एक ही दिन कार्यरत होता है तो मैं जरूर निर्देशित करूंगा कि विशेष तौर पर कि ये वर्किंग डे में सभी दिन वहां काम करें और इसको जरूर समीक्षा करा लेता हूं ।

तारांकित प्रश्न सं0–1142 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक–05/06, फरवरी 2025 की रात्रि में नीलाम पत्र के वारंटियों के विरूद्ध विशेष समकालीन अभियान के तहत छापामारी हेतु जयनगर थाना से पु०नि०–सह–थानाध्यक्ष अमित कुमार, पु०अ०नि० शुभम कुमार, पु०अ०नि० संतोष कुमार, पु०अ०नि० शेषनाथ प्रसाद पु०अ०नि० मुकेश कुमार, परि०पु०अ०नि० मोनिका कुमारी के साथ सशस्त्र बल के पुलिस वाहन एवं चालक के साथ थाना से प्रस्थान किये थे। छापामारी के क्रम में नीलाम पत्र पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर वाद सं0–2159/23–24 के वारंटी अमरजीत कुमार एवं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधुबनी के नीलाम पत्र वाद सं0–86/19–20 के वारंटी प्रदीप पासवान को गिरफ्तार किया तथा स्थानीय चौकीदार–01/08 सूर्यनाथ यादव के साथ जयनगर यूनियन टोला बाजार समिति के पास से विजय कुमार सिंह जिनसे पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वे ऋण लिये हुए हैं, जिनके सत्यापन हेतु उनसे आधार कार्ड की मांग करने पर आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया । तत्पश्चात उन्हें सिरिस्ता में बैठाया गया ।

खंड–2 वस्तुस्थिति यह है कि सुबह में विजय कुमार सिंह के परिजन आधार कार्ड के साथ थाना पर उपस्थित हुए, जिसके अवलोकन करने से पता चला कि उक्त विजय कुमार सिंह जो नीलाम पत्र वाद के वारंट से भिन्न है ।

वारंट में विजय कुमार सिंह के पिता का नाम चन्द्रभूषण सिंह अंकित है जो उक्त व्यक्ति के पास के ही दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें सत्यापन के उपरांत विजय कुमार सिंह को जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधुबनी के नीलाम पत्र वाद सं0–09/18–19 में गिरफ्तार कर संबंधित कार्यालय को भेजा गया तथा विजय कुमार सिंह को निजी मुचलका बनवाकर मुक्त किया गया ।

एक ही जगह के दो नाम के व्यक्ति होने के कारण विजय कुमार सिंह को सत्यापन हेतु थाना लाया गया था, जिन्हें जयनगर थाना द्वारा निजी मुचलका पर मुक्त किया गया।

कंडिका–''1'' एवं ''2'' में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, अरूण शंकर प्रसाद जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, उत्तर प्राप्त है एक प्रश्न का और 1209 जो मेरा दूसरा प्रश्न है गृह विभाग का उसके उत्तर के बदले छत्रपति यादव जी का उत्तर आ गया था मैं उनको भेज दिया हूं ।

अध्यक्ष : आपके पास अपना उत्तर उपलब्ध है न ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मेरा उपलब्ध नहीं है । पहले प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : उत्तर उपलब्ध है तो पूरक पूछिये न ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, इसमें मुझे माननीय मंत्री जी से यही जानना है आपके माध्यम से कि विजय कुमार सिंह और विजय कुमार सिंह, पिता–चंद्रभूषण सिंह ये दो व्यक्ति हैं तो विजय कुमार सिंह, पिता–चंद्रभूषण सिंह के बदले विजय कुमार सिंह को रात के दस बजे जो एक सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, उनकी पत्नी जिला पार्षद रही हैं, ऐसे लोगों को रात के 10:00 बजे पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और सुबह 12 से 1 बजे तक उसको थाने के...

(व्यवधान)

हल्ला करने का विषय नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : थाने के हाजत पर बैठाकर रखती है और ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मेरा आग्रह होगा कि माननीय सदस्य लोगों को जो उत्तर भेजा जाता है उसको समुचित रूप से पढ़ें कृपा करके । अब मैं पढ़ रहा हूं देखिए स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ।

वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक–05/06, फरवरी 2025 की रात्रि में नीलाम पत्र के वारंटियों के विरूद्ध विशेष समकालीन अभियान के तहत छापामारी हेतु जयनगर थाना से पु०नि०–सह–थानाध्यक्ष अमित कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक शुभम कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक शेषनाथ प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार, परि० पुलिस अवर निरीक्षक मोनिका कुमारी के साथ सशस्त्र बल के पुलिस वाहन एवं चालक के साथ थाना से प्रस्थान किये थे । छापामारी के क्रम में नीलाम पत्र

पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर वाद सं0–2159/23–24 के वारंटी अमरजीत कुमार एवं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधुबनी के नीलाम पत्र वाद सं0–86/19–20 के वारंटी प्रदीप पासवान को गिरफ्तार किया तथा स्थानीय चौकीदार–01/08 सूर्यनाथ यादव के साथ जयनगर यूनियन टोला बाजार समिति के पास से विजय कुमार सिंह जिनसे पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वे ऋण लिये हुए हैं, जिनके सत्यापन हेतु उनसे आधार कार्ड की मांग करने पर आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया । तत्पश्चात उन्हें सिरिस्ता में बैठाया गया ।

खंड–2 वस्तुस्थिति यह है कि सुबह में विजय कुमार सिंह के परिजन आधार कार्ड के साथ थाना पर उपस्थित हुए, जिसके अवलोकन करने से पता चला कि उक्त विजय कुमार सिंह जो नीलाम पत्र वाद के वारंट से भिन्न है ।

वारंट में विजय कुमार सिंह के पिता का नाम चन्द्रभूषण सिंह अंकित है जो उक्त व्यक्ति के पास के ही दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें सत्यापन के उपरांत विजय कुमार सिंह को जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधुबनी के नीलाम पत्र वाद सं0–09/18–19 में गिरफ्तार कर संबंधित कार्यालय में भेजा गया था तथा विजय कुमार सिंह को निजी मुचलका बनवाकर मुक्त किया गया ।

एक ही जगह के दो नाम के व्यक्ति होने के कारण विजय कुमार सिंह को सत्यापन हेतु थाना लाया गया था, जिन्हें जयनगर थाना द्वारा निजी मुचलका पर छोड़ दिया गया । स्पष्ट कर दिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, जब पुलिस समझ गई कि मैं गलत पकड़ कर ले आया..

अध्यक्ष : छोड़ दिया ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, छोड़ दिया लेकिन निजी मुचलका बनाकर छोड़ा । यह कौन सा न्याय है ? अपराधियों के साथ पुलिस नरम हो जाय और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करे तो क्या यही फ्रैंडली पुलिस है महोदय।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

टर्न–4 / आजाद / 17.03.2025

तारांकित प्रश्न सं0–1143(श्रीमती शालिनी मिश्रा, केसरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। इसके अधीन दो अल्पसंख्यक बालक छात्रावास पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय में चल रहा है । वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए माननीय सदस्या ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, मेरा प्रश्न था केसरिया, संग्रामपुर, कल्याणपुर प्रखंड के बारे में, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अल्पसंख्यक छात्रावास जिला मुख्यालय में बनता है और उन्होंने बताया है कि आपके जिले में दो बना है । जिला मुख्यालय में अगर बनता है तो इस बजट में माननीय वित्त जी ने कहा कि छात्रावास बन चुका है, 50 तो हमारे जिले भी नहीं हैं, एक्सेपशनल केसेज में जिला में बने हैं तो क्या माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र कुछ पंचायत केसरिया एवं संग्रामपुर प्रखंड में, वहां पर एक्सेपशनल केस में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाना चाहते हैं और दूसरा मेरा एक पूरक और है कि इन्होंने लिखा है कि दो बालक छात्रावास है तो मैं कहना चाहती हूँ कि बालिका छात्रावास भी माननीय मंत्री जी कम से कम हमारे क्षेत्र में बनाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : बैठ जाईए ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : महोदय, यह प्रावधान नहीं है कि प्रखंड में बनाया जाय, लेकिन जिला के अन्दर में है, बालिका छात्रावास के लिए हम उसको देखवा लेते हैं और आगे उसको हम बनवायेंगे ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, माननीय मंत्री जी कम से कम एक बनवा दें हमारे विधान सभा क्षेत्र में ।

अध्यक्ष : अब बैठिए । श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

तारांकित प्रश्न सं0–1144(श्रीमती प्रतिमा कुमारी, राजापाकर)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग । जवाब पढ़ दीजिए, इनको जवाब नहीं मिला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला का देसरी पुलिस अंचल कार्यालय, अंचल कैम्प महनार से संचालित हो रहा है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि देसरी पुलिस अंचल कार्यालय का भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण अंचल कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हो सका है। नया कार्यालय के लिए भूमि एवं भवन निर्माण हेतु पुलिस उप–महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया गया है ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कब तक हो जायेगा, चूँकि भूमि वहां पर है और किसानों को भी नोटिश दिया गया है लेकिन सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जमीन ज्योंही उपलब्ध हो जायेगी, कार्रवाई होगी ।

तारांकित प्रश्न सं0–1145(श्री अचमित ऋषिदेव,रानीगंज,अररिया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1146(श्रीमती मनोरमा देवी,बेलागंज)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1147 (श्री अवध विहारी चौधरी,सिवान)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत –

1. सदर प्रखंड के ग्राम–मोहिउद्दीननगर, जियांय, पिठौरी, टडवॉ, रामपुर, बलेथा एवं धनौती में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है ।

2. बड़हरिया प्रखंड के ग्राम पकड़ी, लकड़ी टोले इजामाली, बंगरा बुजुर्ग, कैलचुलाई हाता एवं लकड़ी दरगाह में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं की गई है । उल्लेखनीय है कि बंगरा बुजुर्ग में कब्रिस्तान रैयती भूमि पर अवस्थित है ।

3. सदर प्रखंड के अमलौरी, खालिसपुर, मौलानगर, सियाड़ी एवं फुलवरिया कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं की गई है ।

4. पचरूखी प्रखंड के ग्राम–चकिया में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है ।

5. उपर्युक्त उप कंडिका–2, 3 एवं 4 में उल्लेखित कब्रिस्तान प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

अध्यक्ष : जवाब दिया हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा मेरे प्रश्न का जवाब प्राप्त करा दिया गया है । मैंने सिवान जिला में कब्रिस्तान घेराबंदी से संबंधित प्रश्न किया और मैं माननीय मंत्री जी ने 2, 3, 4, 5 खंडों में जवाब देने का काम किया है .....

अध्यक्ष : यानी विस्तार से माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब देने का काम किया है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : जी, जवाब आया है । परन्तु मैं क्षेत्र में गया हूँ और देखा हूँ कि कहां–कहां घेराबंदी है और कहां–कहां नहीं है, उसको मैंने स्वयं घुमकर देखा हूँ । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय को भी पत्र दिया था और सिवान के जिला पदाधिकारी को भी पत्र दिया था कि यह आवश्यक है, इसकी घेराबंदी की जाय परन्तु जो जवाब आया है, जो चीज मैंने ऑख से देखा है और जवाब आया है कि घेराबंदी करा दिया गया है । अन्य के बारे में कहा गया है कि जिला में प्राथमिकता सूची कलक्टर और एस0पी0 के संयुक्त बैठक के बाद तय की जाती है कि कहां घेराबंदी की जाय और संवेदनशीलता के आधार पर घेराबंदी की जाती है । बहुत खंडों में आपने कहा है कि घेराबंदी नहीं हुई है परन्तु जो सूची है, उसमें यह सम्मिलित नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या एक बार पुनः अपने स्तर से जो जवाब आपने दिया है, उस जवाब में मैं

पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, चूँकि मैंने ऑख से देखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने किसी उच्चस्थ पदाधिकारी से सिवान जिला और जहां के लिए मैं दिया हूँ, 105 विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं जीत कर आता हूँ, उसकी जॉच करा लेंगे?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, हम उसकी पूरी समीक्षा करके इसको देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाईए । पूरी समीक्षा करेंगे, आपने जो आग्रह किया है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ ।

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है आपका ?

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, व्यवस्था यह है कि मैं कब्रिस्तान घेराबंदी का मामला लेकर आया तो दूसरे विभाग में भेज दिया गया, जबकि यह मामला पूरी तरह से गृह विभाग का है.....

अध्यक्ष : आप जैसा पूछते हैं उसपर निर्भर करता है । अब आप बैठिए । कोई आपसे झगड़ा है, कोई झगड़ा नहीं न हो सकता है, क्यों झगड़ा होगा, जो सवाल आता है, उसका जवाब आता ही है । जवाब आने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है । अब आप बैठिए ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, मुझे संरक्षण दिया जाय ।

अध्यक्ष : पूरा संरक्षण है आपको, जवाब आयेगा तो आपका आयेगा । अभी तो 10 दिन हाउस है, फिर गृह विभाग आने वाला है । अब आप बैठिए । श्री मनोहर प्रसाद सिंह, पूरक पूछिए ।

तारांकित प्रश्न सं0–1148 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, मनिहारी)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : उत्तर प्राप्त नहीं है, जवाब पढवा दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, जरा इनका उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में बिहार के कटिहार जिले में बिहार राज्य में लागू बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से आच्छादित खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में कुल 03 ईकाइयॉ कार्यरत है । साथ ही 03 इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस एवं 10 ईकाईयों को स्टेज–1 क्लीयरेंस प्रदान की गई है ।

किसानों को मक्का का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा इसका न्यूनतम बाजार मूल्य (एम0एस0पी0) निर्धारित किया गया है, जो रू0 2225 (दो हजार दो सौ पच्चीस रूपये) प्रति क्विंटल है ।

राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति में निहित प्रावधानों के तहत सहायता प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, सरकार के स्तर से इसपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है ?

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, यही तो पूछ रहा हूँ कि सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है ?

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट कहा, इनका स्पेशीफिक प्रश्न कटिहार जिला से था । सरकार के द्वारा उद्योग की स्थापना नहीं की जाती है, सरकार के द्वारा नीति का निर्धारण किया जाता है । कटिहार में तीन फूड प्रोसेसिंग इकाईयां पहले से कार्यरत हैं, तीन को वित्तीय क्लीयरेंस अभी हमलोगों ने दिया है और 10 को अभी स्टेज–1 क्लीयरेंस दिया गया है । जितनी भी औपचारिकतायें हैं, चाहे वह स्वीकृति या एप्रुवल की होती है, वह गवर्नमेंट के स्तर पर होती है और कोई भी इकाई अगर किसी पॉलिसी के तहत आच्छादित होता है तो उसमें जो प्रावधान है इनसेंटिव की या सब्सिडीज की, वह सरकार देती है । सरकार एक इको सिस्टम बनाती है, वातावरण बनाती है, जिसमें कोई निजी निवेशक आयें और वे उद्योग की स्थापना करें और मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि बिहार में ही जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पोस्ट कोविड स्कीम की घोषणा की गई थी तो फूड प्रोसेसिंग के लिए स्पेशीफिक स्कीम की शुरूआत की और बिहार में 10हजार से अधिक इकाईयां आज उसमें कॉवर्ड हैं और 2000 करोड़ से अधिक का निवेश उस पॉलिसी के तहत हुआ है तो फूड प्रोसेसिंग हमारा बिहार का एक स्ट्रैन्थ वाला

सेंटर है और हम नई पॉलिसी भी जल्द लाने वाले हैं तो उस पॉलिसी के बाद ही बिहार के कमोबेश सभी क्षेत्रों में जहां फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने की संभावना रहेगी, वहां पर उद्योग की स्थापना के लिए निवेशक आकर्षित होंगे।

टर्न–5 / पुलकित / 17.03.2025

तारांकित प्रश्न सं0–1149 (श्री राजेश कुमार, कुटुम्बा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना के संयुक्तादेश दिनांक–16.12.2024 के आलोक में न्यू बाईपास, जीरो माईल, अनीसाबाद, एम्स गोलम्बर पटना में नो एन्ट्री लागू है । नो एन्ट्री हटने के पश्चात यातायात का दबाव रहता है, जिसके नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक, यातायात के कार्यालय ज्ञापांक–500, दिनांक–14.02.2025 के आदेश से जगह–जगह पोस्ट निर्धारित कर यातायात के सुगम संचालन हेतु नौबतपुर एन0एच0–139, एम्स गोलम्बर, जीरोमाईल एवं अन्य सबंधित पोस्ट पर तीन पाली में पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी प्रतिनियुक्ति किए गए हैं ।

पिछले दो माह में जीरोमाईल, खगौल सगुना यातायात ओ0पी0 से यातायात का उल्लंघन करने वाले कुल 5,467 वाहन से 1,19,45,000 / – (एक करोड़ उन्नीस लाख पैंतालीस हजार) रू0 की राशि शमन की गई है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, राजेश जी ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर ऑनलाईन आया है और जो मेरा प्रश्न है उसका यह उत्तर नहीं है । सरकार का जो उत्तर आया है वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना के संयुक्तादेश दिनांक–16.12.2024 के आलोक में न्यू बाईपास, जीरो माईल, अनीसाबाद, एम्स गोलम्बर पटना में नो एन्ट्री लागू है । नो एन्ट्री हटने के पश्चात यातायात का दबाव रहता है । महोदय, यही प्रश्न मैंने किया था कि रात्रि में 9 बजे के बाद जब नो एंट्री हटती है तो पूरे शहर की गाड़ियां एक साथ होती है तो इस पर सरकार दबाव कह रही है इसका मतलब दबाव है । लेकिन मेरा जो पूरक है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री राजेश कुमार : मेरा पहला पूरक है कि क्या आप 9 बजे की जो पुरानी व्यवस्था है, उस पुरानी व्यवस्था पर चलाने का सरकार विचार रखती है या नहीं ? दूसरा, पूरक मेरा यह है कि कितने लोगों पर शुल्क उल्लंघन का लगा है । उत्तर में लिखा हुआ है कि 5467 लोगों को हम दंडित किये हैं और 1,19,45,000/– (एक करोड़ उन्नीस लाख पैंतालीस हजार) रुपये की हम वसूली किये हैं । मेरा सीधा पूरक यह है कि जो पुरानी व्यवस्था ट्रैफिक नियम की थी, जो दिनांक 16.12.2024 के पहले पुरानी व्यवस्था थी । उस पुरानी व्यवस्था को लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पुरानी व्यवस्था क्या थी ? माननीय सदस्य एक बार उसे लिखकर दे देंगे तो हम इसको दिखवा लेंगे ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पुरानी व्यवस्था यह थी कि सारी गाड़ियां नो एंट्री की वजह से एम्स से निकलती थी और पुराने बाईपास होकर के, जीरो माईल होकर के गंगा पार जाती थी । गंगा पार से जो भी गाड़ियां आती थी उसमें जिनको इधर जाना हो वह जाती थी । महोदय, परिचालन हमारा स्मूथ रहता था । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहूंगा कि पुरानी व्यवस्था में कभी–भी यह अव्यवस्था नहीं थी । अब गया से आने वाली गाड़ी जीरो माईल रूकती है, उधर मुजफ्फरपुर से आने वाली गाड़ियां सब आकर गांधी सेतु पर रूकती है और इधर एम्स में गाड़ियां रूकती है । ये जो सारी व्यवस्था है, सरकार भी मान रही है कि ट्रैफिक का दबाव रहता है तो पुरानी व्यवस्था सरकार लागू कर दें । अध्यक्ष महोदय, पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाए ।

अध्यक्ष : अब आपका पूरक हो गया ।

श्री राजेश कुमार : माननीय मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : आपके बैठेंगे, उसके बाद ही मंत्री जी बोलेंगे । माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसे आप दिखवा लीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, हम दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–1150 (श्रीमती रश्मि वर्मा, नरकटियागंज)

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, पूछती हूं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : कृपया माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग । उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री कृष्णनंदन पासवान, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक है ।

2– अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 के अधीन गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति के तहत् चीनी मिलों द्वारा पेराई प्रारम्भ करने के साथ ही सर्वेक्षण के अनुसार शुरूआत में प्रीमियम प्रभेद के खूँटी एवं शरदकालीन रोप के मोरहन गन्ने (क्रमशः प्रीमियम, सामान्य एवं निम्न) का चालान निर्गत करते हुए ईख आपूर्ति प्राप्त किया जाता है । एक वर्ष के गन्ने को मोरहन गन्ने के खेतों का सर्वेक्षण होता है । एक वर्ष से अधिक गन्ना खूँटी के रूप में मिल के रिकॉर्ड में सर्वेक्षण में दर्ज की जाती है ।

गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति के अन्तर्गत खूँटी गन्ने को प्राथमिकता देते हुए गन्ना तौल चालान मिल द्वारा निर्गत किया जाता है ।

सभी चीनी मिलों द्वारा सट्टा नीति एवं निर्गत कैलेण्डरिंग के अनुरूप समानुपातिक रूप से सभी प्रभेदों/खूँटी/मोरहन के गन्ने का उठाव किया जाता है तथा निर्धारित दर पर गन्ना कृषकों को ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है ।

3– खंड–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, न जाने किन लोगों ने यह जानकारी सदन को दी है, यह जानकारी गलत है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि प्रत्येक किसान के प्लॉट की पैमाइश की जाती है और प्रत्येक वर्ष का, एक वर्ष के उपरांत गन्ना के खूँटी का चालान निर्गत नहीं किया जा रहा है । यह बात किसानों द्वारा लगातार मुझे जानकारी मिल रही है और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को भी यह जानकारी मिल रही होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, मेरा पूरक है कि किसानों के प्लॉट का आधा–अधूरा चालान दिया जाता है । सिर्फ एक वर्ष जो प्रीमियम खूँटी का चालान है वही दिया जाता है, दूसरे वर्ष का नहीं मिल रहा है और तीसरे वर्ष का भी नहीं मिल रहा है । एक ही वर्ष का प्रीमियम प्रभेद का चालान मिलों द्वारा निर्गत किया जा रहा है, जिससे किसानों की कृषि बाधित है । साथ–साथ में आर्थिक क्षति पहुँच रही है और यह गंभीर विषय है ।

अध्यक्ष : आपके तीन प्रश्न हो गये हैं ?

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, अंत में मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह प्रीमियम प्रभेद के साथ–साथ खूँटी सहित सभी किसानों की खरीदारी सुनिश्चित की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या के सवाल को एक बार दिखवा लीजिए ।

श्री कृष्णनंदन पासवान, मंत्री : महोदय, दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : जो माननीय सदस्या ने पूरक पूछा है उसको दिखवा लीजिए और बाद में उनको बताइयेगा भी । आप दोनों चम्पारण से ही है ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, बहुत गंभीर विषय है । जी, हम चम्पारण से ही है ।

श्री कृष्णनंदन पासवान, मंत्री : जी महोदय ।

अध्यक्ष : चम्पारण के लोग दोनों आपस में बात करिये ।

श्री कृष्णनंदन पासवान, मंत्री : ठीक है, हुजूर ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है । चम्पारण के साथ–साथ पूरे बिहार का विषय है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आप कहां जायेंगे उधर ? बैठिये ।

तारांकित प्रश्न सं0–1151 (श्री मुकेश कुमार रौशन, महुआ)

अध्यक्ष : मुकेश जी, आपका प्रश्न ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर हुआ है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों से मेरा यह प्रश्न दो बार आया और दोनों बार यह प्रश्न स्थानांतरण कर दिया जाता है । आखिर वैशाली जिला के महुआ में और चेहराकलां के प्रखंडों में सरकार आई0टी0 भवन बनाना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : परसों, ग्रामीण विकास विभाग का ही प्रश्न रहेगा ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, दो–दो बार ट्रांसफर हुआ है । जब–जब हम प्रश्न करते हैं तब–तब ट्रांसफर हो जाता है ।

अध्यक्ष : परसों आने तो दीजिए । बैठ जाइये ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : बोलिये, क्या व्यवस्था है ?

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, आप इस हाऊस के कस्टोडियन हैं । सर्वत्र दृष्टि आपकी रहनी चाहिए ।

अध्यक्ष : है, आपकी ओर है ।

श्री विजय शंकर दूबे : माननीय सदस्य जब सवाल करते हैं, उसका उत्तर सरकार नहीं दे पाती है ।

अध्यक्ष : उत्तर कहां नहीं दिया ?

श्री विजय शंकर दूबे : और आसन का निदेश होता है कि देख लीजिए । सरकार देखती नहीं है ।

अध्यक्ष : सरकार पूरा देखती है ।

श्री विजय शंकर दूबे : ऐसे प्रश्नों का उत्तर....

अध्यक्ष : पूरा देखती है सरकार । सब तरफ देखती है । बैठ जाइये ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, इस पर व्यवस्था आप कीजिए । आसन ऐसे कैसे...

अध्यक्ष : बैठिये । माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत ।

तारांकित प्रश्न सं0–1152 (श्री कुमार सर्वजीत, बोधगया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । उक्त कब्रिस्तान में अतिक्रमण नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, सर्वजीत जी ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है वह कब्रिस्तान । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सूची में शामिल करने का तरीका क्या है ? क्या इन पांच वर्षों में कौन–कौन ऐसे बिहार में जिला है जो संवेदनशील कब्रिस्तानों को सूची में शामिल कराने का....

अध्यक्ष : आपका प्रश्न किसी एक पर्टिकुलर कब्रिस्तान के बारे में है ।

श्री कुमार सर्वजीत : जी ।

अध्यक्ष : पर्टिकुलर कब्रिस्तान के बारे में आपका प्रश्न है । इसको आप पूरा व्यापी बनायेंगे तो बाद में सरकार जवाब देगी ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन बार इस सदन का सदस्य हो गया हूँ । एक ही जवाब आता है कब्रिस्तान के बारे में कि प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है इसलिए विधायक कोटा से करा लीजिए । शामिल कब होगा ?

अध्यक्ष : प्राथमिक सूची में जो शामिल है वही होगा विधायक कोटा से ।

श्री कुमार सर्वजीत : हुजूर, शामिल कब होता है, कैसे होता है ? यह तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे ।

अध्यक्ष : उत्तर में लिखा हुआ है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, अगर शामिल होता है तो माननीय सदस्यों की उसमें कोई भूमिका होती है क्या ?

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य खुद भी मंत्री रहे हैं । प्राथमिकता सूची में शामिल करने का कॉन्स्पेट यह है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी का कि विवाद से बचा जाए । जहां विवाद, टेन्शन की परिस्थिति रहती है, उसको कलेक्टर, एस0पी0 की अध्यक्षता वाली कमेटी प्राथमिकता सूची को शामिल करती है । जहां टेन्शन नहीं है । पहले से भी कब्रिस्तान चल रहा है, घेराबंदी अगर नहीं होती थी तो क्या वहां आफत आ जाती थी ? यही पैरामीटर है कब्रिस्तान की प्राथमिकता सूची का । बारी–बारी से....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप इधर देखकर बोलिये । आप उधर कहां देख रहे हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : कोई सुनने को तैयार नहीं है और न कोई पढ़ने को तैयार है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इधर देखकर बोलिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसलिए प्राथमिकता सूची का यही आधार है, बारी–बारी से सबको किया जाएगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, हमने पांच कब्रिस्तान का प्रश्न किया है । पांच कब्रिस्तानों का कम से कम अभी तक पांच बार एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी है, हिन्दु, मुसलमानों के झगड़े का । तीन–तीन दिन वहां पर कैम्प लगा है कि यह झगड़ा मिट जाना चाहिए । जिलाधिकारी से पूछा गया तो कहा गया कि हमने गृह विभाग को लिख दिया है । जब मुकदमा हो गया, आपकी प्राथमिकता यही है कि जब शांतिभंग होगी तो घेरेंगे । जब प्राथमिकता यही है तो घेराबंदी होनी चाहिए, हुजूर । यही तो मैं कह रहा हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी, एक बार दिखवा लीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, हिन्दू–मुस्लिम के टेंशन में प्राथमिकता सूची होती है । कोई व्यक्तिगत झगड़ा होता है तो उसको प्राथमिकता सूची में..

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक बार दिखवा लीजिए, उन्होंने विशेष कहा है ।

श्री कुमार सर्वजीत : मेरा दूकान तो नहीं है हुजूर । मैंने कहा कि कब्रिस्तान है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : गया का मामला है, आप कहां से आ गये ।

श्री कुमार सर्वजीत : हुजूर, मैंने कहा कि कब्रिस्तान को लेकर कई बार झगड़े हो गये हैं । वैसे ही कब्रिस्तान का माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं जहां पर कई बार झगड़े हो ही जाते हैं । हम बस आपसे चाहते हैं हुजूर कि क्या माननीय सदस्यों को यह अधिकार दिया जाय कि प्राथमिक सूची में शामिल करने के लिए हम जिलाधिकारी को, बतलायें जिलाधिकारी को कि भाई इसमें हिन्दू–मुस्लिम का झगड़ा होता है तो आप जरा देख लीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : दे दीजिए । आवेदन दे दीजिए और उसकी एक कॉपी हमको भी दे दीजिए, दिखवा लेंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : आवेदन तो हुजूर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कैसे जा सकते हैं । एक पार्टिकूलर प्रखंड का जिक्र है । नहीं, पूरे बिहार का विषय नहीं है ।

माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1153 (श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सिकटा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1– आंशिक स्वीकारात्मक।

2– वस्तु–स्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। पूर्व में उक्त कब्रिस्तानों के संबंध में उत्पन्न विवाद के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, पटना में दायर वादों यथा–CWJC No.-

9586/2024 राकेश प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा CWJC No.-17923/2024 उमाशंकर यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित निदेश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

3– कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, मेरा भी कब्रिस्तान की घेराबंदी वाला सवाल है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, वीरेन्द्र जी ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं । पूर्व माननीय मंत्रीजी का जो प्रश्न था उसी नेचर का यह भी प्रश्न है । हमारे यहां एक लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान है और एक नगरदेही कब्रिस्तान है जिसका विवाद हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट ने पुनः उसको जिला प्रशासन को दे दिया और अभी मंत्रीजी का उसमें जो जवाब है कि ये डी0एम0 और एस0पी0 द्वारा बनायी गयी कमेटी उसको तय करती है कि वह घेराबंदी वाली सूची में जायेगा । हम माननीय मंत्रीजी से पहला यह प्रश्न करना चाहते हैं कि जो देश के हालात हैं, हाईकोर्ट तक झगड़े गये, पिछले साल वहां एक आदमी के शव को दफनाने के लिए भी विवाद हुआ..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय । हमने जो दो पार्टिकूलर, आपने, जब जेनरलाईज्ड बात की जाती है तो आप कहते हैं कि पार्टिकूलर करिए । हम पार्टिकूलर बात कर रहे हैं कि सी0डब्लू0जे0सी0 जो हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में जो मामले चले हैं उसका जिक्र किया है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : हम यह कहना चाहते हैं कि ये दो कब्रिस्तानों को संवेदनशील मानती है या नहीं ? यह हमारा पहला सवाल है और उसको प्रथमिकता सूची में जोड़ेगी की नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्पष्ट जवाब दिया गया है कि हाईकोर्ट के मामले पर कार्रवाई की गयी है बाकि प्राथमिकता सूची में नहीं है, प्राथमिकता सूची में आयेगा तो करवाया जायेगा ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, यह जवाब नहीं हुआ । आप कह रहे हैं कि विवाद है और उस पर शव दफनाने को लेकर भी विवाद हो जायेगा, उसको भी आप कह रहे हैं कि डी0एम0, एस0पी0 तय करेंगे । डी0एम0, एस0पी0 क्या सरकार से ऊपर हैं महोदय । यह सरकार निर्देश नहीं दे सकती है ।..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उनको बैठा दें ? पहले यह तय कीजिए न, उनको बैठा दें ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : सरकार क्या यह निर्देश नहीं दे सकती है कि वहां के डी0एम0, एस0पी0 उसको प्राथमिकता सूची में जोड़े । उसके घेराबंदी का प्रस्ताव भेंजे । क्या डी0एम0, एस0पी0 सरकार से ऊपर हैं ? यह हम जानना चाहते हैं महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, उनको पूछने नहीं दें । प्रश्नकर्ता को पूछने नहीं दें । आपलोग बोलिएगा तो वे कैसे पूछेंगे । कैसे जवाब देंगे ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : हमने पूछ दिया है महोदय ।

अध्यक्ष : भाई ! पहले अपने लोगों को कहिए आप ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : हमने पूछा है मंत्री जी से जवाब चाहिए महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बढ़ जायें आगे । आपलोग प्रश्नकर्ता को पूछने नहीं देंगे । आपलोग बैठिएगा तब न पूछेंगे । आप पूछने नहीं दे रहे हैं । हम तो कह रहे हैं बठिए वे जवाब देंगे । अब बताइये कैसे होगा । आप ही लोग तय कर लीजिए । पहले बैठिएगा तब न वे पूछेंगे । वीरेन्द्र जी को सवाल करने नहीं देना चाहते हैं आपलोग । सवाल करने दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

अरे भाई ! मंत्रीजी जवाब कैसे देंगे, जब इतने सारे लोग खड़े हैं । पहले प्रश्नकर्ता पूछेंगे कि बाकी लोग पूछेंगे । खड़े रहिएगा तो कैसे जवाब होगा । इतने लोग एक साथ बोलिएगा तो जवाब कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है । जब आपलोग बैठिएगा तभी विरेन्द्र जी का जवाब होगा । इतने लोग खड़े हो गये हैं तो कैसे जवाब होगा, बताइये आप ही । बैठेंगे लोग तभी न जवाब होगा । अभी आप प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं होने दे रहे हैं । प्रश्नकर्ता को आपलोग बोलने नहीं दे रहे हैं । बताइये आप ही, बिना प्रश्नकर्ता

के कैसे होगा । प्रश्नकर्ता को बोलने नहीं दे रहे हैं । आपलोग जवाब चाहते ही नहीं हैं । सवाल करने वाले को तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हैं ।

माननीय सदस्य मुकेश कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1154 (श्री मुकेश कुमार यादव, बाजपट्टी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रसलपुर बाजार से बाजपट्टी थाना की दूरी 12 कि0मी0 है । सुरसण्ड थाना की दूरी 08 किलोमीटर है । पुपरी थाना की दूरी 10 कि0मी0 है तथा चोरौत थाना की दुरी 12 कि0मी0 है । रसलपुर बाजार में वर्तमान में विधि–व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है । स्थानीय थाना से लगातार गस्ती किया जाता है एवं डॉयल 112 का ठहराव भी रसलपुर बाजार में रहता है । रसलपुर बाजार एवं अगल–बगल के क्षेत्रों का विगत पांच वर्षों का अपराध आंकड़ा हत्या–03, लूट–01, डकैती–01, गृहभेदन–03, साधारण अपहरण–15, चोरी–12 एवं शस्त्र अधिनियम का 01 कांड प्रतिवेदित हुआ है ।

उक्त अपराध आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्तमान में रसलपुर बाजार में अपराध नियंत्रण में है । रसलपुर बाजार में ओ0पी0 निर्माण का कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष : मुकेश जी, पूरक पूछिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी उत्तर दिए हैं । उत्तर में हत्या 03 के बजाय 09 हुए थे, लूट 01 के बाजय 15 हुए थे, चोरी 12 के बजाय 29 हुए थे । डकैती हुए, चोरी हुए, हत्याएं हुईं, सैकड़ों घटनाओं को मैं जानता हूं और सरकार ने उत्तर दिया है कि 01 घटना हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक क्या है ?

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ओ0पी0 बनाने का सरकार ने क्या काईटेरिया रखी है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ओ0पी0 निर्माण का क्या काईटेरिया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जो अपराध के आंकड़े हैं उसके आधार पर ओ0पी0 की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ओ0पी0 नहीं बनवाया जा सकता है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांत रहिए । बोलिए नहीं ।

माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1155 (श्री रामबली सिंह यादव, घोसी)

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद औद्योगिक प्रागंण 6.15 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान में इस औद्योगिक परिसर में 8 इकाईयाँ कार्यरत हैं। प्रश्नगत जय भवानी इन्टरप्राइजेज सम्प्रति कार्यरत है।

प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा चर्चित वेंकटेश टेक्सटाईल नामक इकाई कई वर्षों से अस्तित्व में नहीं है। फिनाईल निर्माता मॉडल केमिकल कम्पनी भी वर्षों से अस्तित्व में नहीं है। बियाडा द्वारा जिन प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की जाती है तथा जिन शर्तों पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है उनके उल्लंघन की दशा में बियाडा अधिनियम 1974 के सुसंगत प्रावधान के तहत अभिषेक फार्मा के भूमि आवंटन को दिनांक– 15.12.2021 को रद्द किया गया हैं। हाल के वर्षों में औद्योगिक परिसर जहानाबाद की भूमि पर निवेशको द्वारा उद्यम लगाने में अभिरूचि दिखाई जा रही हैं। वर्ष 2024 में चार इकाईयों को भूमि का आवंटन किया गया है जिनके द्वारा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन हैं। सरकार राज्य के सभी औद्योगिक परिसर को विकसित करने हेतु सतत प्रयास कर रहीं है। जिन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ नये सिरे से औद्योगिक विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रहीं है, जिसमें जहानाबाद जिले में भी 284 एकड़ भूमि पर औद्योगिक परिसर का निर्माण सम्भावित है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, उत्तर आया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं । महोदय, मेरा जो प्रश्न था..

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इनके दल के सभी सदस्य निर्णय लेकर सदन से वाक आउट कर गये हैं । ये सदन में मौजूद हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, तो सरकार जानना चाहती है कि ये क्या दल से अलग हो चुके हैं ?

अध्यक्ष : यह सरकार के साथ हैं ।

श्री रामबली सिंह यादव : यह महोदय, दल की रणनीति है । सरकार को सड़क से लेकर सदन तक हिसाब–किताब चुकता करना है । इसी रणनीति के तहत मेरा प्रश्न आ गया तो मैंने सोचा कि अंदर में रख दूं, बाहर में हमारे साथी हिसाब–किताब ले रहे हैं ।

अध्यक्ष : रामबली बाबू, पूरक पूछिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, मेरा जो प्रश्न था और जिस जगह का प्रश्न था । जहानाबाद में एक औद्योगिक परिसर है और उसी के आस–पास मेरा आवास भी है । प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर, उत्तर तो अस्वीकारात्मक कहा गया है लेकिन पूरे राज्य भर का हिसाब–किताब दिया गया है उद्योग–धंधे का ।..

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गये)

अध्यक्ष : ठीक है, बैठिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : तो महोदय, ये जो औद्योगिक परिसर है जहानाबाद का,

(व्यवधान)

हां ठीक है साथी लोग आ गये सब, तो इसमें महोदय, बताया गया है कि 6.51 एकड़ जमीन में वह औद्योगिक परिसर है..

..क्रमश..

टर्न–7 / हेमन्त / 17.03.2025

श्री रामबली सिंह यादव : (क्रमशः) : और 8 औद्योगिक इकाई अभी कार्यरत हैं, लेकिन नाम एक का दिया गया है, जय भवानी इंटरप्राइजेज का । सरकार से जानना चाहते हैं कि सात और कौन–कौन सी औद्योगिक इकाईयां हैं और ये सभी...

अध्यक्ष : बस एक ही कीजिए । समय हो गया है ।

श्री रामबली सिंह यादव : समय दीजिएगा न महोदय । सभी औद्योगिक इकाईयों में कितने लोग रोजगार कर रहे हैं । दूसरा है महोदय, उसमें शेष जो बची हुई जमीन है,

वह कितनी है और उसमें कौन सा उद्योग लगाने का सरकार का विचार है और शेष बची हुई जमीन में कब तक उद्योग लगाया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बता दूं, जो उन्होंने स्वयं कहा कि लगभग 6.15 एकड़ भूमि वहां उपलब्ध है । लगभग 2.5 एकड़ भूमि वहां पर रिजर्व रखी गयी है, जो इंस्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज हमको इंडस्ट्रियल एरिया में देनी होती हैं, उसके लिए । 2.09 एकड़ अलॉटेड है और अभी 1.55 एकड़ भूमि हम अलॉट कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य को मैं एक नयी जानकारी दे दूं । दो इकाई जिसका इन्होंने जिक्र किया, वह कई वर्षों से बंद है, उसका कोई ट्रेस नहीं है । तीसरा, उसका लैंड कैंसिल कर दिया था, क्योंकि जिस उद्देश्य के कारण बियाडा ने उसको भूमि दी थी, उन्होंने लैंड यूज चेंज कर दिया था, उस कारण उसको कैंसिल किया और हम आशा करेंगे कि माननीय सदस्य सरकार को धन्यवाद दें, क्योंकि चार नयी इकाईयों की स्वीकृति अभी सरकार द्वारा दी गयी है जिसमें मेसर्स किंग स्टील की स्वीकृति 27.08.2024 को, मेसर्स रिद्धी इंटरप्राइजेज की स्वीकृति 05.10.2024 को, मसर्स पिनाक पोलिसर्स की स्वीकृति 17.10.2024 को और ग्रीन प्लाई हाऊस की स्वीकृति 01.03.2025 को । इसके अलावा लगभग 200 एकड़ से अधिक का नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त है, जो जिला प्रशासन से भूमि का विवरण आया है । माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में लगभग 3200 एकड़ हम लोगों ने नये औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित किया है और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से बिहार के सभी जिले, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है या औद्योगिक क्षेत्र की भूमि लगभग जो लैंडबैंक है, समाप्ति की ओर है, वहां हम नया लैंडबैंक क्रियेट कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब प्रश्तोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, महोदय,...

अध्यक्ष : जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, बताया नहीं गया कि वह सात कौन–कौन इकाईयां कार्यरत हैं।

अध्यक्ष : श्री शकील अहमद खां जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और तमाम सदन का, सदन के तमाम उमरान का, काबिना के तमाम मिनिस्टर्स का और पूरे सदन का, कर्मचारियों का, सबका मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे दुख की घड़ी में साथ रहे, तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 मार्च, 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं–

1. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0, श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0, श्री विजय कुमार, स0वि0स0 एवं श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0 ।

2. श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 17 मार्च, 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक पर सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

आप अगंभीर कब उठाते हैं ?

(व्यवधान)

इतने लोग कैसे खड़े हो गये ? बैठिये अजीत जी । बैठिये रामबली बाबू । बैठ जाइये न । अजीत जी बैठिये आप । पढ़िये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : राज्य में सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित और सत्ता प्रायोजित अपराध सब रिकॉर्ड तोड़ चुका है । सत्ता, अपराधी और पुलिस की गठजोड़ में नागरिकों का जीना मुहाल कर, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है । अपराधियों द्वारा अररिया एवं मुंगेर में ASI की हत्या, नौबतपुर में हत्या, औरंगाबाद में अनुसूचित जाति की बच्ची की हत्या एवं नवादा, पटना तथा भागलपुर में पुलिस पर हमले से राज्य की जनता में आक्रोश है ।

अतः दिनांक 17.03.2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य के कानून व्यवस्था एवं पुलिस कर्मियों की शहादत पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा ।

(व्यवधान)

सब विषय गंभीर होते हैं । विधान सभा के अंदर सारे विषय गंभीर होते हैं ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज के लिये सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं परीक्षा के पेपर लीक पर चर्चा करायी जाय।

उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा जो बापू परीक्षा परिसर, पटना में आयोजित हुई उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया जिसके बाद परीक्षार्थियों के काफी आक्रोशित होने पर बिहार लोक सेवा आयोग ने उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी, परंतु बहुत सारे परीक्षार्थियों ने इसे सही नहीं माना और पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा लेने हेतु आज तक संघर्षरत हैं ।

अतः आज के लिये सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं परीक्षा में हुए पेपर लीक पर चर्चा करायी जाय ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री गोपाल रविदास ।

(व्यवधान)

बोलिये । शून्यकाल पढ़िये ।

(व्यवधान)

गोपाल रविदास जी, आप पढ़ेंगे कि आगे बढ़ें ?

<u>शून्यकाल</u>

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, एस0एफ0सी0 गोदाम से बिचौलियों पर पूर्ण प्रतिबंध करते हुए विक्रेता के गोदाम तक बैग के वजन के साथ अनाज का पूर्ण वजन के साथ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देखिये, दोनों बातें नहीं हो सकती हैं । आप पढ़ने का आग्रह करते हैं, पढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर शोर करते हैं । दोनों बातें कैसे हो सकती हैं । या तो आगे से नहीं पढ़ायेंगे आपको । दोनों बातें नहीं हो सकती हैं कल से । एक ही बात कल से होगी ।

श्री गोपाल रविदास : 02 प्रतिशत हैंडलिंग लॉस देने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथ देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा के पंचायत भितिहरवा के पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से ग्राम बड़ा मेघौली तक जानेवाली कच्ची पथ का पक्कीकरण कराने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं ।

मुहम्मद अंजार नईमी : महोदय, बिहार सरकार अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार हेतु ऋण देने का प्रावधान था । वर्तमान में इसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में परिवर्तित कर दिया गया है । फलस्वरूप अत्यधिक आवेदन के कारण अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं मिल पाता है ।

अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा हेतु अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा संचालित करने की मांग करता हूं ।

श्री राम सिंह : महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बगहा अनुमंडल के ग्राम रायबरी महुआ एवं ग्राम महुई की बीच मसान नदी पर पुल नहीं होने से किसानों को हरिनगर शुगर मिल से गन्ना ले जाने में बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है ।

अतः पुल निर्माण हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य के किसानों को सुदृढ़ बनाने में किसान सलाहकारों की भूमिका अहम है । अस्तु संविदा पर कार्यरत किसान–सलाहकारों की सेवा स्थायी करते हुए जनसेवक के पद का दर्जा देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगांव में गंगा नदी पर फोरलेन सड़क पुल का निर्माण कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के भागकोहलिया पंचायत के लवानाटोला वार्ड संख्या 03 एवं 04 में अवैध पशुवधशाला चलायी जा रही है जिससे बड़ी हिंदू आबादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे दिनप्रतिदिन जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है । अवैध पशुवधशाला बंद करने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी के महान साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, जे0पी0 आंदोलन के सेनानी फणीश्वरनाथ रेणु तथा बिहार लेनिन शोषितों–पीड़ितों की आवाज अमर शहीद जगदेव प्रसाद को उनकी अमूल्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए भारत रत्न देने के लिए बिहार सरकार से अनुशंसा करने की मांग करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर विश्वविद्यालय अंतर्गत BRM कॉलेज मुंगेर में लाइब्रेरी भवन जर्जर है तथा उपस्कर की कमी है ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से BRM कॉलेज मुंगेर में लाइब्रेरी भवन का जीर्णोद्धार तथा उपस्कर लगाने की मांग करता हूं ।

टर्न–8 / धिरेन्द्र / 17.03.2025

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखंड–आमस के ग्राम पंचायत–महुआवां के ग्राम–हटवरिया बिगहा से ग्राम–चतुरेखाप पुल तक सड़क का निर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहारा इंडिया कंपनी में लाखों लोगों का हजारों–करोड़ों रुपये जमा है । अरवल एवं कलेर प्रखंड के 76 हजार जमाकर्त्ता का करीब 200 करोड़ रुपये जमा है । सरकार से सहारा इंडिया कम्पनी द्वारा जमाकर्त्ता की राशि लौटाने की मांग करता हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अन्तर्गत मैरवा के गुठनीमोड़ पर भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेदकर की आदमकद प्रतिमा लगाने का सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड अंतर्गत विक्रमपुर चौक एन०एच०–322 पर निरंतर दुर्घटनाएं होती रहती हैं । दिनांक–14/07/2024 को दो युवकों का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी, जिसका हलई थाना कांड संख्या–70/24 है ।

अतः जनहित में विक्रमपुर चौक के समीप एन०एच०–322 पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं । इस समुदाय के बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुँच पा रहे हैं । इन्हें सामाजिक मुख्य धारा में शामिल करने हेतु एक

शिक्षक एक विद्यालय की अवधारणा स्थापित करने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय को पूर्ण न्यायालय का दर्जा देने के साथ क्रिमिनल कोर्ट नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को जिला कोर्ट 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ।

अतः मैं पूर्ण कोर्ट का दर्जा देते हुए क्रिमिनल कोर्ट की मांग करती हूँ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंडन्तर्गत भगवतीपुर ग्राम होकर नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की हरदी नदी बहती है, नेपाल में नदी पर तटबंध बना हुआ है, मारत में नदी से भारी कटाव होता है।

सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत भगवतीपुर ग्राम होकर बहने वाली हरदी नदी पर तटबंध निर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी०पी०एस०सी० से नवनियुक्त शिक्षकों की भाँति स्वास्थ्य विभाग, बिहार में कार्यरत स्टाफ नर्सों (ग्रेड–ए) एवं ए०एन०एम० (ग्रेड–बी) को भी स्वैच्छिक स्थानान्तरण करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक सहायकों की बहाली बिहार सरकार द्वारा निकाले गये विज्ञापन के आलोक में कमिटी बनाकर जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत एवं अन्य कार्यालयों में नियुक्ति की गयी । बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान से प्रशिक्षित कार्यरत कार्यपालक सहायकों को ग्रेड पे देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई विधान सभा क्षेत्र में खैरा प्रखंड अन्तर्गत बरनार नदी से कहरडीह–चांगोडीह गांवों के राजस्व क्षेत्र के कटाव और जानमाल के खतरे को देखते हुए कहरडीह रानी बांध से रामसजीवन बगीचा होते हुए पिपरी बगीचा से चांगोडीह खेल मैदान तक कच्ची बांध के निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूँ ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अन्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के गौररहा विषणपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नं०–08 के पश्चिम टोला से पूरब टोला जहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय अवस्थित है, जाने वाली पक्की सड़क से गुजरने वाली खरसाही नहर में पुल निर्माण की माँग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण से उभरे महागरीबी की तस्वीर से साबित हुआ है कि राज्य के मजदूर किसान महंगी बिजली बिल चुकाने में सक्षम नहीं हैं ।

अतः झारखंड के तर्ज पर बकाया बिजली बिल माफ करने, बिजली दर कम करने तथा 200 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है ।

अतः मधुबनी नगर क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से पहल किये जाने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, धुनिया, दर्जी, रंगरेज के जीवन में सुधार हेतु 2019 में बिहार सरकार द्वारा धुनिया, रंगरेज, दर्जी आर्टीजन विकास समिति का गठन हुआ परन्तु आजतक इसे धरातल पर नहीं उतारा गया ।

अतः सदन के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की सरकार से मांग करती हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डॉ॰ शमीम अहमद ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के प्रखंड अलीनगर में ग्राम–जयन्तीपुर दाथ के कनुनिया घाट पर कमला नदी में पुल का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है ।

अतः जयन्तीपुर दाथ के कमला नदी में कनुनिया घाट पर पुल का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सासाराम प्रखण्ड के दरिगांव में सासाराम के प्रथम विधायक स्वर्गीय जगरनाथ सिंह जी की स्मृति में पार्क निर्माण एवं मूर्ति स्थापना की मांग करता हूँ ।

श्री छत्रपति यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, एन॰एच॰–31 पथ खगड़िया गंडक नदी पर नवनिर्मित पुल डेढ़ वर्षों से क्षतिग्रस्त के कारण पुराने गंडक पुल से आवागमन में जाम और दुर्घटना होती है । खगड़िया–बेगूसराय फोर लेन पथ पर टोल टैक्स वसूलना जारी है । क्षतिग्रस्त गंडक नवनिर्मित पुल के मरम्मति एवं निर्माण तक टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अन्तर्गत सदर (जहानाबाद) प्रखण्ड के गोनवां पंचायत (रसीदपुर) बलवा गाँव के बच्चा विद्यालय के लिए, मरीज अस्पताल के लिए आजादी के 75 वर्षों बाद भी सड़क का वाट जोह रहा है । सड़क निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री विजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखण्ड अन्तर्गत चोढ़दरगाह छिलका से करकी, वृंदावन होते हुए मनकौल तक पईन का जीर्णोद्धार कार्य विगत 30 वर्षों से नहीं कराया गया है । किसानों को पटवन करने में कठिनाई हो रही है ।

अतः उक्त पईन का जीर्णोद्धार कार्य कराने की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां सहित बिहार के सरकारी, गैर–सरकारी वाहनचालक एवं संवाहक की माली हालत अच्छी नहीं है । इनको समय पर सम्मानजनक वेतन, मेडिकल फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, पारिवारिक सुरक्षा, शिक्षा लाभ देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और....

(व्यवधान)

पूरी बात तो सुन लीजिये । क्यों घबरा जाते हैं, हम हैं न अभी यहाँ ।

माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं भी ली जायेंगी ।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' एवं श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, ''राज्य के विभिन्न पंचायती राज संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2002–03 से लेकर 2022–23 तक आवंटित राशि 26 हजार 182 करोड़ में से मात्र एक तिहाई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा

किया गया है । इस कारण 20 हजार करोड़ से अधिक आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हो चुकी है । पुरानी योजनाओं बी आर जी एफ, आर एस वी वाई, 12वें वित्त आयोग, 13 वें वित्त आयोग, तृतीय राज्य वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की राशि भी इसमें शामिल हैं । आवंटित राशि से पंचायती राज संस्थानों द्वारा विकास कार्य नली, गली, सड़क आदि बनाने का प्रावधान है । मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल सात निश्चय योजना के अनुरक्षण और रख–रखाव, कुंआ के जीर्णोद्धार छठ घाट का निर्माण में खर्च करने का प्रावधान है ।

अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र के विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई तथा जल्द–से–जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

टर्न–9 / संगीता / 17.03.2025

अध्यक्ष : अब शून्यकाल की शेष सूचनाएं ली जायेंगी ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग द्वारा पूरे बिहार में बिजली कर्मचारी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के नाम पर बाइपास बिजली के नाम पर अवैध रुपये की मांग की जाती है रुपया नहीं देने पर जुर्माना कर दी जाती है लगभग 100 मामला है इसकी जांचकर कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग करती हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आंगनबाड़ी सेविका को 7000 रुपया एवं सहायिका को 4000 रुपया मानदेय दिया जाता है जबकि दिल्ली सरकार द्वारा सेविका को 12,720 रुपया एवं सहायिका को 6810 रुपया दिया जाता है ।

मैं दिल्ली की तर्ज पर बिहार में सेविका को 12,720 एवं सहायिका को 6810 मानदेय देने तथा पोषाहार की राशि में वृद्धि की मांग करता हूं ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–1353664 दिनांक–08.11.2022 के आलोक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं कर्मी को संविदा के आधार पर

नियोजित संविदा कर्मी का लाभ और मापदण्ड के अनुरूप सुविधा देने एवं ससमय भुगतान करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान, मधुबनी और भागलपुर सुता मिल मजदूरों का मजदूरी 20 वर्षों से बकाया है जांच पड़ताल के बाद मजदूरों के मजदूरी रोकने हेतु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है जो मजदूरों के साथ अन्याय है हम मांग करते हैं कि सरकार केस वापस कर मजदूरों की मजदूरी भुगतान करे ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगुसराय नगर परिषद तेघड़ा के सौन्दर्यीकरण के नाम पर तेघड़ा बाजार, स्टेशन रोड में वर्षों से आवासित पिछड़ा/महादलित/दलित/अत्यंत पिछड़ा/अल्पसंख्यक समुदाय एवं व्यवसायी वर्ग को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, सरकार से उक्त स्थान पर वर्षों से आवासित परिवारों को स्थायी निवास प्रदान करने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के पारा मेडिकल छात्रों की 2021–23 सत्र की परीक्षा देर से हुई । परिणाम निकलने से पहले 9 वर्षों बाद तकनीकी सेवा आयोग द्वारा भर्ती निकली है । एक अप्रैल तक आवेदन लिया जाना है । जिन छात्रों का परीक्षाफल आने वाला है, उनका भी आवेदन लेने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहपुर प्रखंड में कोशी नदी के कटाव से गोविंदपुर मुशहरी और कहारपुर के पीड़ित परिवार बिहपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन और सड़क के किनारे रहने को विवश हैं । कटाव से पीड़ित उक्त प्रखंड के परिवारों को भूमि अधिग्रहण कर बसाने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–10 / सुरज / 17.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनके सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :–

भारतीय जनता पार्टी	– 59 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 57 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 14 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)	– 08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0)	– 02 मिनट
सी0पी0आई0	– 02 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	– 01 मिनट
निर्दलीय	– 01 मिनट

....

कुल = 180 मिनट

....

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 16093,45,98,000/– (सोलह हजार तिरानवे करोड़ पैंतालीस लाख अंठानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार मिश्र, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम से ग्रामीण विकास विभाग के संपूर्ण मांग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ से अनुदान मांग के मद को मितव्ययिता के आधार पर घटाने के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं इन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं ।

सम्पूर्ण मांग पर प्राप्त प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का प्रस्ताव प्रथम है एवं अनुदान के मदों पर माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महोसठ का कटौती प्रस्ताव प्रथम है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–173 (6) के प्रथम परन्तुक के तहत मितव्ययिता के आधार पर दिये गये कटौती प्रस्ताव को पूर्वता दी जाती है ।

अतः माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष–2515, उप मुख्य शीर्ष–00 के लिये 851,57,00,000/– रुपये की मांग 5,00,00,000/– से घटायी जाय ।

मितव्ययिता पर विचार–विमर्श करने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव मितव्ययिता के दृष्टिकोण से दिया है । इस उप मुख्य शीर्ष में कार्यालय व्यय मद में गाड़ी के ईंधन, दूरभाष, विधि प्रभार आदि में अत्यधिक बढ़ोतरी की गयी है जबकि योजना मद में कटौती की गयी है इसलिये इस तरह के गैर जरूरी खर्चों में कटौती की जानी चाहिये ताकि योजनाओं के लिये निधि का अभाव नहीं हो ।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव अपना पक्ष रखें । आपका समय 20 मिनट है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और साथ ही मैं अपने पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मुख्य सचेतक भाई शाहीन साहब का भी आभारी हूं, उन्होंने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, तमाम महापुरूषों ने कहा है कि भारत गांवों का देश है । जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है और जो परिस्थितियां अभी मैं देख रहा हूं कि ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं चाहे वह जीविका हो, मनरेगा हो, लोहिया स्वच्छ अभियान हो, सात निश्चय हो, जल–जीवन–हरियाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास जीर्णोद्धार योजना । मैं समझता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जोर माननीय मुख्यमंत्री जी का जीविका पर है और मैं देख रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले जीविका की दीदीयां पटना में आ कर धरना पर बैठी थीं अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर के और मुझे लगता है कि उनकी एक भी मांग मानी नहीं गयी थी, जबकि 01 करोड़ 30 लाख के करीब जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और उनका सहकारिता से जो सी0एल0एफ0 उनके हैं, सहकारिता से 1996 एक्ट के तहत निबंधन भी किया गया है लेकिन अधिकतर सी0एल0एफ0 का बायलॉज जो अधिकार दिया गया, उसका हनन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है जबकि प्राधिकार के द्वारा 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और आज भी पदाधिकारी के द्वारा स्वतंत्र रूप से जीविका की दीदीयों को निर्णय नहीं लेने दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ जीविका की दीदीयां जो पैसा मिलता है उनको, उसका एक परसेंट जो ब्याज होता है उससे वह अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं और सरकार के द्वारा प्रतिदिन भत्ता के तौर पर 50 से 60 रुपया दिया जाता है, जो हमें जानकारी हुई है । चाहे वह जीविका का मधुमक्खी पालन हो, मत्स्य पालन हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो और अब देखते हैं कि तमाम जगहों पर जीविका की दीदीयों को लगाया जाता है । हमारे मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज में जब दीदी की रसोई चालू हुई है, मैंने वहां जाकर देखा है कि मरीजों को अच्छा खाना तो मिल रहा है और जीविका से एक साल में 2024–25 में पता लगा लें लोग 45 लाख रुपया मुनाफा हुआ है जीविका के द्वारा वहां मेडिकल कॉलेज में दीदी की रसोई से। लेकिन क्या हश्र है दीदी का 50 से 60 रुपया उसको मिलता है । हॉस्पीटल में दिन–रात, सुबह–शाम मरीजों को खाना बनाकर खिला रही हैं । उतना ही नहीं जीविका के काम में उनको भत्ता भी कितना मिलता है कि जीविका के काम में गांव–गांव घुमती हैं,

जीविका का समूह बनाती है, जोड़ती हैं, महिलाओं को जाकर स्वावलंबी बनाने पर अग्रसर रहती हैं । मैं तो सदन से कहूंगा, मंत्री जी पुराने लोग हैं और हम तो देखे हैं अपने यहां जाकर के 12 फरवरी, 2020 को मंत्री जी हमारे यहां 13 करोड़ के भवन का उद्घाटन किये थे, नया ब्लॉक जो बना था । उसमें बहुत व्यवस्था थी । सारे पदाधिकारी से लेकर चपरासी तक के रहने की सारी व्यवस्था थी, उसका जाकर उद्घाटन किये । मैं कई बार मंत्री जी से भी बोला, अभी जो जिलाधिकारी हैं, इनसे पूर्व के जिलाधिकारी को भी जा कर बोला । मंत्री जी आपके उस भवन में एक चपरासी भी नहीं रहता है और हमलोग चिल्लाते रहते हैं । विनय भाई हमारे ठीक कहते हैं, हम तो वह शब्द नहीं बोलेंगे सदन में कि विधायकों के बजूद को खत्म कर दिया गया है इस सरकार में । लाख कहने के बाद, मैंने आपको भी कहा, उसके बाद जिलाधिकारी को भी जाकर मैंने बोला लेकिन आज तक एक चपरासी, 13 करोड़ कुछ लाख की बिल्डिंग में आज तक चपरासी भी नहीं रहता और बिल्डिंग की स्थिति खराब हो रही है । मंत्री जी उद्घाटन किये थे, अपने हाथ से किये थे 12 फरवरी, 2020 को ।

अध्यक्ष महोदय, जीविका की दीदी की जो 10 मांगें थी, मैं समझता हूं कि इनकी मांग बाजिव थी । अभी तक जीविका के दीदी को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र नहीं मिला । उनका मांग एक नंबर मांग है । उसके बाद उनका भत्ता जो 50 रुपया और 60 रुपया मिलता है मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि जीविका के दीदीयों को कम से कम 02 हजार, 03 हजार की रकम, कम से कम 100 रुपया का रोज तो भत्ता दीजिये । उसके बाद मानदेय के नाम पर कुछ नहीं है । जीविका के दीदी ने मानदेय का प्रश्न उठाया है । मैं यह तो नहीं कहूंगा कि जो मांग है उनकी उतना आप मान लीजिये लेकिन कुछ तो मानदेय उनका होना चाहिये । उनकी हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, न डेथ पर कोई सिक्योरिटी है उनकी और सारा सिस्टम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चला आता है जीविका पर ।

महोदय, मैं सदन को बताना चाह रहा हूं कि जीविका में अधिकतर गरीब घर की महिलाएं हैं । हमारे गरीब घर की बहु–बेटियां हैं । मेरा आग्रह होगा मंत्री जी कि उनकी जो मांग है, उस मांग को भी ध्यान दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मनरेगा का स्वर्गीय रघुवंश बाबू हमलोगों के राजनीतिक गुरू थे । सारा देश जानता है कि मनरेगा, जिस समय ग्रामीण विकास मंत्री यू0पी0ए0 फर्स्ट में वह थे, उस समय वह मनरेगा लाये थे और इसमें था कि 100 दिन मजदूरों को काम मिलेगा । मैं एक बार बोला था आज के डेट में किसानों के साथ बहुत समस्या हो गयी है मंत्री महोदय पलायन

जारी है, गांव में मजदूर नहीं मिलता और जो मिलता है, मैंने मंत्री जी से कहा भी था कि जिस तरह से रोजगार गारंटी हमारे गार्जियन आदरणीय रघुवंश बाबू ने लाया था रोजगार गारंटी

(क्रमशः)

टर्न–11 / राहुल / 17.03.2025

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : (क्रमशः) उसी तरह से आपसे मेरा आग्रह था, कई बार मैं इस सवाल को उठाया हूं कि आप मजदूर गारंटी योजना लावें और वे मजदूर किसान की देखरेख में खेतों में काम करे और उसके पैसे की भरपाई सरकार करे । इन्होंने हमको कहा भी था कि मैं आपकी बात को प्रोसीडिंग में ले आया हूं लेकिन आज ऊपर और नीचे दोनों सरकार है, मैं तो आगे कहूंगा कि अब जो ही समय है कम से कम हमारे राज्य के किसानों के हित में इतनी व्यवस्था कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, पहले पशु शेड बनाने थे, गांव में जाइये तो किसान लोग मवेशी पालते हैं, बकरीपालन बहुत कम होता है लेकिन पशु शेड को अब हटा दिया गया है और बकरी शेड को लागू किया गया है कि बकरी शेड बनेगा, पशु शेड नहीं बनेगा । हम लोगों के क्षेत्र में भी बहुत से पशु शेड बने, गरीब आदमी सरकार का पैसा लेकर लाभ उठाता था । पशु शेड बनाकर के अपना पैमेंट लेता था, कर्जा, पैसा लेकर के, लेकिन अब पशु शेड नहीं बन रहा है, अब बकरी शेड बन रहा है । मनरेगा में जो मजदूरी है वह 245 रुपये अभी भी है । मंत्री जी, श्रम संसाधन विभाग ने जो न्यूनतम मजदूरी तय की है, आप वह न्यूनतम मजदूरी भी मनरेगा के मजदूरों को नहीं दे रहे हैं । दूसरी बात है कि दिसंबर का पैसा, हमको लगता है कि डिमांड भी किये हैं अब आपकी सरकार ऊपर में है वह सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है ? दिसंबर से लेकर के अभी तक मनरेगा का पैसा रिलीज नहीं किया गया है । मैं तो इस पर मंत्री जी से जवाब चाहूंगा कि अपने जवाब में बतावें कि जब डबल इंजन की सरकार, ऊपर और नीचे इनकी सरकार है तब फिर मजदूरों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है । एक अहम चीज है लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिये, बिहार में भी ओ0डी0एफ0 हो गया । अध्यक्ष महोदय, जो 12 हजार रुपये सहायता राशि गरीबों को दी जाती थी मैं समझता हूं 6 महीने से अभी तक गरीबों को 12 हजार रुपये सहायता राशि ओ0डी0एफ0 शौचालय की नहीं मिल रही है । गरीब आदमी कर्ज लेकर शौचालय बनाता है और जितना वह पैसा लिया था उससे ज्यादा उस पर कर्ज हो गया और सरकार उसका पेमेंट नहीं कर रही है । जीयो टैगिंग नहीं हो रही है और जिसका जीयो टैगिंग भी हो गया उसका पैसा नहीं मिल रहा है । सात निश्चय में हर घर नल का जल । पहले हम लोग देखते थे कि गांव में, पंचायत में जवाबदेही रहती थी, सब

मिलकर के चूंकि वार्ड को फिर आगे लड़ना होता था वह तैयार रहता था कि अगर थोड़ी भी कहीं गड़बड़ी हुई तो तुरंत जाकर जल–नल ठीक करवाता था । अब पूरे बिहार में जो यह जल–नल योजना है, यह पी0एच0ई0डी0 विभाग को दे दी गयी है और पी0एच0ई0डी0 विभाग को जब से दिया गया है, जल–नल का रखरखाव खत्म हो गया है । हमारे प्रधानमंत्री जी भी 44 जो घोटाले गिनाये थे उसमें एक घोटाला जल–नल योजना घोटाला भी है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास । रखरखाव की भारी कमी, अगर मोटर जल गयी तो समझिये कि सप्ताह, महीनों जल–नल चालू नहीं रहता है । पी0एच0ई0डी0 विभाग को कहा जाता है तो कभी कहता है कि हमको हैंडओवर नहीं किया गया, कभी कहता है कि मैं ठीक करवा दूंगा । इन सब पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी । जल–जीवन–हरियाली का है। इसी सदन में जब हम लोगों की सरकार थी, महागठबंधन की । 25525 करोड़ का बजट बना था जल–जीवन–हरियाली का और रिपोर्ट में आया कि 11205 कुओं को लगभग अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है, 15 करोड़ से अधिक पौधे लगा दिये गये हैं, 50 हजार से अधिक जलस्रोत सृजित किये गये हैं । जरा जांच करके दिखवा लीजिये कि यह कहां से रिपोर्ट आती है आप लोगों को । हम लोगों के क्षेत्र में तो देखते हैं एक पोखरा में से आधा हटा देता है और आधा वैसा ही है । कहीं एक भी पौधा हम लोगों के क्षेत्र में नहीं लगाया गया है और कोई पदाधिकारी अगर बोलते हैं, रिपोर्ट किया है तो हम लोगों के साथ चले हम लोग जांच करके दिखा देते हैं । प्रधानमंत्री आवास योजना । अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल, 2019 से हम लोगों के यहां पोर्टल बंद था और अब इधर जब पोर्टल चालू हुआ, सर्वे का काम चालू हुआ है तो जब चुनाव सामने में आ गया है तो प्रधानमंत्री का सर्वे चल रहा है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि बतायें, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब तक भुगतान हो जायेगा और इसमें कोई भी ऐसा सर्वे करने वाला जो वहां जाता है, जिसका लगाया हुआ है पंचायत सचिव, इंदिरा आवास सहायक कोई भी सर्वे करने जाता है गरीब आदमी से बिना पैसा लिये हुए उसका सर्वे नहीं करता यह स्थिति बनी हुई है । मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना का है । गरीब आदमी का जो अधूरा घर रहा गया, जिस समय 20 हजार रुपया, 25 हजार रुपया मिलता था, अधूरा घर जिस समय रह गया, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना लायी गयी । ताकि उस गरीब आदमी को 50 हजार रुपया मदद की जायेगी ताकि जो अधूरा घर है उसको पूरा किया जायेगा । मैं समझता हूं कि इस योजना का भी कोई लाभ गरीब को नहीं मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति अभी बनी हुई है, मैं समझ रहा हूं कि हर जगह केवल लूट–खसोट मची हुई है । सरकार तीर्थ करा रही है । आम आदमी त्रस्त हो गया है और यहां कहता है, कहावत है कि

'रोम जल रहा था, और पोप बंशी बजा रहा था ।' चिंता मत कीजिये 2025 आने वाला है...

(व्यवधान)

चुनाव नवंबर में आने वाला है और मैं देख रहा हूं कि विधान सभा को, कहना नहीं चाहिए हमको, हम लोग देखते हैं कि कर्पूरी जी का भी भाषण सुने हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं जिस समय कॉलेज में पढ़ता था, मैं एथलेटिक्स चैंपियन था 1985 में । 1985 में कर्पूरी जी हमारे कॉलेज में गये थे और उनका भाषण मैं सुना था । वे हमको प्राइज दिये हुए थे जिस समय हम एथलेटिक्स में कॉलेज चैंपियन थे और उन्होंने कहा था कि राजनीति का मतलब होता है बुराई से लड़ना । अब जो स्थिति हो रही है, पूरे सदन को लोगों ने ठाकुरबाड़ी बना दिया है, यह कतई नहीं होना चाहिए । आप सदन से बाहर जो करते हैं कीजिये लेकिन सदन को ठाकुरबाड़ी मत बनाइये । किसी को प्रताड़ित करने वाला काम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर इस सदन को प्रताड़ित करने का काम न करें । यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर को लोग ठाकुरबाड़ी बनाकर रख दिये हैं । मैं तो कहूंगा कि मैं जो स्थिति देखता हूं, मैं तो बचौल भाई का भी कुछ सुना...

(व्यवधान)

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष जी, ठाकुरबाड़ी...

(व्यवधान)

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : आप स्थिर रहिये । अरे बैठिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिये । बैठ जाइये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । आप बोलिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, जब जलियावाला बाग में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : स्थिर रहो न । बोलने तो दीजिये । बोलिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : जब जलियावाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवायी थी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब जलियावाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवायी थी तब उनसे पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलवायी तो जनरल डायर ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलवाये । उसी समय अब्दुल गफ्फार खान ने खड़े होकर के कहा था कि अगर एक पठान के भी पीठ में गोली लगी होगी तो मुसलमान आजादी की लड़ाई से बाहर हो जायेगा

। 5 दिन तक पोस्टमार्टम चलता रहा, 76 लाशें मिली और 76 के 76 पठानों ने अपने सीने पर गोली खायी थी । आज उसी को जलील कर रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में आपके साथ था । आपको यह मालूम नहीं है कि आज भी पाकिस्तान से ज्यादा संख्या हमारे यहां मुसलमान भाई की है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ग्रामीण विकास पर बोलिये न । कहां चले गये आप । ग्रामीण विकास पर आ जाइये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : आज भी पाकिस्तान से उनकी जनसंख्या हमारे देश हिंदुस्तान में है और सब आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है...

(व्यवधान)

इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये । बैठिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : अब तीन मिनट आपका समय बचा है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि :

जिधर से गुजरो, धूआं बिछा दो,
जहां भी पहुंचो धमाल कर दो,
तुम्हें सियासत ने हक दिया है,
हरी जमीनों को लाल कर दो,
अपील भी तुम, दलील भी तुम,
गवाह भी तुम, वकील भी तुम,
जिसे भी चाहो हराम कह दो,
जिसे भी चाहो हलाल कर दो ।

तमाशा बनाकर रख दिये हैं लोग । जहां जाइये हिंदु–मुस्लिम, मंदिर–मस्जिद, हिंदुस्तान–पाकिस्तान...

अध्यक्ष : ग्रामीण विकास पर बोलिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : ऐसा नहीं है कि आप केवल चंदन कर लिये तो आप सनातनी हो गये । अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है...

(व्यवधान)

एक लाख वर्ष पहले का हमारा सनातन धर्म है और 14 हजार वर्ष पहले का इस्लाम धर्म है । इस्लाम धर्म 14 हजार वर्ष का होने के बाद भी पूरे विश्व में छा गया और सनातन धर्म इंडिया, हमारे देश के कोने तक भी नहीं पहुंचा जो कि इस पर चंद लोगों ने अपना कब्जा जमा कर रखा है । समझता है कि हम बोलते हैं तो हम ही सनातनी हैं...

(व्यवधान)

हम लोग सनातनी नहीं हैं ? चंद लोगों के कारण ही सनातन धर्म आज तक अपने देश के कोने में नहीं पहुंच पाया...

अध्यक्ष : आप विषय से भटक गये ।

टर्न–12 / मुकुल / 17.03.2025

क्रमशः

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि–

''आग लगाने वालों को क्या खबर,

रुख हवा ने बदला तो,

खाक आप भी हो जाइयेगा ।''

इसलिए सर्तक रहिया । अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहना चाहूंगा । ग्रामीण विकास विभाग है, पिछली बार सुने थे, अखबार में आया था कि हमारे यहां मीनापुर में प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, हमारे यहां सब्जियों की खेती ज्यादा होती है, औने–पौने भाव में लोग सब्जी बेचते थे, इस बार जो गोभी की खेती हुई है, फसल लगी हुई खेती लोग ट्रेक्टर से जोत दिया, कोई दाम नहीं, कहीं कुछ नहीं, ढकिया का ढकिया टमाटर फेंक देता है रोड पर । मेरा मंत्री जी से भी गुजारिश होगा कि मेरे यहां एक प्रोसेसिंग प्लांट बना दें, जैसा कि अखबार में भी आया था, कोल्ड स्टोरेज बनायें, चूंकि हमारे यहां की सब्जियां पूरे देश में जाती हैं । दूसरा है कि हमलोगों को थोड़ा उपहास सुनना पड़ता है कि 9 साल से 2017 में जब सरकार थी हमारे यहां आई0टी0आई0 कॉलेज का प्रस्ताव हुआ था हमने तीन–तीन बार जमीन दी, मीनापुर आई0टी0आई0 कॉलेज का नामाकरण भी हुआ, उसमें नामांकन भी हो रहा है, दूसरी जगह चल रहा है और तीन–तीन जगह जमीन दी लेकिन उसमें आज तक आई0टी0आई0 कॉलेज नहीं बना और यह कहकर कि गड्ढा है, मैं जानना चाहता हूं कि जब एम्स बनाने के लिए दरभंगा में 300 करोड़ रुपया का आवंटन हो सकता है तो दो, चार करोड़ रुपया गरीब जो हमारे शिक्षित होंगे, जो हमारा नक्सल क्षेत्र रहा है उसको बनाकर के मंत्री जी से आग्रह होगा कि कब तक ये बनवा देंगे, अपने भाषण में अगर बोल देंगे तो हमें तसल्ली मिल जायेगी और हमारे लोगों को भी उम्मीद बढ़ जायेगी । एक जो है 500 बेड का आवासीय विद्यालय आया था, हमने जगह भी 21 एकड़ दिया और उसका था कि 500 बेड का छात्रावास, 10 प्लस टू तक की पढ़ाई पिछड़ा, अतिपिछड़ा के लिए और ये राजनीति द्वेषता के कारण हमारे क्षेत्र से हटाकर के आज कुढनी

में ले जाया गया । मैं तो कहूंगा कि राजनीति द्वेषता में इतनी बड़ी भिन्नता कि जहां एक तरफ हमारा नक्सल क्षेत्र, जहां कलेक्टर ने आदेश दे दिया, जमीन चयनित कर ली और उसको भी हटा दिया और हमारे क्षेत्र में बदनामी होती है कि विधायक जी नहीं करते हैं । मंत्री और मुख्यमंत्री आपलोग हैं, अगर हमारी सत्ता होती मैं अपने नेता को कहकर करवाता, अभी आग्रह करता हूं कि हमारे मीनापुर में जो आई0टी0आई0 कॉलेज और 10 प्लस टू का और प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करवा देंगे । जय हिंद, जय भारत ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राम सूरत कुमार । आपके पास 15 मिनट का समय है ।

श्री राम सूरत कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, खाद्य उभोक्ता संरक्षण विभाग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं और कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं । ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, पैसा की राशि कटवाना चाहते हैं यानी विकास नहीं करना चाहते हैं, घोटाला से इनको फुर्सत नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से औराई की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी मेहनत से और वोट की बदौलत मैं आज सदन के अंदर खड़ा होकर के बोलने के लिए खड़ा हूं और तमाम अपने एन0डी0ए0 के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि आज अगर बिहार के अंदर विकास की किरण अगर अंत्योदय जिसको हमलोग कहते थे, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि विकास की किरण गांव के उन दलित, शोषित, वंचित समाज के बीच में जाना चाहिए, आज यह दिखाई दे रहा है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन गरीबों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, उनके संक्षिप्त उनके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो चालू है, हम स्पष्ट सदन के अंदर, हमारे सभी साथी यहां पर बैठे हुए हैं, पक्ष और विपक्ष में बोलना लाजिमी है लेकिन यही महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत ज्यादा नहीं 15 से 20 साल पहले जब काम हुआ करता था, अभी मुन्ना यादव जी कह रहे थे कि हमारे गुरू रघुवंश बाबू थे, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं उसी विधान सभा क्षेत्र से मैं भी आता हूं लेकिन.....

अध्यक्ष : राम सूरत जी, इधर देखकर बोलिये । कहां उधर आप देख रहे हैं, इधर आ जाइये ।

श्री राम सूरत कुमार : हुजूर, आदत जो है वह जायेगी नहीं न, आदत तो वही रहेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुन्ना यादव जी कह रहे थे, माननीय

स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने रोजगार गांरटी के तहत योजना लाने का काम किया, लेकिन उस समय धरातल पर जो लोग बैठे हुए थे, 10 परसेंट भी काम गांव में दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन जब हमारी एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो अब उस योजना को, उस समय हमारे ग्रामीण मंत्री मिश्रा जी भी थे, अभी वर्तमान में श्रवण बाबू हैं, आज जाइयेगा तो उसी पैसा से चकाचका रोड भी नजर पड़ेगा, चकाचक पोखरी भी नजर पड़ेगा, जल–जीवन–हरियाली का काम पर नजर पड़ेगा और गरीबों को रोजगार का पैसा भी मिलेगा । पहले गरीबों को रोजगार का जो पैसा होता था वह उनको नहीं मिलता था, लेकिन माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय विभाग के मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके कारण आज गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसा, बैनीफिट अकाउंट्स के माध्यम से जा रहा है और धैर्य रखिए, आज हमारी, कल तुम्हारी देखो भाई फेरा–फारी, चिंता मत कीजिए भाई वीरेंद्र जी । आज मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के अंतर्गत 5671 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यह अद्‌भुत काम, खेल–कूद की सुविधाएं दी गयीं और पहले क्या हुआ करता था कि शहर के बच्चे ही शहर में खेल पाते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण, हमारे विभाग के मंत्री जी की सोच के कारण आज पूरे पंचायतों में खेल स्टेडियम तैयार हो रहा है, एक साथ सब जगह काम चालू हो गया है, मुझे भी अपने विधान सभा क्षेत्र में सौभाग्य प्राप्त हुआ है, खेल स्टेडियम का, टेनिस का, फुटबॉल का सारा ग्राउंड तैयार हो गया है और आज बच्चे वहां पर बड़ी आसानी से खेल रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : राम सूरत जी, उधर मत सुनिये, इधर देखिए, इधर बोलते रहिये । ये लोग आपका समय कील कर रहे हैं । आप बोलते रहिये ।

श्री राम सूरत कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है । इसके अलावे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास योजना होती थी, लेकिन उस इंदिरा आवास योजना के तहत जो कुछ भी काम नहीं हो पाया, आधा–अधूरा रह गया उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजना से आच्छादित करके उसे पूरा करने का काम किया । जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो उस सरकार के तहत उस राशि को बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपया और 1 लाख 30 हजार रुपया किया गया जिसके तहत गरीबों का घर बनना तय हो गया और गरीब अब छत वाले मकान के अंदर रहते हैं बड़ी सुविधा के साथ । लेकिन बीच में कुछ योजनाएं मुजफ्फरपुर जिले के अंदर छूट गया था, जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि हमारे आवास सहायक हड़ताल पर चले गये, लेकिन अब पोर्टल खुला है जिसके कारण वहां

सर्वे चल रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वह पोर्टल खुला है और हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भी और बिहार के अंदर भी इसका कार्यक्रम चल रहा है । जॉब कार्ड बनवाकर के सभी लोग अपना–अपना नाम जुड़वा रहे हैं, वैसे और वृहत पैमाने पर इसको जुड़वाया जाय जिससे कि उन गरीबों को लाभ मिल सके । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है जल–जीवन–हरियाली के तहत, वैसे पोखर/परभिंडा पर आश्रित लोगों को भी जमीन उपलब्ध करवाकर उनको भी आवास योजना के तहत जोड़ा गया है और इसके अलावे एम0वी0आर0 की रेट पर जिनको जमीन देनी है उसमें लक्ष्य जितना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी इसके प्रयास में लगे हुए हैं कि एक बहुत बड़ा जरूरी है कि सदन के अंदर सभी सदस्यों के हक की बात मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार या बिहार सरकार उन गरीबों का घर बनवाना चाहती है लेकिन उस जगह पर जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उनलोगों का भी आवास योजना का काम रुक जाता है तो मैं अपने मंत्री जी और सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वैसे लोगों का सर्वे हो और उनको जमीन आवंटित कराकर के उनका भी घर बन जाये नहीं तो फिर जब पोर्टल बंद हो जायेगा तो फिर वे वंचित रह जायेंगे ऐसी प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब अभी माननीय बिहार सरकार और भारत सरकार के तमाम अपने नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1378 करोड़ की लागत से जल संसाधन विभाग के द्वारा जो सुदृढ़ीकरण का काम होना शुरू हुआ है, जहां से यह बांध बना है हमारे विधान सभा क्षेत्र में और रूनी सैदपुर में, रूनी सैदपुर का अलग है और मेरा अलग है । इसमें 51 किलोमीटर का रोड स्वीकृत हुआ है, बांध पर बनना है, सुदृढ़ीकरण होना है । लेकिन परियोजना बांध बनने के कारण, इसी विभाग से संबंधित मामला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो गरीब भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के लोग दोनों बांध के बीच में जो 192 किलोमीटर की दूरी के अंदर है और मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बोलना चाहूंगा कि

क्रमशः

टर्न–13/यानपति/17.03.2025

(क्रमशः)

श्री रामसूरत कुमार : अध्यक्ष महोदय, 51 कि0मी0 दोनों तटबंध मिलाकर है और रिंग बांध भी उसमें है, वैसे लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वैसे लोगों को जमीन नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा जल संसाधन

विभाग के मंत्री जी बैठे हैं, ग्रामीण विकास के मंत्री बैठे हैं राजस्व मंत्री भी बैठे हैं तो एक चिन्हित करके पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्योंकि बांध पर काम होना है, सामने चुनाव है तो निश्चित तौर पर मैंने डी0एम0 को पत्र भी लिखा है, विभाग को लिखा है, सबको लिखा है, प्रोजेक्ट बनाकर इस आवास योजना के तहत महत्वपूर्ण विभाग का बजट है, तो वैसे गरीबों को भी जमीन 3–3 डिस्मिल, 5 डिस्मिल देकर बसाया जाय जिससे कि आगे विकास का भी काम हो, गरीबों को लाभ मिल सके । इसके अलावे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उद्योग विभाग का भी बजट है, मैं अपने उद्योग विभाग के मंत्री जी को कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से उद्योग को बढ़ावा बिहार में मिला है, उद्योग, एक समय था माननीय अध्यक्ष जी कि पूर्ववर्ती सरकार में ड़द्योग लगानेवाले नहीं जो छोटे दुकानदार हुआ करते थे, जो छोटे दुकानदार अपने गांव में सूतापट्टी जैसे शहर में बड़े–बड़े दुकान चलाते थे वैसे दुकानदार पलायन करना शुरू कर दिए थे । यह सच्चाई है, हकीकत बात है लेकिन आज वह व्यापारी बड़े बड़े शहर जाकर के अपना बड़ा बड़ा उद्योग खोल लिए लेकिन आज के दिन में मैं इसका साक्षी हूं, गवाह हूं कि आज के दिन में हमारे मुजफ्फरपुर में बड़े–बड़े उद्योग लग रहे हैं, एथनॉल लग रहे हैं, फूड पार्क बन रहा है, तमाम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं, तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है और किसान के हित की बात करनेवाले लोग आज एथनॉल फैक्ट्री लगने के कारण आज क्या स्थिति है, किसानों के मक्का का दाम कितना हो गया, आज 30 रुपये किलो मक्का का दाम हुआ है इसका कारण है बिहार के अंदर ड़द्योग लगा है, लोगों को रोजगार मिला है और लोग भयमुक्त होकर के यहां व्यापार कर रहे हैं । निश्चित तौर पर उद्योग मंत्री जी को मैं सराहता हूं कि आपने जिस तरह से पूर्व के मंत्री हों, वर्तमान के मंत्री हों, एन0डी0ए0 की सरकार के तमाम नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके कारण बिहार का जो सम्मान बढ़ा है, देश के अंदर बढ़ा है, वह निरंतर बढ़ता रहे यही मैं कामना करता हूं । इसके अलावा...

अध्यक्ष : रामसूरत जी, अभी जो माननीय सदस्य लोग कह रहे हैं अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक शेर उनको जरूर सुनाता कहिए तो सुना दें ।

श्री रामसूरत कुमार : महोदय, आप सुना दीजिए । एक शेर सुना दीजिए ।

अध्यक्ष : हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाह का मेरी अजब फितरत है, उनकी ओर से मैं कह रहा हूं, मैं आईना रखता हूं । बोलिए ।

श्री रामसूरत कुमार : महोदय, इसके अलावे चीनी मिल बंद करा दिए, चीनी मिल की जो स्थिति पैदा कर दिए, कोई तैयार नहीं हो रहा है खैर उसके अलावे मैं कहना चाहूंगा कि तमाम हमारे जो, विभाग की उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेशी

सिंह जी बैठी हैं और जरा गौर से दिल पर हाथ थामकर सुनियेगा, सोचियेगा भी पी0डी0एस जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत पहले की जो सरकार हुआ करती थी, पहले की जो पी0डी0एस0 की व्यवस्था थी उसपर मैं दो लाइन कहना चाहूंगा कि जब मुझे याद है कि हमारे पिताजी मुखिया प्रमुख हुआ करते थे, हमलोग बच्चे थे छोटे–छोटे, मुन्ना जी भी जानते हैं इस बात को और जनता को पीडीएस दुकान क्या होता है सिर्फ होली और दिवाली में पता चलता था, उसमें भी जब पैरवी होता था तब वह दुकान के मार्फत किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा मिलता था लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई, वन नेशन वन राशन कार्ड और के0वाई0सी0 से जोड़ना और ऑनलाइन डिलीवरी करना, डोर स्टेप डिलीवरी करना यह आज बताता है, यह दर्शाता है कि बिहार की जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहा है तो निश्चित तौर पर वह 12 महीना मिल रहा है । इनके जमाने में 12 महीना में मात्र दो महीना ही डिलीवरी हुआ करती थी और 10 महीना का घोटाला हुआ करता था जिसकी जांच भी नहीं होती थी और तमाम वैसे...

(व्यवधान)

आप जनता से पूछ लीजिए । आप जनता के पास चले जाइये । कहीं अगर 19–20 अगर कुछ होता है तो आज 12 महीना का 12 महीना डिलीवरी होता है । यह सरकार, एनडीए की सरकार की देन है, एनडीए के मंत्रियों की देन है, माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें तमाम विधायक, सदन के अंदर जो भी लोग हैं, अपनी जनता को राशन नहीं दिलवा पाते थे...

अध्यक्ष : आपका समय तीन मिनट है ।

(व्यवधान)

श्री रामसूरत कुमार : सत्यदेव बाबू, बैठ जाइये । आप महादलित के नेता हैं, आपके महादलितों का हक लूटा जाता था, जिस समय कोई बोलने वाला नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए हैं तो सदन के अंदर तो गरीबों के हक–हकूब की लड़ाई लड़ने की व्यवस्था का काम किए हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । सत्यदेव जी ।

श्री रामसूरत कुमार : अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने...

(व्यवधान)

माननीय सत्यदेव बाबू, बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : मात्र दो मिनट है ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं ।

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है, बोलिए ।

श्री रामसूरत कुमार : महोदय, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, जन वितरण प्रणाली के तहत 5 किलो अनाज देने का प्रावधान है और आज 4 किलो मिल रहा है ।

अध्यक्ष : अपनी पार्टी की ओर से बोलिएगा । बोलिए रामसूरत जी । बैठिए, बैठ जाइये ।

श्री रामसूरत कुमार : रहनुमाई करने वाले अल्पसंख्यकों को, तमाम साथियों को कहना चाहूंगा, आपने मुसलमान भाइयों को यूज ऐंड थ्रो किया है, आपने वोट लेने का काम किया है, विकास के नाम पर जितना आपने अल्पसंख्यकों को लूटने का काम किया है, उतना किसी ने लूटने का काम नहीं किया है । सिर्फ भाजपा का भय दिखाकर आपने मुसलमानों से वोट लिया, मैं कहना चाहता हूं कि एनडी0ए की सरकार, भाजपा की सरकार जब बनी है देश के अंदर और राज्य के अंदर तो अल्पसंख्यक महफूज कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जितना उनके विकास का काम हो, चाहे वह कब्रिस्तान का काम हो, चाहे उनकी शिक्षा का काम हो, जितना काम अल्पसंख्यक विभाग ने किया है, जमा भाई यहां बैठे हैं, एक–एक काम को निपटाते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एन0डी0ए0 की सरकार है तो संभव है और इनलोगों के यू0पी0ए की जो सरकार थी, गरीबों को चूसने का, लूटने का काम किया, आज जब जनता को सम्मान मिल रहा है, जनता का नाम हो रहा है, बिहार का नाम हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और हमारे दोनों डिप्टी सी0एम0 के नेतृत्व में हो रहा है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जिस तरह से संरचनाएं तैयार की गई हैं, गरीबों को लाभ मिल रहा है । उसके अलावे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान के तहत उन गरीब परिवारों को शौचालय बनवाकर देने का काम किया गया है ।

अध्यक्ष : अब एक मिनट बचा है, समाप्त कीजिए ।

श्री रामसूरत कुमार : निश्चित तौर पर तमाम अपनी बातों को समाप्त करते हुए मैं अपने, माननीय सत्यदेव जी, हमेशा गरीबों के हक की बात करते हैं लेकिन गरीब का हक मारकर खा जाते हैं ये। निश्चित तौर पर मैं अपने तमाम, ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि समय कम है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे औराई विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो वैसे गरीब, सुयोग्य परिवार श्रेणी के लोग हैं उनका पोर्टल में नाम चढ़ जाय, अभी 10 से 12 दिन और बचा हुआ है, 31 मार्च तक है, इसका डेट बढ़वाकर कोई भी बिहार का गरीब न छूटे इसको ध्यान में रखते हुए नाम जुड़वाया जाय और हमारा औराई प्रखंड मुख्यालय जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के बैठने के लिए भवन नहीं है बाकी और...

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री रामसूरत कुमार : वहां पर कृषि विभाग में चलता है तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि वहां नया भवन निर्माण कराया जाय । आप सबों को बहुत–बहुत धन्यवाद, नमस्कार ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र राम । आपके पास 15 मिनट का समय है ।

श्री सुरेन्द्र राम : माननीय अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद । आज मैं कटौती प्रस्ताव ग्रमीण विकास विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप जो दूसरे को बोलते रहते हैं, मोबाइल में आप बात करते रहते हैं, सब आवाज यहां आ रही है ।

श्री सुरेन्द्र राम : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं खड़ा हूं । महोदय, आज मैं इस सदन में गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालूजी और नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू और अपने गरखा विधान सभा की सम्मानित जनता की कृपा से आज इस सदन में मैं बोल रहा हूं । महोदय, जिस तरह से हमने यह बजट पढ़ा है तो बजट से स्पष्ट होता है कि भोली सूरत दिल के हैं काले नाम बड़ा और दर्शन छोटे, जिस हिसाब से इस बजट को हमलोग देख रहे हैं, इस बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग...

(क्रमशः)

टर्न–14 / अंजली / 17.03.2025

(क्रमशः)

श्री सुरेन्द्र राम : और महिलाओं के विकास के लिए इसमें जो योगदान होना चाहिए, बजट में प्रावधान होना चाहिए वह प्रावधान नहीं है । चूंकि ग्रामीण विकास तभी संभव होगा जब गांव का हर गली, हर नाली का विकास संभव होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जाति के बस्ती में, पासवान भाई के बस्ती में, पासी भाई के बस्ती में, रविदास भाई के बस्ती में, कानू, बिंद, मल्लाह के बस्ती में आने–जाने का रास्ता भी नहीं है । यदि इमरजेंसी पड़ जाए तो खटिया छोड़कर के कोई एंबुलेंस जाने तक का भी रास्ता नहीं है । कोई बीमार पड़ जाय तो कहीं–कहीं खटिया भी घुसने और जाने का रास्ता नहीं है, तो मैं यह जानना चाहता हूं हमारे ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्रवण बाबू जी से और यहां पर उपस्थित तो नहीं हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 20 साल में आप क्या विकास का कार्य किए हैं ? विकास का कार्य होता तो दलित भाइयों के गांव में, बस्तियों में जाने का कम से कम रास्ता तो होता, विकास का कार्य होता, तो दलित भाइयों के गांव में नाले का पानी जो सड़क पर, घर का जो पानी बह रहा है वह घर का पानी रास्ते पर नहीं झुग्गी–झोपड़ियों से बहकर झुग्गी–झुपड़ियों तक नहीं घुसता । आप गांव को सुंदर बनाने के लिए ये 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट में प्रावधान किए लेकिन आप एक योजना तो बताइए कि उन दलित बस्ती और पिछड़ा/अतिपिछड़ा जाति के बस्ती में जहां आज रास्ता नहीं है, वह बस्ती रास्ता से दूर है, उस बस्ती में जाने के लिए कौन–सी आपकी योजना है, उस योजना का मंत्री जी नाम तो बता दीजिए, इस बजट में आप जब बोलिएगा तो उसका प्रावधान तो बता दीजिए कि दलित बस्ती में जाने के लिए इस योजना का हमने इसमें प्रावधान रखा, उस योजना में इतना राशि हमने रखा । इसके तहत दलित भाई के बस्ती में, पिछड़ा भाई के बस्ती में, अतिपिछड़ा भाई के बस्ती में जाने के लिए यह प्रावधानित राशि है । हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर मिले, हमने कहा कि हम भी दलित वर्ग से आते हैं, हम भी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, हमारे घर तक भी जाने का रास्ता नहीं है, अनुसूचित जाति बस्ती के वर्ग के लोगों का रास्ता रोका जाता है, लाश उठाने तक भी नहीं दिया जाता है और जब बीमार लोग बढ़ता है तो कांधे पर उठाकर मरीज को ले जाते हैं तो हम यह जानना चाहते हैं कि ये 20 वर्षों से जो पीठ और बांह पूजवाने वाली सरकार से एक दलित का बेटा यह सवाल कर रहा है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से आखिर क्या जुल्म किया है हमने कि आप हमारे लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं, ये रास्ता का प्रावधान नहीं कर रहे हैं, आप तो बजट बड़ा–बड़ा पेश कर रहे हैं उस

बजट में दलित के गांव में जाने के लिए उस बजट में क्या रास्ता है ? आपने प्रावधान नहीं किया हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां जाकर कहा कि आप एक ऐसा प्रावधान बनाइए जिसमें उस प्रावधान, उस योजना का आप अम्बेदकर साहब मार्ग के नाम से या कर्पूरी ठाकुर के नाम से या दोनों महापुरुषों के नाम से अम्बेदकर कर्पूरी ठाकुर मार्ग के नाम से योजना चलाइए और सर्वे कराइए, सर्वे कराइए कि किस दलित बस्ती में रास्ता नहीं है, किस दलित बस्ती में नाला नहीं है, किस दलित बस्ती में सामुदायिक भवन नहीं है, तो कहे कि हम किनके–किनके नाम से बनाए ? हमने कहा कि किनके–किनके नाम से मत बनाइए, दलितों और पिछड़ों के लिए जो संविधान में अधिकार दिये, शोषित वंचितों के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिये और उस संवैधानिक अधिकार को सरजमीं पर उतारने वाले महापुरुष आदरणीय लालू जी, तो हम यह कहें कि आदरणीय लालू जी, जिन्होंने गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़े ।

(व्यवधान)

अरे भाई बोलने दीजिए । आपकी बारी आएगी तो आप भी बोलिएगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य इधर देखकर बोलिए ।

श्री सुरेन्द्र राम : आपकी बारी आएगी तो आप भी बोलिएगा ग्रामीण का विकास तभी होगा । महोदय, आप तो जानते हैं कि जो परंपरागत पेशा था, जो राजतंत्र राज में भी और राजतंत्र राज खत्म हुआ, अंग्रेजों का शासन आया और अंग्रेजों के शासन के बाद जब देश की आजादी हुई तब भी पासी और पासवान भाई लोग और दलित समाज वर्ग के लोग ताड़ी उतारने का काम करते थे । जब राजतंत्र राज्य में नहीं रोका गया, अंग्रेजों के शासन काल में ताड़ी उतारने के काम को रोका नहीं गया तो हमारे चाचा के राज में पासी और पासवान भाइयों को ताड़ी उतारने से रोका गया । ताड़ी उतारने के नाम से क्या आप ताड़ी उतारने का जो पेशा था, परंपरागत पेशा था उस पेशा को आप बंद करके आपने उनको कोई काम दिया क्या ? आपने कोई काम तो दिया नहीं, आप जिस पेशा को देखिएगा हमारे नोनिया भाई का भी कोई परंपरागत पेशा रहता है, बिंद भाई, मल्लाह भाई, कुम्हार भाई, माली भाई, हजाम भाई, लोहार भाई, धोबी भाई और हमारे डोम समाज से और रविदास समाज से इन सब लोगों का परंपरागत हमलोगों का पेशा है और उस पेशा को, उस हुनर को स्किल्ड नहीं किया गया तो आप जब तक ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों के हुनर को, स्किल्ड को आप बढ़ाने का काम नहीं कर सकते हैं तब तक ग्रामीण विकास और गांव का विकास संभव नहीं है । गांव का विकास तभी होगा जब पासी–पासवान, रविदास, चमार इन सभी जातियों का आप चयन कीजिए कि इनका परंपरागत पेशा क्या है और उस परंपरागत पेशा को स्किल्ड डेवलपमेंट जब तक नहीं

कीजिएगा तो आज जो ट्रेन भर–भर के बिहार से पलायन हो रहे हैं, वह पलायन आपका रूकेगा नहीं । जब आप पलायन रोकना चाहते हैं तो बजट में इनके लिए प्रावधान तो करना पड़ेगा तभी बिहार का विकास होगा । आप प्रधानमंत्री आवास योजना का देख लीजिए कि सभी जगह 40 से 45 हजार रुपया एक प्रधानमंत्री आवास योजना पर इनके अफसर ले रहे हैं, अफसर आखिर क्यों ले रहे हैं, तो बी0डी0ओ0 साहब कहते हैं कि हम तो ऊपर तक देकर आए हैं तो नीचे तो वसूलना पड़ेगा । गांधी जी के इस देश में, गांधी जी का उपदेश नहीं चल रहा है, गांधी जी के देश में गांधी छाप चल रहा है, कितना ही हमलोग ब्लॉक में, थाने में गांधी जी के उपदेश को हमलोग देते हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और वहीं उनके दलाल के यहां जाइएगा तो गांधी छाप देखकर के निश्चिंत हो जाइएगा आपका काम एकदम जरूर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, हंड्रेड प्रतिशत हो जाएगा, यह इस सरकार का चरित्र और चित्रण है तो हम यही कहेंगे कि यह सब जो चीज है इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा और देखकर के उसको सुधार करने की जरूरत है, अब तो आपसे सुधार भी नहीं होने वाला है । चूंकि जनता आपको नकार चुकी है और 2025 में आपकी सेवा समाप्त होने वाली है, तो हम तो यही कहेंगे कि

(व्यवधान)

अरे भाई चुप रहिए न । इतना बड़ा–बड़ा बजट है आपके पास में तो कफन का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है ।

अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी, तीन मिनट बचा है ।

श्री सुरेन्द्र राम : प्रावधान नहीं है आपके पास में । आपको लगता है कि एक साल से कफन का पैसा जो कबीर अंत्येष्टि योजना का पैसा है वह पैसा भी सरकार नहीं दे रही है और प्रक्रिया इतना जटिल कर दिया गया है कि आप अंत्येष्टि कराकर के आइएगा उसके बाद आप दौड़िएगा तो एक महीना–दो महीना के बाद पैसा मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा और वह भी राशि कितनी है तो मात्र 3 हजार रुपया है, इस महंगाई के युग में आप बजट तो बता रहे हैं कि इतना मेरा बजट बढ़ गया । (क्रमशः)

टर्न–15 / पुलकित / 17.03.2025

(क्रमशः)

श्री सुरेन्द्र राम : लेकिन कबीर अंत्येष्टि का राशि मात्र तीन हजार रुपया है । हम तो माननीय मंत्री से, माननीय मंत्री जी हमारे सामने हैं, मंत्री जी ताक रहे हैं, टुकुर–टुकुर । हम देख रहे हैं उनको, हम तो यही कहेंगे कि माननीय मंत्री

जी, वित्तमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आप उनके बजट में प्रावधान बढ़ाइये । कम से कम कबीर अंत्येष्टि का राशि दस हजार रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर के कफन का दाम भी होगा और लकड़ी का दाम भी आएगा, नहीं तो उसमें अपने घर से मिलाकर के गरीब आदमी कर्जा करके, कर्ज लेकर के अंत्येष्टि का कार्यक्रम करते हैं । हम तो यही कहेंगे कि इस राशि को बढ़ाया जाए । आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास जो वर्ष 2010 से पहले बने हैं, वे जर्जर अवस्था में है, वे आवास चू रहे हैं, उन आवासों में पानी टपक रहा है । हम तो यही कहेंगे कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें भी आप उसकी मरम्मती के लिए पैसा लीजिए लेकिन गरीबों का जो जर्जर आवास है, उस आवास की भी मरम्मती कराए । आपने तो इंदिरा आवास योजना का नाम ही बदल दिया

अध्यक्ष : अब एक मिनट बचा है । एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये ।

श्री सुरेन्द्र राम : लेकिन हम तो यही कहेंगे कि उस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही जो जर्जर मकान हैं । उन जर्जर मकान का भी आप मरम्मत कीजिए । अब हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बारे में बोलेंगे । कब्रिस्तान की घेराबंदी अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है । हम यह कहेंगे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो0 जमा खान भाई से कि आप कब्रिस्तान की घेराबंदी कराइए और उसमें पेय जल की, पानी की भी व्यवस्था कराइये, चूंकि हम लोग जाते हैं, कवर देने के लिए जाते हैं, माटी देने के लिए जाते हैं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री सुरेन्द्र राम : उसमें पानी की व्यवस्था नहीं होती है और हम यही कहेंगे कि उसमें आप पानी की व्यवस्था करा दीजिए । खाद्य आपूर्ति विभाग के संबंध में हम यह बोलेंगे कि उसमें 41 किलोग्राम से लेकर के 65 किलोग्राम तक की बोरी होती है ।

अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुरेन्द्र राम : महोदय, एक मिनट समय दिया जाए ।

अध्यक्ष : समय आपको कैसे दें ? अब समाप्त करिए ।

श्री सुरेन्द्र राम : महोदय, उसमें उसका लोडिंग–अनलोडिंग की दर श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रावधान किया गया है । लोडिंग का 11.65/–रुपया है और अनलोडिंग का भी 11.65/– है ।

अध्यक्ष : आप समाप्त करिये । एक ही बात बोल रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र राम : उसके बदले में मात्र 4/– रुपये से 5/– रुपये मजदूरों को दिया जाता है । इसमें घोर आपत्ति है, इसमें कटौती की जा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में वर्ष 2025–26 के आय व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों कि मांग जो ग्रामीण विकास विभाग पर है । गिलोटीन में उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार के लोकप्रिय कर्त्तव्यनिष्ठ, दिन–रात बिहार की महान जनता के लिए चिंतन कर बिहार को मॉडल राज्य बनाने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश बाबू का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदय, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं । महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । महोदय मैं आपके माध्यम से आदरणीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री, मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । जिनके विभाग का आज विषय भी है और मैं आपके माध्यम से सदन में उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज सदन में तीनों विभाग के माननीय मंत्री महोदय एवं महोदया विराजमान है, मैं इनका भी हार्दिक अभिनन्दन करता हूं । महोदय, मैं आपके माध्यम से जिस विधानसभा से मैं जीतकर आता हूं । मैं बिहारीगंज विधान सभा से हो वहाँ की महान जनतागण, देवतुल्य जनतागण, युवा साथियों, माताओं एवं बहनों का भी मैं हार्दिक अभिनन्द और इसी सदन से प्रणाम करता हूं ।

महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश बाबू के कुशल नेतृत्व में राज्य के विकास में ग्रामीण विकास विभाग में महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न योजनाओं द्वारा हुआ है और हो भी रहा है । बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा, 88 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं । महोदय, बापू का सपना था कि ग्राम को ग्राम साम्राज्य बनाना । जिसको कि हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हरेक क्षण बापू के सपने को पूरा कर रहे हैं ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, सबको जानकारी है बिहार सरकार द्वारा कोई भी नया काम लॉन्च होता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय चम्पारण की धरती से ही उसका शुभारंभ करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सर्वमान्य नेता हरेक महापुरुष का, चाहे डॉ0 लोहिया हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, बापू तो है ही किसी भी महापुरुष का जो सपना था, सबका सपना साकार करने का काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश बाबू के द्वारा निरंतर किया जा रहा है । महोदय, मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान । 24 नवम्बर, 2005 को नयी सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का काम हो रहा है । जनता ने भी जनसमर्थन देकर लगातार सराहा है और वर्ष 2025 में भी निश्चित तौर पर पुनः महान जनता गण का जनसमर्थन मिलेगा, इसमें कोई किंतु, परंतु नहीं है । महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश बाबू के दिशा निर्देशन में ग्रामीण विकास विभाग की बहुत सारी योजनाएं चल रही है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य योजनाएं चल रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास का ही जिस पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का ड्रीम प्रोजेक्ट है– जीविका । महिला सशक्तिकरण की मिशाल बन रही है जीविका । मैं जीविका पर ही अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा । जीविका के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश बाबू ने अपने संकल्पित कार्य में प्राथमिकता के आधार पर बहुत ही आगे बढ़ाया है । आमतौर पर जीविका की वर्ष 2006 में स्थापना हुई । तत्पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश बाबू के कार्य कुशल की ही देन है कि महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया और महिलाओं को रोजगार देने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गये । बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं को विकास सशक्तिकरण एवं ग्रामीण उन्मूलन हेतु कार्यरत है । उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया । वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है । यह है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सुविचार जो कि यह दर्शाता है कि महिलाओं का सम्मान हमारे

मुख्यमंत्री महोदय ने कितना आगे अब तक बढ़ाया है । महोदय, पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी कम थी । वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, जिसका नाम जीविका दिया गया । अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख 63 हजार हो गई है । जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 01 करोड़ 31 लाख से भी अधिक है । अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह की व्यवस्था की जा रही है ।

(व्यवधान)

यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ही देन हैं कि जिनका हरेक कार्य नजर आ रहा है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन की ओर देखकर बोले । निरंजन बाबू, आप आसन की ओर देखकर बोले ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अभी हमारे पूर्व मंत्री महोदय बोल रहे थे कि महादलित परिवार के लिए रास्ता नहीं है । ये पूर्व मंत्री रहे हैं और महादलित परिवार के लिए ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / अभिनीत / 17.03.2025

..क्रमशः

श्री निरंजन कुमार मेहता : हमारे सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री महोदय ने, आप जानिए कि सात निश्चय के तहत केवल महादलित परिवार के लिए गली–नली योजनाओं का आविष्कार किया, खोज किया और आज हरेक जगह राशि सात निश्चय की ग्राम पंचायत से लौट गयी । मैं मुखिया रहा हूं 2001 से 2015 तक लगातार तीन टर्म, राशि लौट रही है । कबीर अंतयेष्टि का पैसा मांग रहे हैं, कबीर अंतयेष्टि का पैसा एडवांस दिया जा रहा है और सब झूठ बोल रहे हैं..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप बैठ जायं । माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अरे भाई, 2005 के पहले क्या था ? जिनकी संख्या 34 हजार हो गयी है तथा इनमें 03 लाख 60 हजार से भी अधिक..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं । आपने अपनी बातें कह दी, अब बैठ जायं । निरंजन बाबू, आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, माननीय पूर्व मंत्री..

उपाध्यक्ष : निरंजन बाबू, आप आसन की ओर देखें ।

(व्यवधान)

श्री निरंजन कुमार मेहता : आपको मैं गारंटी देता हूं । बिहारीगंज विधान सभा चालिए मैं घुमाता हूं । 43 पंचायत, अरे गांव मैं आपको साथ लेकर घुमा दूंगा । घुमा दुंगा मैं आपको, चलिए मेरे क्षेत्र बिहारीगंज विधान सभा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य निरंजन बाबू, आप आसन की ओर देखें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं कीजिए ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा चलें हमारे मंत्री महोदय, 43 पंचायत..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : निरंजन बाबू, आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : मैं अपको गांव घुमा दूंगा । कोई भी महादलित बोलेगा तो मैं एम0एल0ए0 पद छोड़ दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं । मैं घुमा दूंगा आपको और महादलित परिवार में घुमा दूंगा । रास्ता कहीं नहीं है, रास्ता सब जगह है । रास्ते का पैसा सात निश्चय का लौटता है । लौट गया था, सरेंडर कर दिया, कहते हैं कि रास्ता नहीं है । जिनकी संख्या 34 हजार हो गयी है तथा इनमें 03 लाख 60 हजार से भी अधिक जीविका दीदियां हैं । विभिन्न पंचायतों में कार्यरत 5986 बैंक सखी, बैंक दीदी सदस्यों के मध्य वित्तीय उत्पादों, समय पर जमा–निकासी, बीमा, पेंशन इत्यादि पर जागरूकता फैला रही हैं । राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 78.40 लाख से अधिक सदस्यों को बीमा से आच्छादित किया गया है । कृषि क्षेत्र में भी लाभुकों को..

उपाध्यक्ष : निरंजन बाबू, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, एक मिनट है न, तो हम साथ–साथ इनलोगों पर भी बोलेंगे । खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग है मुखबंद में, इन लोगों का भी स्वागत करेंगे । आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री नीतीश बाबू के कुशल नेतृत्व

में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने वाला देश में बिहार प्रथम राज्य है । राज्य में 01 फरवरी, 2014 से यह योजना लागू है । अंत्योदय परिवार को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न तथा पूववर्ती प्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक लाभुकों को..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें । अब बैठ जायं ।

माननीय सदस्य श्री शाहनवाज साहब । आपके पास 10 मिनट का वक्त है । अपना भाषण जारी करें ।

श्री शाहनवाज : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज ग्रामीण विकास विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पेश किये गये बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं अपने विधान सभा क्षेत्र जोकीहाट, जहां की आम–अवाम ने लगातार 1970 से हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे परिवार और हमको दुबारा चुनकर खिदमत करने का मौका दिया है । आज इस सदन के माध्यम से तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं । साथ ही साथ अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हम सबके नेता तेजस्वी यादव जी का भी मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जिस समाज की बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं वह पहले की तरह आज भी अपनी बुनियादी सुविधा, अपने बुनियाद को मजबूत करने के लिए तरस रहा है । हाथ फैलाये खड़ा है । सरकार द्वारा बजट पर बजट पेश किया जा रहा है लेकिन ये दावे साज–सज्जा के लिए कागजी सामान के माफिक है । उपाध्यक्ष महोदय, आप आज अल्पसंख्यकों की हालत देख लें तो आपको सही जवाब मिलेगा कि उनकी स्थिति आज भी बहुत दयनीय है । खासकर मैं सीमांचल से आता हूं जहां अल्पसंख्यकों की आबादी का बड़ा तबका आज भी विकास को, अपने दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी को तरस रहा है । उनके हालात दिन–ब–दिन बदतर होते जा रहे हैं । बारिश हो तो उनको बाढ़ से जूझना पड़ता है, कटाव से त्रस्त होते हैं, गर्मी हो तो बीमारी से, न स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा है और आखिर में उनका एक ही सहारा बचता है पलायन । सिर्फ कागज पर विकास की बात होती हुई आ रही है । महोदय, आप सीमांचल जाकर देखेंगे तो आपको वादों और इरादों में कितना जमीन और आसमान का फर्क है उसका अंदाजा लगेगा । चंद लाईनों से मैं इसकी बात रखता हूं–

''आंखों को मूंद लेने से खतरा न जायेगा,

वह देखना पड़ेगा जो देखा न जायेगा ।

पैमाना भरा चला है मोहब्बत के सब्र का,

झूठी तसल्लियों से संभाला न जायेगा ।''

महोदय, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं । मैं आंकड़ों पर सदन का ध्यान बाद में आकृष्ट करूंगा पहले जो बिहार में लगातार हेट्स स्पीच दिये जा रहे हैं उसका प्रभाव हमारे बिहार की अस्मिता, भाईचारा और अमन–चैन पर पड़ रहा है । महोदय, हम किसी धर्म के विरोध में बोलकर क्या साबित करना चाहते है । हम अपने आने वाले जेनरेशन को क्या बतलाना चाहते हैं ? इस हिन्दुस्तान को आजाद कराने में जितना खून हिन्दुओं का बहा है उतना ही खून मुसलमानों का भी बहा है । यह हिन्दुस्तान गंगा–यमुना तहजीब से एकजुट और मजबूत रहेगा न कि फूट डालो राज करो वाली नीति से । एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा अल्पसंख्यकों के विकास की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की चिंता जताते हैं लेकिन उन्हीं के साथी विधायक, मंत्रीगण लगातार विरोधाभास बयान देते आ रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी के कानों में जूं नहीं रेंगता है । मैं अमन–चैन के खिलाफ जाने वालों के बारे में कुछ चंद लाईनों के बारे में कहना चाहता हूं–

''अगर खिलाफ है तो हो जाने दो जान थोड़े ही है

ये बस दुआ है कोई आसमान थोड़े ही है

लगेगी आग तो आयेंगे कई जद में

यहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े ही है

मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं है

खून का खून है, साहुल यहां की मिट्टी में

किसी के बाप का हिन्दुस्तान थोड़े ही है ।''

बिहार की डबल इंजन की सरकार ने लगभग 870 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित किया है । जो कुल बजट का 0.27 ही मात्र है जबकि अन्य विभागों के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि है । शिक्षा और स्कॉलरशिप की केवल घोषणा मात्र है, उनका जमीन पर कुछ नहीं दिखता है । व्यवसायों और उद्यमिता के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है । हज नीति पर भी सरकार की स्पष्ट दिशा की कमी है । हर साल हज यात्रियों की संख्या में गिरावट आती जा रही है फिर भी सरकार केवल दावे पर दावे किये जा रही है । सरकार हर क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को ठग रही है बस दावा और कागज पर हवा–हवाई है । महोदय, मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना

चाहता हूं । एक महत्वपूर्ण विषय है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है । पिछले की सरकारों में रमजान को ध्यान रखते हुए अकलीयत समाज के सरकारी कर्मचारी को सहूलियत दिया करती थी जिससे वे सभी की शांति के लिए इबादत किया करते थे और सपरिवार इफ्तार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता था और सपरिवार इफ्तार करते थे । हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार रमजान के पाक महीने में छूट देते हुए शाम चार बजे से उनको छुट्टी देने का काम करे जिससे कि उनको इबादत करने में सहूलियत हो और वे मुल्क के अमन–चैन के लिए दुआ, प्रार्थना मांग सकें ।

महोदय, अकलियत समाज के लोगों की शिक्षा व्यवस्था मदरसा पर निर्भर है । महोदय, दिन–ब–दिन मदरसा की व्यवस्था लाचार और बेबस होती जा रही है । महोदय, बिहार में कुल 3587 मदरसे हैं लेकिन सिर्फ 1942 मदरसों को सरकारी मान्यता प्राप्त है । सरकारी देख–रेख नहीं होने के कारण मदरसों की मनमानी और बदहाली किसी से छिपी नहीं है । महोदय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करा देने से मदरसों की हालत में काफी सुधार हो सकता है।

..क्रमश..

टर्न–17 / हेमन्त / 17.03.2025

श्री शाहनवाज : (क्रमशः) : इससे गरीब बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं । महोदय, मदरसों की अधिकांश संख्या सीमांचल क्षेत्र में है । महोदय, मदरसा के कामकाज के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करके, सफर तय करके पटना आना पड़ता है । मैं सरकार से मांग करता हूं सीमांचल में मदरसा बोर्ड का एक कार्यालय खोलने का काम करें, लोगों को पटना आना पड़ता है । जब वह मदरसा के काम के लिए पटना आते हैं, यहां पर उनको सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है । मेरे विधान सभा, मेरे जिला से कई ऐसे संबंधित मदरसा के मामले हैं, जो पिछले तीन साल, चार साल से सिर्फ उनको तारीख मिल रही है । तीन साल में मदरसा के चेयरमेन बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके मामले का निष्पादन नहीं हो सका है ।

महोदय, बिहार सरकार में विगत कुछ वर्षों से मदरसा बोर्ड के चेयरमेन की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है । सरकारी अफसरों की मिलीभगत से काफी लूटपाट हो रही है । महोदय, जांच के नाम पर मदरसा में आर्थिक अत्याचार हो रहा है । जो लोग मदरसा की जांच के लिए जाते हैं, वह मदरसा वालों पर आर्थिक अत्याचार करते हैं । महोदय, गरीबों को तालीम देना ही हम सबका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये । माननीय सदस्य बैठ जाएं ।

श्री शाहनवाज : मंत्री जी जहां बैठे हुए हैं, सीमांचल के प्रभारी हैं । बार–बार किशनगंज जाते हैं, सीमांचल जाते हैं । किशनगंज की बदहाली मंत्री जी से छिपी हुई नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लगभग लाखों अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों ने अनुदान के लिए आवेदन किया था, लेकिन यह काफी शर्म की बात है कि सिर्फ एक हजार अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ, जो कि साफ–साफ यह बोलता है कि इस योजना का लाभ जितना अल्पसंख्यक समाज को मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है । इसका पूरा विवरण सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है । महोदय, नतीजा यह है कि सीमांचल में लाखों लोग रोजगार नहीं मिलने के कारण उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वह है पलायन।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री शाहनवाज : मैं खत्म कर देता हूं । सीमांचल का हर तीसरा–चौथा, जो युवक है वह पलायन होने पर मजबूर है ।

उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं ।

श्री शाहनवाज : महोदय, अंत में अपनी बातों को खत्म करता हूं । महोदय, सीमांचल में सिर्फ बाढ़ है, कटाव है । यहां तक कि बाढ़ आने के कारण जो गांव कट जाते हैं, हम लोगों के बार–बार लिखने के बावजूद भी बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य नहीं होते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार ।

श्री शाहनवाज : महोदय, अंत में जल वितरण प्रणाली....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार । आपके पास में पंद्रह मिनट का वक्त है ।

श्री प्रणव कुमार : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया है इसके लिए आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं । मैं सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार, सदन के उपनेता सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी और अपने सचेतक जनक सिंह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं । मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दानवीर कर्ण की भूमि मुंगेर, जो योग नगरी के रूप में विश्व में ख्याति प्राप्त यह है । मैं उस योग नगरी की

जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद के प्रतिफल मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग विभाग, खाद्य उपभोक्ता एवं आपूर्ति विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिये ।

श्री प्रणव कुमार : के पक्ष में मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं और विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव, जो विकास नहीं चाहते हैं । एक तरफ तो विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ कटौती प्रस्ताव लाते हैं। यह बहुत ही हास्यप्रद है । मैं विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

बंधुओ, आज ग्रामीण विकास की बात हो रही है। ग्रामीण, जो भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा गांवों में बसती है, उसके विकास की बात करते हैं। हमारे विपक्ष के सदस्यों ने सही कहा कि रघुवंश बाबू के समय मनरेगा योजना लागू हुई, लेकिन मनरेगा योजना आपके भ्रष्टाचार की चादर से बाहर नहीं निकल सका था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार समूचे बिहार के लोगों को व्यक्त करना चाहिए कि उनके नेतृत्व में, एनडीए सरकार के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर आज बिहार में ग्रामीण विकास और मनरेगा का काम दिखाई दे रहा है। आज वर्तमान में आप गांव चले जाइये। माननीय मुख्यमंत्री जी का मनरेगा के तहत, जो पंचायतों में खेल मैदान बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है, उसका समूचे बिहार की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय द्वय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने गांव और गलियों में, जिन्हें दौड़ने के लिए कोसों दूर जाना पडता था, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए गांव के गरीब के बच्चे, जो फौज में, बिहार पुलिस में या अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते थे, उन्हें दौड़ने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती थी, आज मनरेगा के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण बाबू ने, जो गांवों में खेल मैदान बनाने का काम किया है, आज देखते ही बनता है । जो गांवों में हमसे कहा करते थे विधायक जी मेरे यहां मैदान नहीं बनेगा क्या ? आज उस मैदान में कबड्डी का कोर्ट है, बैडमिंटन का कोर्ट है, फुटबॉल का मैदान है और लोग आते हैं। गांव के लोग जब साथ जाते थे, तो वह कहते थे शहर के लोग सुबह–सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, हमारे यहां जगह नहीं है । आज के लोग भी उस मैदान में, गांव की मां–बेटी भी उस मैदान, गांव की बहु भी उस मैदान में जाती हैं और मॉर्निंग वॉक करके अपने स्वास्थ्य में सुधार करके और गांव के बच्चे

नौकरी के लिए अर्धसैनिक बल में, सैनिक बल में वहां जाकर तैयारी करते हैं और गांव के लोग, जो फुटबॉल, कबड्डी और खो–खो खेला करते हैं। वैसे छात्र आज खेल की दुनिया में परचम लहरा रहे हैं । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। पहले इंदिरा आवास योजना थी और क्या मिलता था ? आप लोग सब जानते हैं कि इंदिरा आवास योजना में क्या मिलता था और आप के समय मुखिया जी के करीबी लोग जिनको आवास नहीं था, वह पैसा लेने के लिए जाते थे, उससे टिप्पा करवा लिया जाता था और 50 परसेंट पैसा मुखिया जी के यहां रह जाता था, वहां के बीडीओ, सीओ के पास रह जाता था, आपके नेताओं के पास जाता था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक–एक पैसा डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खाता में जाता है और आप जैसे बिचौलिया लोग उसे लूटने का, भरमाने का प्रयास करते हैं, उसे ठगने का प्रयास करते हैं । गांव का गरीब जग चुका है । गांव का गरीब विकास को देख चुका है । इसलिए गांव का गरीब अब आपके झांसे में नहीं जाने वाला है । इसलिए हमारी सरकार का जो लक्ष्य है,

(क्रमशः)

टर्न–18 / धिरेन्द्र / 17.03.2025

...क्रमशः....

श्री प्रणव कुमार : महोदय, योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त कुल भौतिक लक्ष्य 2,43,701 के विरुद्ध में अब तक 2.36 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति देते हुए 34,915 आवासों को पूर्ण कराया गया है ।

योजना क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लक्ष्य के विरुद्ध 01 लाख 823 करोड़ 30 लाख रुपये का व्यय किया गया है । यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा गरीबों के हित के लिए है, गरीबों के विकास के लिए है । जिनको आवास, जिनको छत मुहैय्या नहीं होता था, आज एन०डी०ए० की सरकार ने जो प्रण लिया हुआ है कि समूचे गरीबों को छत देने का काम हमारी एन०डी०ए० की सरकार करेगी ।

इसके साथ–साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना वर्ष 2023–24 के लिए आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 87,319 के विरुद्ध 07.01. 2025 तक कुल 86,429 लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गयी है । वर्ष 2024–25 में अब तक कुल 413 करोड़ 88 लाख रुपये का व्यय किया गया है । यह व्यय बताता है कि एन०डी०ए० सरकार ग्रामीणों और गरीबों के प्रति

कितनी सचेत है । अब बिहार में कोई लूट तंत्र नहीं चलेगा, गरीबों को ठगने का काम अब बंद हो गया है, यह एन०डी०ए० की सरकार है ।

अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से वर्ष 2014–15 से लेकर 2019–20 तक यह योजना लायी गयी । लोहिया स्वच्छ बिहार योजना का संचालन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है । बंधुओं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लोगों को स्वच्छ करने के लिए, इस देश के गरीबों के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए, जो गरीब स्वच्छता क्या होता है वे नहीं जानते थे, इस गांव की, इस बिहार की गरीब जनता खासकर वे गरीब महिलाएं जिनके घरों में शौचालय नहीं होता था, जो दिन के उजाले में शौच करने के लिए नहीं जाती थी, वे सूर्यास्त होने का समय देखती थी और सूर्यास्त का समय देखकर वे शौच करने के लिए जाती थी । आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने समूचे देश में गरीबों के लिए जिनके घर में शौचालय नहीं था उनको शौचालय देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है । आज हमारे गांव के लोग शहर आते थे, रोजी–रोजगार करने के लिए आते थे, वे देखते थे गांव में, शहर में कचरा प्रबंधन था शहर में झाड़ू लगाया जाता था, हमलोग सोचते थे कि मेरे गांव में वह दिन कब आयेगा जब हमारे घर के बगल के कचरे को उठा कर ले जायेगा । आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन था उसके तहत आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण बाबू के नेतृत्व में हमारे यहाँ स्वच्छता कर्मी का गठन किया गया है और आज हमारे गाँव–गाँव में भी स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी गाँव में आते हैं स्वच्छ भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है उसको साकार करने के लिए गाँव और गली घूमकर वे मेहनत करते हैं । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं उनका मानदेय बढ़ाने की जरूरत है और उनको सशक्त करने की जरूरत है जो एन०डी०ए० सरकार ही करेगी, आपलोग से अपेक्षा नहीं है । प्रथम चरण में 122 करोड़ परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान की गयी है, यह सरकार की नियति बताती है । भूमिहीन परिवारों एवं अस्थायी आबादी के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में, अब तक राज्य में 9,281 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया गया है । आज स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2024–25 के द्वितीय चरण में, राज्य में अब तक 21.5 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय सुलभता प्रदान की गयी है । इसी तरह लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण और द्वितीय चरण मिलाकर पिछले 10 वर्षों में 01 करोड़ 43 लाख से अधिक परिवारों को शौचालय की सुलभता प्रदान की गयी है, यह एन०डी०ए० सरकार की कार्यपद्धति बताती है ।

बंधुओं, मैं कौशल विकास की तरफ आना चाहूँगा । कौशल विकास योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन किया गया है जो कौशल के विकास की दिशा में जीविका....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, जीविका दीदी के द्वारा और यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है । आज कौशल विकास योजना के तहत यहाँ के युवा प्रशिक्षित होकर रोजगार ही नहीं करते हैं बल्कि गाँव के आवश्यक गरीबों को भी रोजगार देने का काम हमारे कौशल विकास से प्रशिक्षित हुए युवा करते हैं ।

मैं मुंगेर क्षेत्र से आता हूँ, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार का जब बंटवारा हुआ तो मुंगेर एक औद्योगिक क्षेत्र था और मुंगेर में कई उद्योग हैं सिगरेट फैक्ट्री जो कि ब्रिटिशकालीन युग से है, आज वहाँ सिगरेट फैक्ट्री में मजदूरों का शोषण किया जाता है । ठेका प्रथा के द्वारा वहाँ के मजदूरों से आठ घंटा के बदले 12 घंटा का कार्य लिया जाता है । उसके अनुसार....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, अंत में मैं इस सदन में सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुंगेर में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसके लिए मैं बहुत–बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ–ही–साथ, हम प्राप्त को समझें मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के वक्त.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव । आपके पास आठ मिनट का वक्त है।

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार और साथ ही हमारी पार्टि भाकपा माले और हमारे क्षेत्र घोसी विधान सभा के संघर्षशील और सम्मानित महान जनता जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया है । आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं ।

महोदय, मैं इस बजट के संबंध में बोलना चाहता हूँ कि यह जो ग्रामीण विकास विभाग है, टास्क तो वर्ष 2023 में ही तय हो गया था, न्याय के साथ विकास की यह सरकार चल रही थी और जब वर्ष 2023 में आर्थिक सर्वे हुआ तो 64 प्रतिशत परिवार 10 हजार से भी कम महीने की आमदनी पर जिंदा

पाये गये और यह मैं नहीं बोल रहा हूँ महोदय, सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा और सूचना पूरे बिहार की महान जनता को दिया था और उसमें से 34 प्रतिशत परिवार 06 हजार से भी कम प्रतिमाह की आय पर जिंदा हैं और आज हमारी सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है । पता नहीं ये किनकी विकास की बात करते हैं । महोदय, बजट में जिनके विकास की बात हो रही है, हमलोग जानते हैं भारत की आत्मा गाँव में बसती है, बिहार गाँवों का देश है, महोदय, गाँव किसान और मजदूरों का बसेरा है और जिनके पास साईकिल खरीदने के लिए हैसियत नहीं छोड़ी है सरकार ने, 06 हजार महीना है, 10 हजार महीना है और सरकार विकास की बात कर रही है कि हम सड़क बना रहे हैं छः घंटा में बोल दिये हैं पटना पहुँचने के लिए, अब दो घंटा कर दिये हैं । महोदय, किस वाहन से ? जिनको चप्पल खरीदने की हैसियत आपलोगों ने नहीं छोड़ी है 20 सालों में...

...क्रमशः....

टर्न–19 / संगीता / 17.03.2025

(क्रमशः)

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, 6 हजार रुपया महीना से भी कम जिनकी आमदनी है और उनके साथ आप मजाक कर रहे हैं, कोई भी सरकारी बस अब नहीं है, सारे बस प्राइवेट आपने कर दिया और इसलिए आप बिहार के गरीबों का, बिहार के मजदूरों और किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है उसमें ये सभी गरीब आपसे हिसाब–किताब लेंगे, जिनका आपने मजाक उड़ाया है । महोदय, ये जो बजट की चर्चा हो रही है, 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपया का बजट है उसमें ग्रामीण विकास पर बहुत खर्च हो रहा है । यह बजट, कितने पैसे का यह बजट है महोदय, जी0एस0टी0 का है, आपने भीखमंगा तक को नहीं छोड़ा, सलाई जो खरीदता है, सलाई पर भी आपने टैक्स लिया गरीबों से और विकास आप किसका कर रहे हैं ? गरीबों के विकास के लिए तो मेरे पास अखबार का एक कटिंग है महोदय, 12 मार्च का यह हमारे पास अखबार है दैनिक भास्कर का, एक जिला जहानाबाद में 112 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास का अभी तक खर्च नहीं हो पाया है और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बजट बनाते हैं और खर्च नहीं होता है ऐसा ही बजट बनाते हैं ? आपके जितने सी0ओ0 हैं वे एन0ओ0सी0 नहीं देते हैं । विकास क्या होगा महोदय ? गरीबों का विकास तो संभव नहीं है, हां भारत माला की सड़क बनवा सकते हैं गरीबों से छीनकर जमीन, किसानों से छीनकर बिना मुआवजा दिए हुए तो हम कहना चाहते हैं कि यह जो बजट था बनाना चाहिए था आर्थिक सर्वे के जमीन पर खड़ा होकर के

और आर्थिक सर्वे का जमीन बता रहा है कि यदि बिहार का विकास करना है तो इतने लोग जो गरीब हैं, सरकार ने कहा था 2–2 लाख रुपया देने का, कोई योजना की चर्चा सरकार ने नहीं किया था, कोई आय प्रमाण–पत्र की चर्चा विधान सभा में नहीं किया था और अब कहा जा रहा है आय प्रमाण–पत्र बनाइए, लघु उद्यमी योजना में आवेदन दीजिए, सरकार ने नहीं दिया महोदय, और इतना भारी अगर गरीबी है तो क्या हमारी सरकार को योजना बनाते समय यह नहीं करना चाहिए ? जो बिजली महंगी है, भारी बिजली बिल बकाया है किसानों पर, मजदूरों पर, लोग तबाह हैं क्या उनका बिजली बिल माफ नहीं होना चाहिए महोदय ? तमाम गरीबों को, बगल के झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया महोदय, क्या बिहार में जो सर्वे था, आर्थिक सर्वे जो आपने कराया है, क्या बिहार के गरीबों का बिजली बिल माफ नहीं होना चाहिए था महोदय ? बगल के झारखंड में 2500 रुपया उन तमाम महिलाओं को दिया जाता है जिनकी उम्र 19 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे है लेकिन बिहार की वे तमाम ग्रामीण महिलाएं कोई आशा में काम कर रही है, कोई जीविका में काम कर रही है, कोई रसोइया में काम कर रही है 50 रुपया रोज के मानदेय पर और अपनी चंद मानदेय के लिए लाठियां खा रही हैं । क्या झारखंड के तर्ज पर आर्थिक सर्वे के बाद क्या बिहार सरकार को उन तमाम महिलाओं को, हम तो कह रहे हैं बिहार में तो 3000 रुपया मिलना चाहिए था जितनी भारी गरीबी है । महोदय, मैं तो आपको जरूर कहूंगा कि सही बात है हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी, कुछ भी नहीं था, हम ही न किए जी, एकदम–एकदम आप ही लोगों ने किया और इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि 2005 के बाद आपने इस बिहार में एक भी अंचल और ब्लॉक नहीं बनाया तो हम कहना चाहेंगे कि कम से कम जहानाबाद में 2 ब्लॉक, जो 2005 के पहले का बना हुआ है, मोदनगंज और रतनी, उसका बिल्डिंग तो बना दीजिए महोदय । पंचायत मुख्यालय का निर्धारण 2001 में हुआ और पंचायत का जो निर्धारण हुआ, बड़ी चालाकी से वह जितना भी पंचायत मुख्यालय है बिहार में, उन सारे मुख्यालय में दलितों की आबादी है, पिछड़ों की आबादी है लेकिन इस सरकार की आंख पर दलित और पिछड़े चढ़े हुए हैं...

उपाध्यक्ष : आपके पास में रामबली बाबू एक मिनट का वक्त बचा है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, 2 मिनट दिया जाय महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप मुख्यालय से अलग हटकर पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं, बड़े लोगों के दरवाजे पर बना रहे हैं और इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि पंचायत भवन, पंचायत मुख्यालय में बनवाया जाय और साथ–साथ मुझे कुछ समय दीजिए महोदय, पहली बार बोलने का मौका मिला है और इसीलिए मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से यह जो सरकार है

प्रचार की सरकार है । एक सीरियल हमलोगों ने देखा था रामायण का, उसमें एक शनिचरा महाराज थे और शनिचरा महाराज का मुड़ी नीचे और पैर जब ऊपर रहता था तब बढ़िया चलता था, मुड़ी ऊपर हो जाने के बाद में लंका भी जो सोने का था वह काला हो गया था और इसीलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि 2025 का जो चुनाव आने वाला है यह बगल में...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री रामबली सिंह यादव : एक मिनट महोदय, मैं पूरी जनता को मैं पूरे बिहार को कहना चाहूंगा कि...

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है रामबली बाबू ।

श्री रामबली सिंह यादव : अगर बिहार को आप विकास के रूप में देखना चाहते हैं तो बिहार में जो सरकार है, जो जदयू है उनको 43 से 13 पर लाइए, भाजपा को भगाइए और ...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शमीम अहमद साहब ।

श्री रामबली सिंह यादव : महागठबंधन की सरकार बनाइए, बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय । इन्कलाब जिन्दाबाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शमीम साहब, आपके पास 12 मिनट का वक्त है ।

श्री शमीम अहमद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं विपक्ष द्वारा लाए हुए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, सबसे पहले आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने नेता सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, युवाओं के भविष्य माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, अपने सचेतक श्री अख्तरूल ईमान साहब को और नरकटिया विधान सभा की सारी जनता को कि दूसरी बार उन्होंने मुझे विधान सभा भेजने का काम किया । आज जिस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि 2005 के पहले कुछ था ही नहीं । महोदय, आपको याद होगा कि जब केंद्र में यूपीए–1 की सरकार बनी और उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे और उस वक्त 90 हजार करोड़ का उन्होंने मुनाफा दिया था और उस वक्त माननीय रघुवंश बाबू ग्रामीण कार्य मंत्री

थे और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त जब ये दिल्ली गए थे और पत्रकार बंधु ने पूछा था क्या केंद्र सरकार आपको मदद कर रही है क्योंकि केंद्र में यूपीए–1 की सरकार थी और यहां एनडीए की सरकार थी तो हमारे मुख्यमंत्री का जवाब यही था कि मैं तो झोला लेकर आया था और यहां से बोरा भरकर ले जा रहा हूं लेकिन जब हमारे इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री राबड़ी जी थीं और एनडीए की सरकार केंद्र में थी तो हमारे मुख्यमंत्री ने आंचल फैलाकर के इस बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था लेकिन देने से इनकार कर दिया । विशेष राज्य का दर्जा कौन कहे, विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाया और जब सच्चर कमिटी की रिपोर्ट आयी महोदय, तो यहां पर अल्पसंख्यकों की स्थिति दलितों से भी बदतर थी । केंद्र सरकार ने एक एमएसडीपी योजना लायी थी, जिसके तहत यह कार्य होना था कि अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ाई का, हॉस्पिटल का, रख–रखाव का व्यवस्था होना था लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, इस योजना को बंद कर दिया गया और इस योजना को डाइवर्ट करके आधारभूत संरचना में लागू कर दिया गया । अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का भी आज है और ग्रामीण विकास मंत्री जी का भी है ग्रामीण विकास तो महोदय, ग्रामीण विकास की हम बात करते हैं । इस देश की आत्मा गांवों में बसती है और आज जो इतने अच्छे–अच्छे पोस्टर हमलोगों को, बजट भाषण के लिए किताब मिला लेकिन यह सिर्फ पढ़ने के लिए और दिखाने के लिए है महोदय । जितनी भी योजनाएं हैं यहां पर, कोई जमीन पर उतारा नहीं गया है । (क्रमशः)

टर्न–20 / सुरज / 17.03.2025

(क्रमशः)

श्री शमीम अहमद : ओ0डी0एफ0 से लेकर जीविका, स्वच्छता अभियान के माध्यम से जो भी आप जांच कराना चाह रहे हैं अचानक जांच कराके आप देख सकते हैं । जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं सभी अपने क्षेत्र के विधायक हैं लेकिन इनलोगों की बातों का कभी भी संज्ञान नहीं लिया जाता है । सिर्फ यही दिखाया जाता है कि 2005 के पहले क्या था और 2005 के बाद क्या हुआ । 2005 के पहले यही हुआ था कि लोगों को आजादी मिली थी कि कहीं भी

जाकर वह अपनी बात रख सकते थे लेकिन 2005 के बाद यही हुआ है कि जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता की बातों को रोका गया है कि कहीं अपनी बात तुम नहीं रख सकते हो ।

महोदय, आज ग्रामीण विकास की बात हो रही है लेकिन ग्रामीण विकास में अभी एक योजना चली है इंदिरा आवास में नाम जोड़ने के लिये । हर ब्लॉक, हर पंचायत में हाहाकार मचा हुआ है लोगों से पैसे की उगाही हो रही है । महोदय, जब जातीय जनगणना हुई हमलोग सरकार में थे । जब जातीय जनगणना हुई तो उस वक्त आंकड़ा आया कि लगभग 94 लाख लोग 6 हजार से नीचे पर बसर करते हैं, उनकी आमदनी मात्र 6 हजार रुपये है । 6 से 10 हजार रुपये तक 81 लाख लोग हैं । 10 से 20 हजार आमदनी वाले 49 लाख लोग हैं । 20 से 50 हजार आमदनी वाले 10 लाख के लगभग हैं और वैसे परिवार जो अपनी आय का स्रोत नहीं बताये वैसे 12 लाख लोग हैं । जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे, जातीय जनगणना का यही मकसद था कि जो बजट हम बनाये इसके आधार पर बने तब जा करके हम गांव का विकास कर सकते हैं लेकिन इसकी फिर अनदेखी कर दी गयी । एन0डी0ए0 की सरकार आयी और इस जातीय जनगणना को ठंडे बस्ते में रख दिया गया । कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम गांव का विकास कर सकते हैं ।

महोदय, दूसरी चीज यह है कि एम0एस0डी0पी0 योजना जो लायी गयी थी चूंकि समय कम मिला है मुझे लेकिन बात बहुत थी । एम0एस0डी0पी0 योजना के माध्यम से सबसे पहले हम पढ़ाई पर मेहनत नहीं करेंगे, एजुकेशन पर किसी जाति–धर्म के लोगों को, सभी को पढ़ने के लिये आजादी हम नहीं देंगे तब तक हम विकास नहीं कर पायेंगे । एम0एस0डी0पी0 योजना के माध्यम से किशनगंज में एम0यू0 की शाखा का प्रावधान हुआ था लेकिन एन0डी0ए0 की जब सरकार आयी तो वह एम0एस0डी0पी0 योजना अलीगढ़ में उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है । माननीय मंत्री जी यहां पर हैं मैं चाहूंगा कि बात करके इसको लागू करने का काम करेंगे ।

दूसरी चीज यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिये जो व्यवस्था किये हैं, बी0पी0एस0सी0 का इंटरेंस एग्जाम दिलवाने के लिये इसको हम चाहेंगे कि सिर्फ पटना तक सीमित न रखकर इसको जिला स्तर पर ऑनलाइन भी उसको जितने भी हमारे अल्पसंख्यक के हॉस्टल हैं वहां पर जोड़ने का काम करेंगे और आवासीय विद्यालय को जोड़ने का काम करेंगे । अभी तक आवासीय विद्यालय आप बहुत कम संख्या में खोल पाये हैं । महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना । प्रधानमंत्री जी जब आये थे तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गिड़गिड़ा कर बोले थे कि पटना को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए लेकिन नहीं बन पाया ।

बहरहाल मोतिहारी बना लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी एक फैकेल्टी उसमें उर्दू का नहीं दिया गया । महोदय, यह कैसा विकास है ? सबका साथ सबका विकास, यह कैसा विकास है तो वहां पर उर्दू की फैकेल्टी खोलने की हम मांग करते हैं । मरदसों का जो एम0एस0डी0पी0 योजना से पैसा स्कूलों को लगाने का काम कर रहे हैं, सारे स्कूल अच्छे हो जाएं लेकिन उसके साथ–साथ मदरसों को आधारभूत संरचना से जोड़ा जाय और जितने भी मदरसे का भवन जो डैमेज है उस डैमेज को सुधार करने का काम करेंगे और अल्पसंख्यक में पहले जो लोन मिलता था एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख इसको अब उद्योग विभाग से जोड़ दिया गया जो योजना 10 लाख से ऊपर की है और अभी मैंने बताया कि 6 हजार से कम पाने वाले लगभग 94 लाख लोग नीचे हैं, 6 हजार से नीचे वाले लोग हैं । ये लोग कैसे उस योजना का लाभ ले सकते हैं ? पहले से पचास हजार, एक लाख, दो लाख, पांच लाख तक का जो लोन था कम ब्याज दर पर, इसको लागू किया जाए ।

दूसरी चीज है कि मोतिहारी में अभी तक उद्योग के लिये कोई खास कदम नहीं उठाया गया है तो उद्योग मंत्री जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि स्टार्टअप एक मोतिहारी में भी बने ।

दूसरी चीज यह है कि 20 साल में खाद्य आपूर्ति विभाग भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है । इन्होंने एक कार्ड बनाया है वन नेशन वन कार्ड । वन नेशन वन कार्ड जो बना है इस कार्ड की इतनी बहुलता हो गयी है कि कहीं से भी कोई राशन ले सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन अब शमशान घाट और कब्रिस्तान से भी लोग आकर कार्ड बनवा ले रहे हैं यह....

उपाध्यक्ष : आपके पास मात्र एक मिनट का बक्त बचा है ।

श्री शमीम अहमद : शमशान घाट और कब्रिस्तान से भी रात में लोग आकर राशन ले जा रहे हैं । इस कार्ड को कौन इशू कर रहे हैं ? इसकी उच्चस्तरीय जांच हो और हम माननीय मंत्री जी से भी चाहेंगे कि यह राशन का जो गबन हो रहा है पूरे बिहार का मामला है, यह राशन जो जा रहा है यह कहां जा रहा है और यह सरकार कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं । जब तक हम गांव का विकास नहीं कर पायेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे । आज एक आदमी अगर कोई मवेशी पालक है एक गाय के लिये लोन लेना चाहता है...

उपाध्यक्ष : अब आप कृपया कर आसन ग्रहण करें ।

श्री शमीम अहमद : गाय के लोन के लिये उसको बैंक इतना परेशान करता है...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री शमीम अहमद : इतना कागजात मांगता है कि वह गाय खरीद नहीं पाता है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती शालिनी मिश्रा । आपके पास पांच मिनट का वक्त है ।

श्री शमीम अहमद : बकरी पालन के लिये व्यवस्था नहीं हो पाता है तो इन सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिये । इसके लिये हम चाहेंगे....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाएं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी के द्वारा जो बजट के अनुदान के लिये जो मांग की गयी है, उसके समर्थन में एवं विपक्ष के साथियों के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव दिया गया है उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं । हम सभी जानते हैं और काफी सदस्यों ने कहा है कि हमारा देश गांवों का देश है । बल्कि हमारे प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, गांवों में निवास करती है इसलिये हम यह कह सकते हैं कि हमारे बिहार की आत्मा गांवों में निवास करती है । इस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर मुझे चर्चा में भाग लेने के लिये, मौका देने के लिये आदरणीय मुख्य सचेतक श्रवण कुमार जी जो इस विभाग के मंत्री हैं एवं सभी विभाग के माननीय मंत्रीगण जो आज इस चर्चा में भाग ले रहे हैं उनको धन्यवाद देते हुये और आपको धन्यवाद देते हुये मैं अपनी बातों को आगे रखती हूं ।

आपने मुझे कहा सिर्फ पांच मिनट है मुझे जानकारी थी दस मिनट बोलना है तो उस हिसाब से तैयारी थी । फिर भी मैं कहना चाहती हूं, हमेशा कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी ही कहते हैं बिहार में क्या था 2005 से पहले । मैं कहना चाहती हूं पूरे सदन में कि बिहार में था न, बिहार में जंगलराज था, गुप अंधेरा था, बिहार की सड़कों में गढ्ढा था, बिहार में खेत में शौचालय और सड़कों पर शौचालय हुआ करता था, बिहार में अपहरण और फिरौती का व्यवसाय था । महोदय, यही सब तो था हमारे बिहार में । काफी कुछ था जो हमारे विपक्षी साथियों ने दिया 1990 से 2005 तक । मैं अपनी बातों को आगे कहते हुये यह कहना चाहती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने ग्रामीण विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया । उन्होंने हर वह काम किया ग्रामीण विकास के लिये जिससे हमारे ग्रामीण भाईयों, ग्रामीण जनता और ग्राम के विकास की जिंदगी में बदलाव हो ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / राहुल / 17.03.2025

श्रीमती शालिनी मिश्रा : (क्रमशः) महोदय, मुझे वह दिन भी याद है जब हमारे गांवों की स्थिति इतनी जर्जर हुआ करती थी, सड़कें तो थी ही नहीं गढ्ढे थे । इतनी खराब स्थिति थी कि पोल हो तो तार नहीं, तार हो पोल नहीं, अगर दोनों हैं तो ट्रांसफॉर्मर नहीं । इन लोगों के जमाने की बात है और ट्रांसफॉर्मर के लिए विधान सभा में क्वेश्चन किया जाता था, हम बजट सेशन में क्वेश्चन करते थे, हमारे सदस्यगण तो अगले मानसून सेशन में वह काम होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी । महोदय, यही था बिहार में 2005 से पहले । महोदय, हमारे बिहार के गांवों में शुरूआत सूर्योदय से होती थी और अंत सूर्यास्त से हो जाता था । हम सब लालटेन का सहारा लेते थे, विवश थे और उस लालटेन में कैरोसीन ऑयल डालने के लिए हम लोगों को जन वितरण की दुकान पर लाईन लगाकर लड़ाई–झगड़ा करना पड़ता था, उस कैरोसीन ऑयल के लिए । सबों को पता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था क्या थी ? इतनी जर्जर थी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाउंगी । बहुत कम समय है हमारे पास । मैं यह दावा नहीं कर रही हूं कि आज भी हर काम हो गया है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, हमारा राज्य विकासशील राज्य है इसको विकसित बनाने के लिए 2047 का प्लान बन गया है जिस पर काम चल रहा है तो एक दिन हमारा राज्य विकसित भी होगा लेकिन मैं बस यह कहना चाहती हूं कि जहां पर हमारे ग्रामीण भाई–बहिन, हमारे राज्य के लोग दो जून की रोटी के लिए तरसते थे एक अद्द कपड़े के लिए तरसते थे, सड़कों के लिए तरसते थे वहां पर आज चमचमाती सड़कें हैं, वहां पर हर जगह बिजली की व्यवस्था है, सब गरीबों का अपना मकान है और साथ ही साथ घरों में शौचालय है, नल–जल योजना के अंतर्गत पीने के पानी की व्यवस्था है । महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस प्रदेश में हमारी बहने भुखमरी का शिकार होती थी, मैं गर्व से कह रही हूं कि आज उस प्रदेश में जीविका की बहनें 30 लाख 25 हजार जीविका दीदीयां लखपति हो गयी हैं यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, यह हमारे बिहार की देन है, यह हमने किया है 2005 के बाद । यह सब हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता की वजह से हुआ है और मैं उनके लिए एक लाईन कहना चाहती हूं कि :

हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है ।
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता साफ हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, सिर्फ एक मिनट और दें मुझे । दस मिनट कहा गया था, समय नहीं मिला है आग्रह करती हूं, आपका संरक्षण चाहती हूं । महोदय, मैं अपनी बात कहती हूं मोतिहारी से पटना आने में जहां पूरा दिन लगा करता था अब मात्र दो से ढाई घंटे में हम लोग यहां तक पहुंच जाते हैं । कभी–कभी

ऐसा होता था कि हम लोग गांवों में रहना नहीं चाहते थे, शहरों में रहना चाहते थे, जो भी थोड़ा भी साधन, संपन्न है लेकिन अब आलम यह है कि...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री अनिल बाबू ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, एक मिनट और दे दें ।

उपाध्यक्ष : आपके पास में तीन मिनट का वक्त है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : धन्यवाद महोदय ।

(व्यवधान)

श्री अनिल कुमार : सर्वप्रथम मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर बोलने एवं अपनी राय रखने का सुअवसर प्रदान किया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर विकास की उंचाइयों के उत्कृष्ट शिखर को छू रहा है । इस क्रम में ग्रामीण विकास विभाग की तमाम योजनाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नया आयाम प्रदान कर रही हैं । ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी रोजगार तो पैदा कर ही रहा है परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है । ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति लगातार विगत बीस वर्षों में सुधरी है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आर्थिक स्थिति में बदलाव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समरसता, आर्थिक सुदृढ़ीकरण, स्थायी रोजगार का सृजन, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को सफल क्रियान्वयन से ही संभव हो सका है । प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत वैसे व्यक्ति जिन्हें रहने के लिए समुचित एवं पर्याप्त आवास नहीं था, को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है । इस योजना के सफल संचालन हेतु मैं ग्रामीण विकास विभाग को धन्यवाद देता हूं । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) । मनरेगा के इस कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों में आत्मविश्वास का संचार हुआ है । मजदूरों को रोजगार के अवसर निरंतर प्राप्त हो रहे हैं । इस योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन एवं दूर दृष्टि से स्थायी संरचनाओं का भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण हुआ है । ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्त्रोतों की स्थायी संरचना विकसित की गयी है । जीविका बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना । जीविका बिहार में महिलाओं के विकास के लिए कार्यरत है ।

ग्रामीण महिलाओं के जीवन में व्यापक सुधार की इस योजना में बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है । प्रत्येक गांव में महिलाओं के आय स्त्रोत के विकास हेतु लगातार प्रयास किये गये हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का परिणाम यह हुआ कि...

अध्यक्ष : अनिल जी अब समाप्त करिये ।

श्री अनिल कुमार : जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें सशक्त भूमिका निभा रही हैं । ग्रामीण विकास विभाग की तमाम योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से बिहार के गांव आज जगमगा रहे हैं । प्रत्येक ग्राम तक सुदृढ़ सड़क, शिक्षा की पर्याप्त सुविधा, स्वास्थ्य की देख–रेख के लिए स्वास्थ्य केन्द्र...

अध्यक्ष : अनिल जी आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, उद्योग के क्षेत्र में बिहार में क्रांति आयी है । 2005 के पूर्व अपहरण के डर से उद्योग लगाने की कोई हिम्मत नहीं जुटाता था । उद्योग लगाने के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं थी । न बिजली थी, न सड़क थी, इसके अलावा सरकार के द्वारा उद्योग लगाने हेतु किसी तरह की...

अध्यक्ष : अनिल जी अब समाप्त करिये । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अनिल कुमार : सुविधा नहीं थी । धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : श्रीमती प्रतिमा कुमारी । आपके पास 14 मिनट का समय है ।

श्रीमती प्रतिमा कुमार : अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद । आज मैं विपक्ष द्वारा ग्रामीण विकास विभाग पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी हुई हूं । इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार के हमारी पार्टी के सी0एल0पी0 लीडर शकील अहमद खान साहब और यहां पर हमारे गठबंधन के सभी सम्मानित नेता के साथ ही अपने राजापाकर विधान सभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देती हूं। जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से, जिन्होंने हम पर पूरा भरोसा करके बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का जो मुझे सहयोग दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग का बजट पेश किया जा रहा है और हमारे विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल बजट का 5 परसेंट है और पहले भी जिस तरीके से हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी जो राशि है, ग्रामीण विकास विभाग में खर्च नहीं की जाती है । विगत वर्षों से सरकार द्वारा सात निश्चय पार्ट–1, सात निश्चय पार्ट–2 लाकर के ग्रामीण विकास की बात की गयी लेकिन धरातल पर सिर्फ और सिर्फ यह विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए दिख रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों, वंचितों, दलितों, शोषितों को पक्का मकान उपलब्ध

कराना लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है । प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने के लिए प्रखंड के बी0डी0ओ0 के माध्यम से आवास सहायक को दलाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । जो लोग दो–दो हजार रुपये देंगे उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ा जायेगा । जॉब कार्ड में बहुत से रोजगार की बात करते हैं । मनरेगा की बात करते हैं, रोजगार में जो गरीब लोग हैं, जो लाभान्वित हो सकते हैं, जो काम की खोज में सरकार के पास जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं उनका नाम काट दिया जाता है, नाम जुड़वाने के नाम पर उनसे दो हजार रुपये लिये जाते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का सतत् और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है । सड़क, बिजली, पानी, पेयजल, शौचालय, सामुदायिक भवन आदि की व्यवस्था करानी है लेकिन सड़क की बात की जाय तो गांव के जो भी दलित टोले हैं, जो दलितों की बसावट है, जहां पहुंच पथ, जहां प्रधानमंत्री पहुंच पथ योजना, मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना । ये योजना सिर्फ और सिर्फ कागजों में बनकर रह गयी हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूं चूंकि मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं, लोगों से मिलती हूं इसलिए मैं क्षेत्र की तरफ माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं । हमारे क्षेत्र में बाकड़पुर पंचायत जो राजापाकर प्रखंड में पड़ती है, 13 नंबर वार्ड है, कई वर्षों से सैकड़ों की आबादी, दो–चार सौ दलित समाज के लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर विकास मित्र भी है, लोगों का काम भी करता है लेकिन आज तक वहां पहुंच पथ नहीं है । मैंने पहुंच पथ के लिए विधान सभा के अंदर ध्यानाकर्षण भी लाया था कि गरीबों के, दलितों के, जो अतिपिछड़े समाज के लोग हैं उनके पास भूमि नहीं है वे गांवों के बीच में बसते हैं, पहुंच पथ का अभाव है ।

(क्रमशः)

टर्न–22 / मुकुल / 17.03.2025

क्रमशः

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : घर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं, जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है । दलित विकास मिशन के पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है । मैं अपने सहदेई प्रखंड के सैनी पोखर नया गांव पश्चिमी की बात करूं, 2 नंबर वार्ड में लगभग सैकड़ों आबादी हैं दलितों की, वहां तक पहुंच पथ नहीं है । यह तो एक मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात है, वैसे पूरे बिहार की बात की जाय तो ऐसे हजारों गांव लगभग बिहार में 45 हजार गांव हैं, उनमें हजारों गांव दलितों का होगा जहां पर पहुंच पथ का अभाव है और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, चूंकि चुनाव के टाइम में जिनके रास्ते से ये जाते हैं उनके दबाव में आकर के उनसे वोट लिया

जाता है तो यह बहुत दुख की बात है । जिस राज्य में सुशासन की बात होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बिहार सरकार के जो मंत्रीगण हैं वे कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, यह कैसा न्याय है माननीय अध्यक्ष महोदय । अब मैं कौशल विकास की बात करूं, जीविका दीदियों की बात होती है, जीविका के विकास की बात होती है ।

(व्यवधान)

मैडम, कव्वाली नहीं हो रही है, बहुत गंभीर बात हो रही है, कृपया ध्यान से सुनिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप इधर देखकर बोलिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं कौशल विकास की बात करूं तो महिलाओं की जो जीविका दीदी हैं, वर्षों से इस आस में जुड़कर के काम कर रही हैं कि हमारा स्कील डेवल्पमेंट होगा और मैं अपने हुनर को आगे बढ़ाकर के काम करके कुछ पैसे कमाऊंगी लेकिन हो क्या रहा है जीविका दीदी बकरी पालेंगी, जीविका दीदी गाय पालेंगी, जीविका दीदी पारच्युन का दुकान खोलेंगी, क्या बिहार की महिलाएं यही काम करने के लिए हैं, क्या उनका स्कील डेवल्पमेंट नहीं हो सकता है, क्या उनके लिए छोटे–छोटे कुटीर उद्योग बनाकर के उनका विकास नहीं किया जा सकता है । महिला विकास की बात होती है, मैं अलग महिलाओं की बात करूंगी, हमारी आशा हैं, ममता हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, आशा दीदियों का क्या हाल हो गया है जो अपनी सेवा 8–8 घंटे देती हैं उनको मात्र एक हजार रुपया मानदेय देते हैं, 600 रुपया प्रति डिलीवरी प्रोत्साहन राशि देते हैं ये क्या उनका आर्थिक शोषण नहीं है, यह महिलाओं के साथ न्याय नहीं है, बल्कि बिहार में रहने वाली लगभग 7 करोड़ महिलाओं के साथ अन्याय है महोदय । मैं चाहती हूं कि सरकार इन महिलाओं को उद्योग से जोड़कर के इनका स्कील डेवल्पमेंट कराये, ग्रामीण स्तर पर इनको रोजगार उपलब्ध करवाकर इनके हुनर को बढ़ाये, चाहे वह किसी समाज की महिला हो । अभी स्वच्छता की बात होती है, स्वच्छ भारत की बात होती है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वच्छता आजादी से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ जगह में ही स्वच्छ मन का वास होता है और स्वच्छ रहकर ही हम स्वच्छ भारत की परिकल्पना कर सकते हैं लेकिन हो क्या रहा है, लोहिया अभियान के तहत जिनको यह जिम्मेवारी मिली कि आप रिक्शा, ठेला खरीदिए, सूखा और गिला कचरा अलग–अलग कीजिए, वह क्या किए, उन्होंने इसमें गजब का भ्रष्टाचार किया । गांव में जो उनके करीबी लोग हैं, उनके यहां तो डस्टबिन पहुंच गया, लेकिन जो उनके विरोध में हैं, जो उनको वोट नहीं दिया वैसे पंचायतों में देखिए, पक्ष–विपक्ष हर जगह होते हैं वहां

डस्टबिन नहीं मिला, कहीं ई–रिक्शा खराब है, कभी कचरा उठाने वाला नहीं आ रहा है, गंदगी का अंबार पसरा हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों जहां–जहां जांच होती है, किनकी होती है जो दलित समाज के मुखिया होते हैं, उनकी योजनाओं की जांच करके उनको जेल भेजने की, उन पर एफ0आई0आर0 करने की कवायद चलती है तो सिर्फ दलित मुखिया ही क्यों आरोपी है, वहां के जितने भी अधिकारी हैं चाहे वह बी0डी0ओ0 हों, डी0डी0सी0 हों इन सब पर भी आरोप लगाकर उनपर भी एफ0आई0आर0 होना चाहिए, चूंकि अधिकारियों का काम है मॉनिटरिंग करना न कि बैठकर के सिर्फ कागज पर योजना बनाकर के और कागज पर काम करना, अभी बिहार में बस यही हो रहा है । पंचवर्षीय योजना बनती है, लेकिन योजना सिर्फ और सिर्फ एक महीना चला, दो महीना चला उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है । यदि विपक्ष के लोग कोई कम्प्लेन करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जिसकी वजह से अधिकारियों का अफरसरशाही बढ़ते जा रहा है बिहार में । इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए जिस तरीके से बिहार में पलायन बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है मैं नहीं नहीं कह रही हूं अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट है जिसमें है कि ग्रामीण क्षेत्र के 87 से 88 प्रतिशत लोग रोजगार विहीन हैं और इससे बिहार भी अछूता नहीं है । इसलिए हमारी पार्टी के द्वारा युवाओं को रोजगार मिले हमलोगों ने यात्रा निकाली है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से बिहार में आउट सोर्सिंग का एक चलन शुरू हो गया है, आप आउट सोर्सिंग से आइये आपको नौकरी दी जायेगी और बेचारे करें क्या, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है उनको परिवार चलाना है, उनके साथ मजबूरी है जिनको 10 हजार रुपया कागज पर साइन कराते हैं उनको 6 हजार रुपया दिया जाता है तो क्या ऐसे हम नौजवानों को सशक्त करेंगे, बिहार का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, बिहार के लोग मेहनती होते हैं, बिहार से लोग सीखने आते हैं, अभी एक दिन तारांकित सवाल था, जब विपक्ष के लोगों ने कहा कि पलायन हो रहा है तो सत्तापक्ष की तरफ से जवाब आया कि पलायन प्रकृति का नियम है लोग विकास के लिए बाहर जाते हैं तो क्या मजदूरी करने के लिए पलायन करना वह विकास की बात है । हमलोग पेपर के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हैं कि बिचौलिये उस गरीब–गुरबा, पिछड़े–दलित लोगों उठाकर के दिल्ली, मुम्बई, असम जहां–तहां ले जाकर के उनसे मजदूरी करवाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गयी है कि वे घर भी नहीं आ पाते हैं, समय पर उनको पैसा नहीं दिया जाता है, उनका सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण हो रहा है अध्यक्ष महोदय, इस पर रोक लगाने की जरूरत है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं, आशा दीदी, जीविका दीदियों के बारे में कहना चाहती हूं जिनको एक परसेंट ब्याज पर जो

उनको लोन उपलब्ध किया जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की बात है उसको माफ किया जाय और जो लोन उनको दिया जा रहा है उसके लिए उनका स्कील डेवल्पमेंट करवाकर के तब उनको पैसा दिया जाय ताकि वह काम करें । उद्योग विभाग की मैं बात करूं, आज उद्योग विभाग का भी बजट है तो जो उद्योग बिहार में लगाये जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और हमारे सामने माननीय मंत्री, उद्योग विभाग बैठे हुए हैं जो कि काफी पढ़े–लिखे हैं तो मैं इनसे आग्रह करूंगी कि जिस नेचर का जो जिला है उस तरीके का वहां पर उद्योग लगाया जाये ताकि वहां के किसानों को, वहां के लोगों को इसका फायदा मिल सके, जैसे हमारा जिला वैशाली केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है तो वहां पर केला है, अमरूद है, आम है इस तरीके के उद्योग–धंधे को डेवल्प किया जायेगा तो वहां के लोगों का हमलोग पलायन रोक सकते हैं । अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय जमा खां साहब बैठे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि वर्ष 2022 में मैंने एक क्वैश्चन भी किया था, पत्र भी दिया था हमारे यहां अल्पसंख्यक समाज की बहुत आबादी है, गरीब हैं, पिछड़े हैं शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए मैंने आवासीय विद्यालय के लिए लिखित दिया, सबकुछ होने के बाद भी जिला और सी0ओ0 स्तर से, अंचल अधिकारी स्तर से शिथिलता बरती जा रही है जिसकी वजह से अभी तक इसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है और न इसकी सूचना मुझे दी जाती है कि हां आपके यहां जो आपने मांग की थी वह काम कितना आगे तक बढ़ा है । खाद्य उपभोक्ता मंत्री माननीय लेशी मैडम बैठी हुई हैं मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि गरीब–गुरबा जिनको राशन की जरूरत है, जिनके लिए हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने भोजन का अधिकार 2013 में लागू किया था ताकि देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं जो भूख से न मरें, जो अन्न से, भोजन से वंचित न रहें लेकिन मैडम बिल्कुल उल्टा हो रहा है, आप अपने स्तर से माननीय अध्यक्ष महोदय हम मैडम से कहना चाहते हैं कि ये अपने स्तर से जांच करवायें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपके पास एक मिनट का समय बचा है ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : जो बिचौलिये हैं, ए0जी0एम0 रैंक के जो लोग हैं, डी0जी0एम0 रैंक के जो लोग हैं जो अनाज को गोदाम से बेच रहे हैं उनपर कार्रवाई की जाये और जो गरीब–गुरबा के लिए 2–2 हजार रुपये राशन कार्ड बनाने के लिए जो डिमांड किया जा रहा है, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है तभी हमलोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ये योजनाएं कागज पर बनकर धरातल पर नहीं उतरेंगी, जय हिंद, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार, आपके पास दो मिनट का समय है ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुख्य तौर पर ग्रामीण विकास विभाग का जो मुख्य काम है वह मनरेगा, स्वच्छता मिशन भी है, आवास योजना भी है, जीविका है, लेकिन मनरेगा के काम को जब मैं देखता हूं तब मैं पाता हूं कि मनरेगा जो मजदूरों के सिर्फ जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसकी जीविका चले, उसकी रोटी चले उसके लिए यह बनाया गया था । मगर मनरेगा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है । पूरे बिहार में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप जांच करवा लीजिए, मनरेगा में भ्रष्टाचार इतना है और होना भी लाजिमी है । चूंकि आपने उसके लिए मजदूरी कितना तय किया है 266 रुपया । आज बिहार के किसी भी खेत में काम करने वाले मजदूर की भी मजदूरी कम से कम 300 से 400 रुपया है, उससे कम में मजदूर नहीं मिलते हैं और तब सरकार जो चाहती है 266 रुपया में कोई मजदूर काम करे, यह इम्पॉसिब्ल है और इसीलिए भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है । मेरी सरकार से मांग है, मैं मांग करना चाहता हूं कि आपने तो 521 रुपया न्यूनतम मजदूरी तय किया है, आप केरल की तरह बढ़ाकर कर सकते हैं, मैं बार–बार केरल का उदाहरण देता हूं, एक कमेटी भेजकर के आप अध्ययन कीजिए, एक छोटा सा राज्य कैसे यह काम कर रहा है, आप इस काम को कीजिए ।

क्रमशः

टर्न–23 / यानपति / 17.03.2025

(क्रमशः)

श्री अजय कुमार : महोदय, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, स्वच्छता मिशन आप चला रहे हैं, लेकिन जिनके भरोसे आप चला रहे हैं, जिसको स्वच्छता कर्मी के रूप में आपने बहाल किया, उसको मजदूरी कितना देते हैं, 100 रुपया, 100 रुपया किस हिसाब से देते हैं, एक दिन की मजदूर की मजदूरी तो कम से कम दीजिए और आप 100 रुपया पर उससे 8 घंटा काम लीजिएगा यह संभव नहीं है । यह बिल्कुल उसका शोषण हो रहा है । अभी आवास योजना की जो बात है, बोल रही थीं माननीय सदस्या, आवास योजना का जो अभी सर्वे का काम चल रहा है पूरे बिहार का, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक ब्लॉक की भी जांच करवा लीजिए, वहां एक–एक आवास का नाम जुड़वाने में 2–2 हजार रुपये लिये जाते हैं और तब वह नाम जोड़ा जाता है । मैं चुनौती देकर कह

रहा हूं कि आप किसी एक ब्लॉक की जांच करवा लीजिए । दूसरा जीविका के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जीविका मिशन चलाया है लेकिन उसका शोषण कहां हो रहा है । जब बैंक से पैसा लेकर महिलाओं के बीच बांटा जाता है और तब जो उसको वापसी के लिए उसका शोषण होता है, और अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा उसको ऋण दिया जाता है...

अध्यक्ष : अब समाप्त किया जाय ।

श्री अजय कुमार : 30 सेकंड लेकर के मैं, महोदय, बहुत कम समय है, मैं उद्योग के बारे में बोलकर के अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं, आपसे मैं उद्योग विभाग के बारे में, किसी भी राज्य का विकास, जब तक उद्योग का विकास नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता लेकिन बिहार के अंदर पहले 28 चीनी मिल थी आज मात्र 11 चीनी मिल है, बिहार में दो जूट मिल था एक समस्तीपुर का, मुक्तापुर का जूट मिल और कटिहार का जूट मिल ये दोनों जो है...

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । श्री सूर्यकान्त पासवान । दो मिनट का समय है आपके पास ।

श्री अजय कुमार : आज वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, माननीय उद्योग मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि समस्तीपुर में जूट मिल को जिंदा कर दीजिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ...

श्री सूर्यकान्त पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाये गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ है । आज महोदय, ग्रामीण विकास विभाग का क्या हाल है, आज किन्हीं माननीय सदस्यों से छुपा हुआ नहीं है महोदय । आज मनरेगा के द्वारा जो साल में 100 दिन मजदूरों को काम देने की गारंटी की गई थी, आज मशीन से काम किया जा रहा है । आज मशीन के द्वारा काम किया जा रहा है और मजदूरों का पलायन हो रहा है । ये लोग भी बोल रहे हैं सहरसा से शुरू कीजिए और अररिया, किशनगंज जितने भी हमारे राज्य के जिला हैं तमाम जिलों से जो गाड़ियां खुलती हैं उसमें हमारे मजदूरों को बोरा की तरह ठूसकर दूसरे राज्य में काम के लिए जाना पड़ता है । आज मनरेगा, मनरेगा ही रह गया । महात्मा गांधी का वह सपना था, वह सपना आज आउटसोर्सिंग, यह राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो काम लिया जा रहा है आज उसकी जांच नहीं हो रही है । जो कंपनियों को काम दिया जा रहा है, जो वाजिब मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको वाजिब मजदूरी नहीं मिल रही है, वह सारा लूट खसोट कंपनी के लोग करते हैं । आज डी0पी0एम0 को हटाया गया है पूरे राज्य के अंदर, जबकि वह काम कर रहा

था प्रखंड के अंदर । आज उद्योग की बात, आज बेगूसराय औद्योगिक नगरी है लेकिन बेगूसराय के नौजवानों को उस उद्योग में रोजगार नहीं मिल रहा है जबकि देश का आठवां स्थान, प्रदूषित शहर में हमारा बेगूसराय जिला है लेकिन बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है । महोदय, आज अल्पसंख्यक कल्याण की बात की जाय तो हमारे जिला के अंदर कई विवादित कब्रिस्तान हैं जो वर्षों से विवाद चला आ रहा है जबकि अंचल अधिकारी बखरी, बेगूसराय के अंदर बखरी हमारा प्रखंड है, अंचल अधिकारी ने उस कब्रिस्तान को जायज करार दिया है, कागज पत्तर उनका है उसके बावजूद भी पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी हैं...

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : वह कहते हैं यह कब्रिस्तान नहीं, हम इसकी घेराबंदी नहीं करेंगे, बैठे हुए हैं माननीय मंत्री महोदय...

अध्यक्ष : समाप्त करिए अब ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि विवादित कब्रिस्तान को निश्चित रूप से आप घेराबंदी करवा दीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल ईमान ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, हमारा ब्लॉक वर्षों से क्षतिग्रस्त है, पदाधिकारी बैठते हैं, एक मिनट महोदय, पदाधिकारी बैठते हैं, छत गिरता है महोदय वर्षों से हमारा अंचल कार्यालय जर्जर है, वह...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान । आपका 1 मिनट समय है।

श्री सूर्यकान्त पासवान : यह सुशासन की बात करते हैं, मेरा अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय कनदारी हो, बखरी हो, या गरपुरा हो काफी जर्जर है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे अंचल और ब्लॉक कार्यालय को बना दें ।

अध्यक्ष : हो गया, बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान जी को बोलने दीजिए। माननीय सदस्य, आपके पास एक मिनट है ।

श्री अख्तरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि शरीफ आदमी हैं, संजीदा हैं और ईमानदार हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में दोनों ब्लॉक में मकान की स्वीकृति दी है, मैं उनको बधाई देता हूं

लेकिन एक बात यह भी कहता हूं कि यह चौकीदार ईमानदार बहुत है, कभी चोरी नहीं किया लेकिन महोदय, अफसोस है कि चोर को यह रोक भी नहीं पाते हैं । मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं इस वक्त कि इस वक्त बिहार में 8463 पंचायत हैं 1 लाख 15 हजार वार्ड हैं, 1 लाख 15 हजार वार्ड में हरेक वार्ड में दो–दो लाख रुपये की उगाही हो रही है, एक पंचायत में 28 लाख रुपये वसूले जा रहे हैं आवास के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर । महोदय, अगर उसको जोड़ा जाय 8463 पंचायत में...

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अख्तरूल ईमान : तो 2370 करोड़ रुपया होता है, इसपर रोक लगाई जाय और दो मुद्दे मैं आपको कहूंगा कि उद्योग विभाग ने किशनगंज में चमरा धुलाई का काम शुरू कराने का फैसला किया, मुबारकबाद देता हूं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारे यहां दे मौका...

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश कुमार ।

श्री अख्तरूल ईमान : एक मुद्दा सर, अकलियत का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि यहां पर हैं एक मामला है...

अध्यक्ष : मिलकर कह दीजिएगा, दे दीजिए ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आज मुझे...

अध्यक्ष : मिथिलेश जी, पांच मिनट में खत्म कीजिए ।

श्री मिथिलेश कुमार : आज मुझे ग्रामीण विकास और उद्योग के संदर्भ में बोलने का अवसर मिला उसके लिए मैं अपने एन0डी0ए0 नेतृत्व और आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं और दुनिया की विशिष्टतम धरती सीता प्राकट्य स्थली के संपूर्ण जानकी पुत्रों का अभिनंदन करता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अख्तरूल साहब, बैठ जाइये ।

श्री मिथिलेश कुमार : कि उन्होंने इस लायक मुझे बनाया कि आज मुझे सदन में बोलने का अवसर मिला है । महोदय, ग्रामीण विकास के कार्य की बात करते हैं, ग्रामीण विकास विभाग में हमने जो मापदंड खड़ा किया है वह ग्रामीण विकास...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, अख्तरूल ईमान जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है, बैठ जाइये ।

श्री मिथिलेश कुमार : विभाग का मापदंड, संपूर्ण भारत में बिहार का जो ग्रामीण विकास का उत्थान हुआ है, उद्भव हुआ है वह संपूर्ण भारत में प्रशस्ति पा रहा है । महोदय, उद्योग की बात हो रही है, उद्योग का विषय मिला है । हमने उद्योग में जो पारामीटर खड़ा किया है, 39 जिलों में 11 हजार एकड़ इंडस्ट्री हब का बनाने के लिए हमलोगों ने अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है, प्रचुर मात्रा में वित्त उपलब्ध करवाया है । महोदय, उद्योग में एन0डी0ए0 सरकार में उद्योग की चर्चा होती है अपहरण उद्योग बनाम पर्यटन उद्योग, अपहरण उद्योग बनाम एथनॉल उद्योग, अपहरण उद्योग बनाम कृषि उद्योग, अपहरण उद्योग बनाम इंडस्ट्री हब, महोदय, उद्योग के बारे में जो हमने पारामीटर खड़ा किया है वह संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व में बिहार को सम्मान दिलाया है । महोदय, जीविका का, जो हमारा ग्रामीण विकास विभाग में जीविका के क्षेत्र में जो हमने मापदंड खड़े किए हैं वह संपूर्ण हिन्दुस्तान, बिहार का अनुकरण करने के लिए तैयार है । जीविका के क्षेत्र में महोदय, महिलाओं को स्वावलंबी बनने का जो अवसर मिल रहा है यह बिहार नजीर बन रहा है संपूर्ण देश के अंदर । हमारे ग्रामीण विकास मिशन में जल– जीवन–हरियाली मिशन, हमलोग प्रकृति के साथ–साथ यहां के गरीब गुरबों का ख्याल रखते हैं कि हमारा गरीब गुरबा कैसे गांव में रहकर, काम करके स्वस्थ रहे, कैसे स्वस्थ जल पिये, कैसे स्वस्थ ऑक्सीजन मिले ताकि उसको स्वस्थ रखकर हम अस्पताल तक भेजने का अवसर ही नहीं दें लेकिन ये विपक्ष के लोग जल–जीवन–हरियाली पर भी प्रश्न उठाते हैं । जल–जीवन–हरियाली होगा, बिहार समृद्ध होगा, स्वस्थ रहेंगे तो आप सबों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा । जल–जीवन–हरियाली यह जीविका, जल–जीवन–हरियाली योजना जो राज्य सरकार ने दिया है वह संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में अपना एक मानदंड खड़ा किया है जिसको दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्य में सभी राज्य जीविका का अनुकरण करके उस पर प्रयोग कर रहे हैं जिसमें बिहार ने सफलता पाई है और ग्रामीण विकास विभाग में वर्षों–वर्ष से जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़े भवन जिसमें गरीबों, किसानों के अभिलेखों को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था वहां हमने प्रखंड और अंचल और सभी कार्यालयों के लिए वित्तीय व्यवस्था की है । महोदय, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक हमलोग 34455 लाभुकों को उद्योगों की स्थापना के लिए 2764 करोड़ रुपया राशि दे चुके हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–24 / अंजली / 17.03.2025

(क्रमशः)

श्री मिथिलेश कुमार : और वित्तीय वर्ष 2024–2025 में 92 सौ से अधिक लाभुकों का चयन किया गया है । महोदय, राज्य सुव्यवस्थित चले, सभी चीजों का संतुलन रहे, इसके लिए दूरदर्शिता परम आवश्यक है । आवश्यक है ईमानदारी के साथ काम करना, जिस लोकतंत्र के मंदिर में जनता हमें चुनकर भेजती है, उस लोकतंत्र के मंदिर में अपने कार्यों का नजीर पेश करना यह है एन0डी0ए0 सरकार की विशेषता, जिसके कारण एन0डी0ए0 सरकार, केंद्र की एन0डी0ए0 की सरकार विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही है और बिहार राज्य की एन0डी0ए0 सरकार संपूर्ण भारत में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही है । महोदय, देखने का चक्षु नहीं होगा तो उसमें सरकार का क्या दोष है ? आप जमीन पर जाकर देखें, आप लाभुकों से मिलें, हम विकास मित्रों के साथ बैठक करते हैं, हम आशा दीदीयों के साथ बैठक करते हैं, उनके साथ उनके सुख–दुख में साझेदारी करते हैं, उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, अधिकारी से करवाते हैं, अपने सरकार के मंत्रियों से । महोदय, अपने किये हुये कालिख को पोतने के लिए किसी पर ऊंगली उठाना यह हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं रही है । हमलोगों ने जो काम किया है, हमलोग काम की चर्चा करते हैं । महोदय, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को...

अध्यक्ष : संक्षेप में अपनी बात कहिए । एक मिनट में खत्म करिए ।

श्री मिथिलेश कुमार : स्वरोजगार आरंभ करने हेतु 2 लाख रुपए का अनुदान बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत हमलोग दिये हैं उसमें अब तक 40 हजार 99 लाभुकों को उद्योग की स्थापना के लिए 214.22 करोड़ रुपए से अधिक राशि सहायता में दे चुके हैं । महोदय, बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की सहमति प्रदान की गई है । महोदय, उद्योग की जहां तक बात है, हमारा सीतामढ़ी क्षेत्र है, यह सीतामढ़ी भी नजीर है उद्योग के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया है । एक तरफ हम बिहार में सबसे पहले सीता जन्मस्थली पर बिहार कृषि उत्पादन बाजार समिति की स्थापना करके उसका उद्घाटन करते हैं यह किसानों के उद्योग के लिए विशिष्ट चीज होता है । दूसरी तरफ, पर्यटन विकास के लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण की स्वीकृति देते हैं और 71 करोड़ का वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया है । तीसरी तरफ, उद्योग के लिए एक सीतामढ़ी जिला में 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब का जमीन हमलोग अधिग्रहण करने की योजना बनाते हैं तो हम देख रहे हैं...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए ।

श्री मिथिलेश कुमार : हर क्षेत्र में उद्योग के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इनको नजर आता है कि लोग लद कर जा रहे हैं । अरे भाई बिहार का इंजीनियर, बिहार का डॉक्टर...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए मिथिलेश जी ।

श्री मिथिलेश कुमार : हर जिले के मेडिकल कॉलेज से पढ़कर जाते हैं बाहर काम करने, दूसरे प्रांत में अपना तालीम देने जाते हैं । बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बिजय सिंह । आपके पास केवल 5 मिनट का समय है ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश बाबू जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, खासकर बरारी के देवतुल्य जनता जर्नादन को धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में उन्होंने मुझे भेजने का काम किया है ।

आज ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो इसमें मुख्य काम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, साल के 365 दिन हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार लोग हैं, राज्य सरकार उसको 100 दिनों का काम देती है और उन 100 दिनों के रोजगार में उसको जो वेतन या रोजी–रोटी मिलती है उसमें केंद्र की सरकार के द्वारा 75 परसेंट राशि और राज्य के द्वारा 25 परसेंट की राशि दी जाती है और यह राशि पहले बहुत कम थी । अब उसको 01.04.2024 से बढ़ाया गया है एवं इस राज्य में प्रभावी कर दिया गया है, हम धन्यवाद अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को देना चाहेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोग अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जाते थे तो युवा वर्ग हमलोग से खेल के मैदान की मांग करते थे । फंड के अभाव के कारण हमलोग अपने क्षेत्रों में स्टेडियम का निर्माण नहीं करा पाते थे लेकिन हम राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे बिहार में एक साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण पंचायतों में 6669 खेल मैदान जो सुविधापूर्ण बनाया जा रहा है, इसके लिए हमारे युवा स्टेडियम में खेलने के लिए अपने ग्रामीण क्षेत्र से हटकर नगर के क्षेत्र की ओर जाते हैं तब वह अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपना खेलयापन कर सकते हैं । हम धन्यवाद अपने नेता श्री नीतीश बाबू जी को देना चाहते हैं, उन्होंने पूरे बिहार में अभी प्रधानमंत्री आवास का सर्वे का काम चालू है । हमारे

क्षेत्र में, हम बरारी विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, 50–60 सालों से जो विस्थापित परिवार थे, जिनको अपनी जमीन नहीं थी, सरकार ने वैसे भूमिहीन लोगों को पर्चा देने का काम किया है । पहले उनकी अपनी जमीन नहीं थी, तो अब प्रधानमंत्री आवास में उसका नाम आ रहा है । अब जमीन उसका हो गया, प्रधानमंत्री आवास का उसको लाभ मिल रहा है । खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम यह धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वास क्रय योजना के तहत जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जिसको रहने के लिए 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है सरकार वैसे लोगों को और जल–जीवन–हरियाली के अभियान के तहत जो अतिक्रमण करके उसको हटा दिया गया था वैसे लोगों के लिए राज्य सरकार एक लाख रुपया सहायता राशि मुहैया कराती है ताकि वह एक डिसमिल, दो डिसमिल जमीन लेकर के अपने घर को बना सकें । हम धन्यवाद अपने नेता को भी देना चाहते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना जो 01.04.2010 से पूर्व से इंदिरा आवास, जिसमें हमारे पिछड़ा/अतिपिछड़ा, दलित, महादलित परिवार के लोग रहते थे, इनका छत टूट गया था, जिसका खिड़की नहीं था, जिसका दरवाजा नहीं था, बरसात के दिनों में जिसका घर चूता था वैसे सभी लोगों के राज्य सरकार 50 हजार रुपया सहायता राशि दे रही है । धन्यवाद हम अपने नेता को देना चाहेंगे जल–जीवन–हरियाली योजना के तहत बिहार को सुंदर, हरित एवं स्वच्छ बनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल–जीवन–हरियाली योजना लाकर बिहार का कायाकल्प करने का काम किया है । हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ेंगे, इसके लिए इन्होंने पर्याप्त जल उपलब्धता की व्यवस्था की । पर्यावरण संतुलन की व्यवस्था कराया, वन पर्यावरण को बढ़ावा देने का काम किया खासकर 5 वर्षों में इन क्षेत्रों में जो काम हुआ है, दुबई के कॉप–28 सम्मेलन में जल–जीवन–हरियाली को वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना करने का काम किया है, इसलिए हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश बाबू जी के लिए एक बार कसकर ताली मारिये कि उन्होंने जल–जीवन–हरियाली में काम करने का काम किया है । खासकर जल–जीवन–हरियाली के बाद चतुर्थ जल पुरस्कार 2022 में पूरे देश को बिहार का तीसरा पुरस्कार मिलने का काम किया है । हम धन्यवाद अपने नेता को देना चाहते हैं कि अभी प्रगति यात्रा के दौरान पूरे बिहार में जो अंचल–सह–आवासीय कार्यालय का निर्माण हो रहा है, हमारे विधान सभा बरारी में आकर बरारी, कुरसेला, सवेली उन्होंने नए प्रखंड कार्यालय बनाने की घोषणा की इसके लिए बरारी जनता की ओर से हम उनको धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं । खासकर अल्पसंख्यक समाज की बात करें...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये बिजय जी ।

श्री बिजय सिंह : महोदय, एक मिनट । अल्पसंख्यक समाज में भी काफी काम हो रहा है, धन्यवाद अपने नेता को देना चाहते हैं, मदरसों का निर्माण हो रहा है, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है, तकालशुदा महिलाओं को सहायता दी जा रही है । खासकर सुरक्षा की बात करें तो अभी पूरे बिहार में राशन फ्री में मिल रहा है 5 किलो राशन और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देते हैं...

अध्यक्ष : सरकार को भी उत्तर देना है । अपनी बात समाप्त करिये ।

श्री बिजय सिंह : महोदय, लास्ट हम बोलते हैं, उद्योग की बात करें तो उद्योग के क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री 10 लाख जो सहायता राशि देती है जिसमें 5 लाख रुपया तो मुफ्त है जिसको छोड़ दिया जाता है और 5 लाख रुपया 84 किस्तों में दिया जाता है इससे काफी युवा लोग आगे बढ़ रहे हैं । खासकर हम बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जो जाति गणना कराकर वैसे बेरोजगार लोग जो 94 लाख लोग थे उनको 2–2 लाख रुपया सहायता राशि देने का काम कर रहे हैं तो इसके लिए धन्यवाद हम अपने नेता को देते हैं जो अनुदान मांग लाया गया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइए । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग ।

सरकार का उत्तर

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आप लोग रहिएगा न ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग की जो मांग रखी गई है, कुल 17 माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे हैं । जिसमें विपक्ष के भी सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के भी सदस्य हैं और इन माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उनके इस बहुमूल्य सुझाव को हम आगे योजना बनाते समय जरूर इनका ख्याल रखेंगे लेकिन विपक्ष के सदस्यों से बड़ी उम्मीद थी महोदय और खासकर के माले के लोग बैठे हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–25 / पुलकित / 17.03.2025

(क्रमशः)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सी0पी0एम0 के, सी0पी0आई0 के माननीय सदस्य बैठे हैं जिनका गांव और गांवों के गरीबों से ज्यादा मतलब रहता है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं ।

(व्यवधान)

लेकिन इनसे भी ग्रामीण विकास विभाग को जो अपेक्षा थी, महोदय इन्होंने कुछ नहीं कहा । केवल वायुमंडल में बातों को घुमाते रहे और घुमाते–घुमाते उनका समय खत्म हो गया । महोदय, मैं जो सत्ता पक्ष के, जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और आज आर0जे0डी0 के माननीय सदस्य हैं, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूं समीर साहब बैठे हैं, सुरेंद्र राम जी बैठे हैं और शाहनवाज हुसैन साहब बैठे हैं । महोदय, ये भी जब उधर चले गए हैं ।

अध्यक्ष : केवल शाहनवाज हैं । शाहनवाज हुसैन नहीं है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : शाहनवाज साहब बैठे हैं । इधर जब रहते हैं तो भाषा बदल जाती है और उधर जब जाते हैं तो उनके विचार भी बदल जाते हैं । महोदय, इनको भी कुछ कहना चाहिए था कि जब ये मंत्री थे । ये कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ । जब काम नहीं हुआ तो आप मंत्री बनकर क्या कर रहे थे ? आपकी भी जवाबदेही बनती थी कि कुछ काम करना चाहिए । हमने तो काम किया है उसकी उपलब्धि को मैं आपके सामने, आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ । लेकिन अच्छा होता कि माननीय सदस्य कुछ सुझाव देते तो ग्रामीण विकास उसपर अमल करती । आज सदन में गाँव और गाँव के गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग ग्रामीण विकास विभाग है । इस विषय पर सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपनी बात रखी हैं उसको हम ग्रामीण विकास की योजनाओं में आगे ध्यान रखेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा राज्य में चल रही थी और चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, चाहे विपक्ष के सदस्य हों सब लोगों ने अपने जिले स्तर पर जब समीक्षा बैठक हो रही थी, सुझाव लिए जा रहे थे उस समय सभी माननीय सदस्यों ने जो–जो अपने जिले की इम्पोर्टेन्ट सवाल थे, जो उनके क्षेत्र के महत्वपूर्ण सवाल हैं, सबको सुझाव दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को और एक बात सदन को बताना चाहता हूं कि इस बात को बताते हुए प्रसन्नता होगी और बिहार की जनता इस बात को जानती है । माननीय मुख्यमंत्री जी वोट के लिए काम नहीं करते, चुनाव के लिए काम नहीं करते, बिहार की जनता के कमिटमेंट के लिए काम करते हैं और जो कमिटमेंट करते हैं उसको ये पूरा करते हैं । न सत्ता पक्ष का सवाल पूछते हैं,

न विपक्ष का सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं बिहार की जनता का ? बिहार की जनता की खिद्मत करने का उन्होंने संकल्प लिया है उस हिसाब से राज्य की तरक्की के लिए विकास के लिए योजना बनायी है और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं । अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की हैं । माननीय सदस्य भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और जब भारत सरकार ने हमें निर्देश दिया, ये सर्वे कराने के लिए हमको निर्देश मिला भारत सरकार से और भारत सरकार से जब निर्देश मिला तो सभी माननीय सदस्यों को सिर्फ इस सदन के सदस्य नहीं, बगल के जो विधान परिषद के सदस्य हैं और लोकसभा में हमारे जो सांसद हैं और बिहार से मंत्री है सबको एक–एक पत्र मैंने लिखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है और गाँव के गरीबों के लिए काम हो रहा है । कोई गरीब बिना छत का नहीं रहे, बिना घर का नहीं रहे, उनके सर्वे का काम चल रहा है इसमें आपका भी सहयोग चाहिए । हमने सभी माननीय सदस्यों को चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों और हमने सिर्फ पत्र नहीं लिखा, हमारे विभाग के हमारे अधिकारी ने, हमारे सेक्रेटरी ने एक टोल–फ्री नंबर भी जारी किया और कहा कि जिनको भी यह शिकायत है, इस टोल–फ्री नंबर पर आप बताइए और उसकी निगरानी से जांच होगी और निगरानी से जब जांच होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमने तो पूरी पारदर्शिता की और सदन में जो माननीय सदस्य चर्चा करते हैं जो चौराहे पर चर्चा होती है, ये सदन में चर्चा करते हैं । चर्चा तो होनी चाहिए वास्तविकता की, चर्चा तो होनी चाहिए विशेष तौर पर जानकारी की तो सदन में चर्चा होती है चौराहे की । महोदय, हम लोग तो पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार एन0डी0ए0 की सरकार ने पूरी पारदर्शिता लाने का पूरा–पूरा हमने प्रयास किया है । अभी तक उसमें हमें सफलता मिली है लगभग 38 लाख 98 हजार 591 लोगों का नाम आवास–प्लस ऐप पर हम लोगों ने शामिल किया है और अभी इस महीने के आखिर तक यह काम चलता रहेगा । अभी भी मौका है माननीय सदस्य कि जिस गरीब का नाम छूट रहा है, किसी के साथ अगर कोई अधिकारी, कोई हमारे जनप्रतिनिधि, मुखिया अगर उनके साथ भेदभाव करते हैं तो आप जरूर आप बताइए एक भी गरीब को छूटने नहीं दिया जाएगा । एक–एक गरीब का पक्का मकान अपना होगा, अपनी छत होगी, यह हमारे मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे । महोदय, हम तो काम कर रहे हैं उसका नंबर भी हमने जारी किया है टोल–फ्री नंबर और दूसरी बात और बताना चाहते हैं कि हमने अखबार के जरिए, विज्ञापन के जरिए भी इन चीजों को भी प्रकाशित किया है और एक बार प्रकाशन नहीं हुआ है । हम उसकी चर्चा संक्षिप्त में करना चाहते हैं । 28 जनवरी को हमने विज्ञापन प्रकाशित किया, 19

फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया, 20 फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया, 2 मार्च को विज्ञापन प्रकाशित किया, 5 मार्च को विज्ञापन प्रकाशित किया, 13 मार्च को राज्य के जो सभी अखबार है, समाचार–पत्र है, उन समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया । महोदय, हम तो काम कर रहे हैं और अब तक ये कहते हैं कि कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं । महोदय, हम तो कार्रवाई भी कर रहे हैं । हमने अब तक 185 आवास कर्मियों के अनुबंध को रद्द किया है और राज्य में 376 प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी हमने दंड अधिरोपित किया है । हम तो कार्रवाई करते हैं और चार–चार अभी यहां पर जो आवास सहायक है उनके ऊपर प्राथमिक भी दर्ज की है । हम तो काम कर रहे हैं और हमारे काम पर, हमारी एफिसियेंशी पर आप प्रश्न उठाते हैं जो चौराहे पर चर्चा होती हैं वह हमारे लिए अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है । मैं समझता हूँ कि जो सही जानकारी है वह देकर के आगे इन चीजों को लाइएगा तो हमको भी खुशी होगी और आपको भी प्रसन्नता होगी । मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, हमने 86,586 घरों की स्वीकृति दी हैं और 79,645 घरों को हमलोगों ने पूर्ण कराया है । जब राज्य में हमारे जो गरीब लोग थे उनका नाम छूटा हुआ था । मुख्यमंत्री जी ने अलग से इस योजना को बिहार में चलाया । देश का पहला राज्य बिहार था जहां मुख्यमंत्री आवास योजना चलायी गयी । बाद में दूसरे राज्यों ने भी अनुकरण किया है, ऐसी बात है और देश में आज तक एक योजना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलायी है बिहार में ऐसे लोग जो आवास के हकदार हैं, पात्र परिवार हैं और हमारे रामसूरत राय जी ने जिसकी चर्चा की थी । जो आवास के पात्र हैं और उनका सर्वे हो रहा है, उनके पास जमीन नहीं है तो अभी सर्वे होने दीजिए । सर्वे हो जाएगा और सर्वे में उनका नाम आ जाएगा तो उनको भी अगर सरकारी जमीन होगी तो सरकारी जमीन देंगे वहां पर पांच डिसमील, अगर सरकारी जमीन नहीं होगी और जो आवासित हैं, वहीं पर अगर रहना चाहते हैं तो ₹1,00,000/– (एक लाख) रुपया हम राज्य के खजाने से देंगे । यह भी बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है । हम माले के नेताओं से कहना चाहते हैं सी0पी0आई0, सी0पी0(एम0) के नेताओं से कहना चाहते हैं कि अब और कितनी पारदर्शिता चाहते हैं और गरीबों की भलाई की कितनी योजना चाहते हैं ? ये सारी योजनाएं गरीब, गाँव और गाँव के गरीबों से जुड़ी हुई हैं ।

(व्यवधान)

महोदय, हमारी दूसरी योजना है कि 1 जनवरी, 1996 से पहले जिन गरीब लोगों का घर बना था और उन गरीबों का घर रहने लायक नहीं है, उनको भी हम घर बनाने के लिए ₹1,20,000/– (एक लाख बीस हजार) रुपया देते हैं। वे लोग भी अपना पूरा घर बनाकर अच्छे से रहेंगे और एक

योजना की हम और चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना । जिसकी भी चर्चा हमारे माननीय सदस्य ने सदन में की है आवास सहायता योजना की । यह भी बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है । मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना 1 अप्रैल, 2010 से पहले जिनके आवास निर्माण हुए हैं और वे आवास आधे–अधूरे रह गये, पूरा नहीं हो सके, गरीब आदमी का पैसा दवाई में, दूसरे काम में खर्चा हो गया । उसको भी राज्य के खजाने से ₹50,000/– (पचास हजार) रुपया देने का काम बिहार की सरकार करती है । आपको तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए थी, धन्यवाद देना चाहिए था लेकिन आपने तो आलोचना में ही समय गुजार दिया। समय गुजारते रहिए उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है, हम आलोचना सुनने वाले लोग हैं और जहाँ गलती होती है उसमें हम लोग अपनी आलोचना को, जो आलोचना करते हैं उसमें सुधार का भी काम करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मनरेगा की भी चर्चा माननीय सदस्यों ने की हैं । कई लोगों ने तो कहा कि मनरेगा कहां चल रहा है पता नहीं चला रहा ? कई माननीय सदस्यों ने कहा कि धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब जानने का तो समय नहीं है हमारा लेकिन आपसे जरूर, आप मंथन जरूर कीजिएगा कि बिहार में मनरेगा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 22,05,000 (बायीस लाख पांच हजार) से ज्यादा हमने मानव दिवस सृजन किया है ।

(क्रमशः)

टर्न–26/अभिनीत/17.03.2025

..क्रमश..

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : और महोदय, हमने काम किया है बिहार में, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में हमें 17 करोड़ का लक्ष्य मिला था और हमने 22 करोड़ 05 लाख मानव दिवस बिहार में सृजन किया है । महोदय, हम काम नहीं कर रहे थे, यह पैसा जा कहां रहा है । ये काम कहां हो रहे हैं । हमको गरीबों की चिंता है । राज्य में गरीब कैसे ऊपर उठें, उनकी कैसे तरक्की होगी । आंगनबाड़ी में किसके बच्चे पढ़ते हैं । आंगनबाड़ी में गांव के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं । हमने उसकी भी चिंता की है और हम 01 हजार 740 आंगनबाड़ी का निर्माण करा रहे हैं । महोदय, 01 लाख 991 पशु शेड का निर्माण कराया है । अभी कह रहे थे, मुन्ना जी तो चले गये, कह रहे थे कि पशु शेड के निर्माण का काम बंद हो गया । निर्माण का काम बंद नहीं हुआ है लेकिन गांव के जो गरीब हैं, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, बकरी पालन से जुड़े हैं उन

गरीबों को प्रॉयोरिटी हमने दिया है और कहा है कि सबसे पहले ये जो बकरी पालन करने वाले, मुर्गी पालन करने वाले जो गरीब परिवार हैं उनका यह काम सबसे पहले शुरू करेंगे । हमने किसी योजना को बंद नहीं किया । दूसरी बात कहना है कि गांव और गांव की गरीब महिलाओं के लिए हम मीटिंग भवन बना रहे हैं जिसका नाम जीविका भवन है । 227 जीविका भवन का भी राज्य में निर्माण करा रहे हैं । महोदय, राज्य में खिलाड़ियों की चर्चा किये, कितने पहले खेल मैदान थे और बहुत सारे माननीय सदस्य कह रहे थे, प्रश्न में भी कह रहे थे कि कोई खेल मैदान नहीं बन रहा है । माननीय सदस्य को हम विश्वास दिलाते हैं कि ग्रामीण विकास की तरफ से जितने खेल मैदान जिनके क्षेत्र में बन रहे हैं सबको अलग से पत्र लिखेंगे तब इनको पता चलेगा । ये तो जाते नहीं हैं, इधर–उधर से घुमकर आ जाते हैं, जब पत्र लिखेंगे तो ये जायेंगे । राज्य में 6859 खेल मैदान का भी निर्माण हो रहा है । माननीय सदस्य इस बार होली में गये होंगे तो हो सकता है कुछ घुमे होंगे और नहीं घुमे हैं तो सदन की समाप्ति के बाद एक बार जरूर क्षेत्र का भ्रमण कर लीजिएगा तब अंदाज लग जायेगा कि किस तरह से राज्य में खेल मैदान बन रहे हैं । गांव के नौजवान, गांव के बच्चे जो खेत में खेलते थे, गेहूं के खेत में खेलते थे, जो सरसों के खेत में खेलते थे उनको खेल मैदान बनाकर के उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है । यह देश का पहला राज्य है जहां इतने बड़े पैमाने पर एक बार में खेल मैदान बन रहे हैं, एक बार इतना किसी राज्य में नहीं बना ।

जल–जीवन–हरियाली योजना के बारे में भी चर्चा कर रहे थे । ये तो ग्राम पंचायतों में हमलोगों ने बनाया है । हमने पौधे लगाये हैं, ये गवाह हैं । ये सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग सब मिलकर जल–जीवन–हरियाली योजना चलाने का फैसला लिये और 18 हजार लंबी मानव श्रृखंला बनी और पांच करोड़ से ज्यादा बिहार के युवा–युवती, नौजवान मिलकर मानव श्रृखंला बनाये, पूरे देश को संदेश दिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया । इस तरह का संदेश बिहार से गया । बिहार जलवायु परिवर्तन को रोकने वाला पहला राज्य है जिसने पूरी दुनिया में संदेश दिया । महोदय, जहां तक पौधों की बात करते हैं तो पौधों के बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि आप ग्राम पंचायत में जाइये, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो मुखिया हैं, हमारी वहां पर जो पंचायत समिति है, जिला परिषद् के जो हमारे सदस्य हैं ये पौधा लगाने का काम करते हैं । अभी तक राज्य में 17 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा पौधें बिहार में लगे हैं । महोदय, इस बात का मुझे फक्र है और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, 9 करोड़ से भी ज्यादा इस लक्ष्य को

हमलोग पूरा करने में कामयाबी हासिल करेंगे । इसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह की चर्चा कर रहे थे । महोदय, जब गरीब लोगों को आर्थिक संसाधन दिया जाता है, गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है तब तरह–तरह की बात करते हैं । तरह–तरह की बात नहीं कीजिए । आप देखिए जब बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को शुरू किया बिहार में तो उस समय बिहार में महिलाएं क्या करती थी । बिहार की महिलाएं क्या किसी दफ्तर में जाती थी । क्या बिहार की महिलाएं पंचायत समिति, जिला परिषद् और इस बैठक में शामिल होती थी । इस तरह का काम अगर, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जीविका के माध्यम से इस काम को किया है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यह जो प्रोजेक्ट है, जीविका ड्रिम प्रोजेक्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर हमेशा इसकी मॉनिटरिंग करते हैं । बिहार में 10 लाख 63 हजार स्वयं सहायता समूह अभी तक बने हैं, 01 करोड़ 35 लाख परिवार तक पहुंचे हैं । यह कौन परिवार हैं, ये माले में जाने वाले नहीं हैं । माले वाले लोग और सी0पी0आई0 वाले लोग निश्चित हो जाइये, धनी और धरती बंट के रहेगी और माले और सी0पी0आई0 को छोड़कर, अब धनी और धरती सबका बंटकर रहेगा आपको बताना चाहते हैं, हिस्सा बराबर । आधी आबादी जाग गयी है, अब तो आपके सामने बेरोजगारी की समस्या है । अब लाल कार्ड कौन खोजने जा रहा है इनसे । इनके घर के लिए तो सारा इंतजाम बिहार की सरकार और भारत की सरकार कर रही है । अब इनके पास कौन दरखास्त देने जायेगा । पांच किलो राशन के लिए ये जुलुस निकलवाते थे । इनका जुलुस का भी काम हो गया बंद, अब बेरोजगार हो जाइये माले, सी0पी0आई0 और सी0पी0एम0 के नेता और बाकी कोई लोग गरीब के बारे में सोचते ही नहीं हैं । ये लोग तो गरीब, ललित यादव जी, ये गरीब के बारे में नहीं सोचते हैं । ये तो गरीबों के लिए नहीं ये गरीब का नाम लेते हैं और गरीब का नाम लेकर इनकी पार्टी और इनके नेता सबलोग गरीबों को सताने का काम करते हैं । अध्यक्ष महोदय, राज्य में, अध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में भी जीविका की दीदियों ने काम किया है । 9 लाख 78 हजार से ज्यादा आज कृषि योजना से जुड़ी हैं और कृषि के क्षेत्र में काम कर रही हैं । उनको मशीन दे रहे हैं, उनको बीज दे रहे हैं, उनको खाद अच्छा दिलवा रहे हैं ताकि हमारी दीदियां आत्मनिर्भर हों । पशुपालन के क्षेत्र में, सुन लीजिए ललित बाबू, पशुपालन के क्षेत्र में 9 लाख 78 हजार 737 परिवार अभी तक शामिल हैं और सहरसा के माननीय सदस्य हैं, माननीय हमारे बिजेन्द्र बाबू हैं, सहरसा में हमलोगों ने एक काम किया है, वहां पर सहरसा में दुग्ध उत्पादन समिति बनाकर दुग्ध संग्रह का कार्य कर रहे हैं और इस तरह से शुद्ध दूध एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य वर्द्धक व्यंजन बनाकर हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं । हमारे पशुपालन से 9 लाख 78 हजार महिलाएं जुड़ी हैं । गैर कृषि के

क्षेत्र में 2 लाख 63 हजार 200 परिवारों को शामिल किया है, समाज की मुख्यधारा से जोड़ा है और इनको नयी रोशनी के लिए, नई जिंदगी जीने के लिए आत्मनिर्भर बनाने का काम जीविका की दीदियों का हम लोग कर रहे हैं । मत्स्य पालन के क्षेत्र में 754 लोगों को रोजगार मिला । जो तालाब दे रहे हैं उसमें मिला है 754 जीविका दीदियों को रोजगार । मुर्गी पालन के क्षेत्र में 2 लाख 7 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया । बकरी पालन के क्षेत्र में 6 लाख 29 हजार परिवारों को हमने काम दिया । मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग हॉस्टल और हॉस्पिटल में जो जीविका दीदियों की रसोई है उसमें 4 हजार 468 को काम दिया । दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 01 लाख 42 हजार को और पशुपालन से जो रोजगार मिले हैं 9 लाख 78 हजार लोगों को, मधुमक्खी पालन से 11 हजार 288 लोगों को, गैर कृषि कार्य से 2 लाख 63 हजार लोगों को, कृषि कार्यों से रोजगार 38 लाख 12 हजार लोगों को, सिलाई–कटाई से 01 हजार 445 लोगों को और गौ मेला से 62 हजार 553 लोगों को रोजगार मिला । आर0सी0टी0 के माध्यम से जो उनको रोजगार मिला है, 02 लाख 40 हजार से ज्यादा और सतत जीविकोपार्जन से 02 लाख 01 हजार हमने उनको रोजगार दिया है । बैंक सखी के रूप में 6 हजार 109 लोगों को हमने राजगार दिया है, पशु सखी के रूप में 01 हजार लोगों को रोजगार दिया है । ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास योजना से 04 लाख 10 हजार 145 लोगों को रोजगार दिया है, तो रोजगार के क्षेत्र में भी ग्रामीण विकास पीछे नहीं है । ग्रामीण विकास भी आगे काम कर रहा है ।

..क्रमशः..

टर्न–27 / हेमन्त / 17.03.2025

श्री श्रवण कुमार : (क्रमशः) अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रखण्ड में जॉब फेयर लगाकर हमने जो काम किया 62 हजार से ज्यादा लोगों के लिये । एक बात शांति से सुन लीजिए। यह जो जीविका के बारे में आप बोलते हैं, समझिये । अभी पटना जिला के फतुहा प्रखंड के पंचायत का भी नाम बता रहा हूं, मानसिंहपुर पंचायत है, इनिओ गांव है सुश्री सृष्टि कुमारी को गोवा में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में केबिन क्रू का कार्य कर रही है और पटना जिला के अंतर्गत प्रखंड दुल्हिन बाजार की ईशा कुमारी सिंह को दुबई में इमिरेट्स फ्लाईट में एयरलाईन केबिन क्रू का कार्य कर रही है । आज उनके माता–पिता बहुत खुश हैं । मजदूरी पर आधारित थे, गांव के गरीब लोग थे । इस बात की खुशी आपको होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

सतत जीविकोपार्जन योजना, सुन लीजिए । सतत जीविकोपार्जन योजना में दारू बेचकर, ताड़ी बेचकर और जो परिवार हाशिये पर था, दो लाख एक हजार परिवार को चिन्हित किया है और उनको नयी जिंदगी की शुरूआत करने के लिए, वैकल्पिक रोजगार के लिए उनको हम लोगों ने सरकार के खजाने से दो–दो लाख रूपया देने का काम कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

आप लोग नहीं सुनियेगा । आप लोग सही बात सुनने के आदी नहीं हैं । आपकी भी बात बोलेंगे । इधर–उधर की बात करते रह गये ।

अध्यक्ष : श्रवण बाबू, जारी रखिये ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दो टाईम की रोटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की दवाई के लिए किसी महाजन के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ती है । तो जब हाथ नहीं पसार रहे हैं महाजन के सामने, तो आप कहां से टिकियेगा । आपको तो भागना ही है । भागेंगे ही ।

(व्यवधान)

एक बात और सुन कर जाइये अरूण बाबू, बहुत अच्छी बात है । आपके फायदे की बात है । बिहार में जीविका का काम देखने के लिए विदेश की टीम आ रही है और पांच–पांच देश से टीम आयी है और पांच देशों से जो टीम आयी है, वह कोई मामूली टीम नहीं है । वह टीम इंडोनशिया के मिस्टर महेल्दी, गवर्नर, पश्चिमी सुमात्रा, इंडोनेशिया की टीम है । फिलीपींस की सरकार के श्रम कल्याण मंत्रालय के मंत्री, मिस्टर रायेसा, असिस्टेंट सेक्रेटरी, श्रम कल्याण मंत्रालय आये हैं । इथोपिया सरकार के मंत्री आये हैं । दक्षिण अफ्रीका के समाज कल्याण मंत्री आये हैं । रंवाडा सरकार के डायरेक्टर जनरल भी आये हैं महोदय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

महोदय, इस प्रकार जीविका का काम देखने के लिए भारत के अलावा दूसरे देश से भी आ रहे हैं । आते हैं और उसकी प्रशंसा करके जाते हैं और सिर्फ प्रशंसा ही नहीं करते हैं, वह कहते हैं कि इसको अपने देश में लागू करने के लिए वहां की सरकार को जरूर इस बात के बारे में बतायेंगे कि किस तरह से

गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में बिहार और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने काम किया है । महोदय, इनको सुनना पसंद नहीं है । मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं ।

महोदय, जो महत्वपूर्ण कुछ काम किये हैं बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार देश का पहला राज्य है, जहां लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा–निर्देश में एक साथ 6714 ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल मैदान का निर्माण किया । देश का पहला राज्य बिहार है, जहां जल वायु परिवर्तन को रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनायी गयी । जल–जीवन–हरियाली योजना चलायी गयी, पांच करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए, 18 हजार किलोमीटर लंबी कतार में मानव श्रृंखला बनी । पूरी दुनिया में यह हमारा इतिहास है महोदय । देश का पहला राज्य बिहार है, जहां 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बनाये गये जिसमें 13500000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल चल रही है । देश का पहला राज्य बिहार है, जहां आवास के हकदार, भूमिहीन उन्हें राज्य के संसाधन से एक लाख रूपया जमीन खरीदने के लिए देते हैं । महोदय, राज्य में एक साथ 440 प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है । बिहार के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एकसाथ योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए, काम करने के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को गाड़ी उपलब्ध करायी गयी है । बिहार में गरीब की चिंता करते हुए ग्रामीण विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथ तीन लाख गरीबों को एक बार 40–40 हजार रूपया उनके खाते में हस्तांतरित किया गया । देश का पहला राज्य जहां दो लाख एक हजार सतत जीविकोपार्जन में शामिल करके उनके जीवनस्तर में बदलाव लाने के कोशिश की गयी है । महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा–निर्देशन में युवाओं को नौकरी व रोजगार देने के लिए काम किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है 2025 में 12 लाख लोगों को नौकरी, 34 लाख युवक–युवतियों को रोजगार का बड़ा अवसर 2025 में मिलेगा । बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है । आगे 2025 में भी नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बनेगी । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ जी जो कटौती प्रस्ताव लाये हैं, वापस लेने का अनुरोध करता हूं ।

(माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग का लिखित वक्तव्य–परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष–2515, उप मुख्य शीर्ष–00 के लिए 851,57,00,000/– रूपये की मांग 5,00,00,000/– रूपये से घटायी जाय।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 16093,45,98,000/– (सोलह हजार तिरानवे करोड़ पैंतालीस लाख अंठानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–37 है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

अध्यक्ष महोदय,

राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 2016–17 से 2022 तक में बिहार को 37 लाख 1 हजार 38 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें अबतक 36 लाख 58 आवास को पूर्ण कराया गया है शेष जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार को 7 लाख 90 हजार 6 सौ 48 लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें 6 लाख 88 हजार 2 सौ 33 की स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्रथम किस्त में 5 लाख 15 हजार 3 सौ 53 लाभुकों को दिया गया तथा 3 लाख परिवार को एक बार में खाते में 40 हजार रूपया दिया गया। 53 हजार घर पूर्ण हो गया है शेष में काम तेजी से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

ग्रामीण विकास के ऊपर गरीबों को बड़ा भरोसा है, हर गरीब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग कृत संकल्पित है ।

अध्यक्ष महोदय,

भारत सरकार के दिशा निर्देश पर 10 जनवरी से 31 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सर्वेक्षण का आरंभ किया है तथा बड़ी तेजी के साथ सर्वेक्षण कार्य चलाया जा रहा है, अब तक 38 लाख 98 हजार 5 सौ 91 आवास प्लस ऐप पर नाम जोड़ा गया। 10 दिन शेष रह गया। कोई गरीब छूटे नहीं उसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही सभी माननीय सदस्यों को पत्र लिखकर अनुरोध किया हूँ। कोई गरीब छूटे नहीं इसके पूरी आपके स्तर पर कोशिश होनाचाहिए। साथ ही समाज में पारदर्शिता लाने हेतु एवं जनता में जागरूकता के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है तथा किसी भी कर्मी/पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की अनियमिता बरतने पर इसके लिए निगरानी विभाग का टॉल फ्री नम्बर 1064, मोबाईल नम्बर 7765953261, टेलीफोन नं0–0612–2215344 ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से जारी किया गया है तथा अनेकों समाचार पत्रों के माध्यम से कई दिनों तक विज्ञापन जारी कर प्रचार–प्रसार कर गड़बड़ी एवं शिकायत से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। यथा :–

अध्यक्ष महोदय,

(i) दिनांक 28 जनवरी, 2025 को दो समाचार पत्र–हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर में।

(ii) 19 फरवरी, 2025 को चार समाचार पत्र–हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, टाईम्स ऑफ इंडिया एवं कौमी तंजीम में।

(iii) 20 फरवरी, 2025 को चार समाचार पत्र–आज, प्रभात खबर, दैनिक भाष्कर एवं हिन्दुस्तान टाईम्स में।

(iv) 02 मार्च 2025 को चार समाचार पत्र–हिन्दुस्तान, दैनिक भाष्कर, टाईम्स ऑफ इंडिया एवं कौमी तंजीम में।

(v) 05 मार्च 2025 को चार समाचार पत्र– दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, दैनिक भाष्कर एवं प्रभात खबर।

(vi) 13 मार्च 2025 को तीन समाचार पत्र– हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवंटाईम्स ऑफ इंडिया में माप दंड के अनुकूल ही पात्र परिवार का नाम जोड़ा जाना है, इस संबंध में पूरी जानकारी दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में अबतक 185 आवास कर्मियों की अनुबंध समाप्त किया गया है। राज्य में 376 प्रखंड विकास पदाधिकारी पर दंड अधिरोपित की कार्रवाई की गयी है।

○ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना

अध्यक्ष महोदय,

देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुरूआत किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 86 हजार 5 सौ 86 घर की स्वीकृति दी गयी है तथा 79 हजार 6 सौ 45 घर पूर्ण कराया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ आवास के पात्र परिवार के पास जमीन नहीं है, वहाँ पर सरकारी जमीन भी नहीं है, उन्हें 1 लाख रूपया जमीन खरीदने तथा 1 लाख 20 हजार रूपया मकान बनाने के लिए, 12 हजार रूपया शौचालय के लिए तथा जॉब कार्डधारी मजदूर को मनरेगा से 90/95 दिन का मजदूरी के रूप में 22 हजार 50 रूपया दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ 1 जनवरी 1996 से पहले दलित महादलित एवं अति पिछड़े वर्ग के घर बने थे परन्तु वर्तमान में उनका घर रहने के लायक नहीं है उनको राज्य सरकार के तरफ से घर निर्माण 1 लाख 20 हजार देकर घर बनवाया जा रहा है।

<u>मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना</u>

अध्यक्ष महोदय,

1 अप्रैल 2010 के पूर्व जिनके घर की स्वीकृति दी गयी और उनका पैसा बीमारी या किसी अन्य कार्य में खर्च हो गया है तथा उनका घर आधा–अधूरा रह गया है उनके घर को पूर्ण कराने के लिए 50 हजार रूपया अतिरिक्त राशि राज्य के संसाधन से दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय,

भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का निदेश है कि कोई गरीब का नाम छूटे नहीं हर परिवार को अपना पक्का मकान हो, अपना छत हो। इसी को डबल इंजन की सरकार कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय,

आज सदन में गाँव और गाँव के गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग ग्रामीण विकास की मांग रखी गयी है, इस विषय पर सदन में माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया तथा जिन माननीय सदस्यों ने सार्थक सुझाव दिया है उनका मैं स्वागत करता हूँ। कुछ माननीय सदस्यों ने इधर–उधर की चर्चा कर सदन का समय बर्बाद कर दिया है। इनके क्षेत्र के लोग टेलीविजन पर जब इन्हें देख रहे होंगे तब समय आने पर आगामी चुनाव में जनता इनका हिसाब–किताब करेगी।

मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना)

अध्यक्ष महोदय,

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में भारत सरकार ने बिहार को श्रम बजट में 17 करोड़ का लक्ष्य दिया लेकिन अबतक 22 करोड़ 87 लाख से ज्यादा मानव दिवस सृजन बिहार ने किया है जो कि लक्ष्य का 134.52 प्रतिशत है। वर्ष 2023–2024 में भी लगभग 22 करोड़ 5 लाख मानव दिवस करने वाला बिहार है।

अध्यक्ष महोदय,

आंगनवाड़ी भवन का निर्माण गाँव के गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए मनरेगा योजना से 1 हजार 7 सौ 40 आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण की दिशा में काम चल रहा है। सिर्फ हम गरीबों का नाम नहीं लेते बल्कि उनके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। गरीबों के लिए पशुपालकों के लिए पशु सेड का निर्माण किया जा रहा है। 1 लाख 911 पशु सेड की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य दिशा में काम हमारे पशुपालक कर रहे हैं तथा बड़े पैमाने पर मुर्गी सेड का भी निर्माण का कार्य जारी है।

अध्यक्ष महोदय,

गाँव एवं गाँव की गरीब महिलाएं जो जीविका से जुड़े उनके मिटिंग एवं कार्यालय के लिए 227 जीविका भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया है तथा भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए **''मेडल लाओ और नौकरी पाओ''** योजना को शशक्त बनाने के लिए तथा ग्रामीण युवाओं को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु बिहार सरकार एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मनरेगा योजना से 6 हजार 8 सौ 59 खेल मैदान का निर्माण कार्य चल रहा है जो जल्द ही राज्य के खिलाड़ी युवा एवं युवतियों के हवाले कर दिया जायेगा।

जल–जीवन–हरियाली योजना

अध्यक्ष महोदय,

बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पहल एवं दिशा निर्देशन में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बिहार में जल–जीवन–हरियाली योजना चलाने का फैसला लिया गया । इस काम को गति देने के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने मिलकर अभियान चलाने का निर्णय लियें और बिहार देश का पहला राज्य है, जहाँ लगभग 18 हजार किलोमीटर की लम्बी कतार में 5 करोड़ लोगों ने हाथ में हाथ जोड़कर मानव श्रृंखला बनाया और पुरे दुनियां को संदेश दिया कि जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे तथा बिहार में जल–जीवन–हरियाली योजना चलायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में जितने भी तालाब, आहर, पैन, पोखर, छोटी नदियों है, के गाद को निकालकर जल श्रोत को बढ़ायेगें तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम आरम्भ की गयी, साथ ही कुआं, चापाकल के पास सोख्ता का भी निर्माण बड़े पैमाने पर कराया गया ।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में बड़े पैमाने पर पौधाशाला का निर्माण के साथ अब तक राज्य में 17 करोड़ 80 लाख से ज्यादा पौधा लगाया गया, जिससे हरियाली बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होने से हो रहे नुकसान में कमी आयी और भी इस कमी को दूर करने हेतु राज्य सरकार के तरफ से सौर्य ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है ।

अध्यक्ष महोदय,

सदन के सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि राज्य में हरियाली परत बढ़ाने के लिए अपने माता–पिता तथा बच्चों के जन्म दिवस पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने का संकल्प लें तथा लोगों को प्रेरित भी करें । समाज में जन प्रतिनिधियों का बड़ा महत्व है, इनका प्रयास होगा तो सफलता मिलने में और आसानी होगी ।

स्वयं सहायता समूह (जीविका)

अध्यक्ष महोदय,

जीविका परियोजना बिहार के लोकप्रिय **मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी** के दिशा निदेश पर राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के विशेष अवसर प्रदान करने तथा बच्चों की दवाई, पढ़ाई तथा दो जून की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए जीविका के माध्यम से **10 लाख 63 हजार स्वयं सहायता समूहों** का गठन किया गया है, **1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा परिवारों** को इसमें शामिल किया गया है। ग्राम संगठन की संख्या **71 हजार 2 सौ 29 है। संकुल संघ की संख्या 1 हजार 6 सौ 73 है** ।

अध्यक्ष महोदय,

सदन में इसे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी** के निदेश से शहरी क्षेत्र के गरीब महिलाओं को भी स्वयं सहायता समुह में **34 हजार 9 सौ 90 समूह** का गठन किया गया है, तथा **3 लाख 61 हजार 3 सौ 33 परिवार** को जोड़ने का काम किया गया है। गरीब महिलाएं जो शहरी क्षेत्र में काम के अभाव में परेशान थी उनके

परिवार के सामने जो समस्या थी इसका हल करने की पहल की गयी।

<u>अध्यक्ष महोदय,</u>

कृषि के क्षेत्र में **9 लाख 78 से ज्यादा परिवार को कृषि कार्य** के लिए प्रोत्साहन राशि तथा मशीन के साथ–साथ उत्तम गुणवत्ता वाला बीज, जैविक खाद की सुविधा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की पहल है।

<u>अध्यक्ष महोदय,</u>

पशुपालन से जुड़े लगभग **9 लाख 78 हजार 4 सौ 37 परिवार** शामिल हैं। सहरसा जिला में कौशमी दुग्ध उत्पाद सहायोग समिति बनाकर दूध संग्रह का कार्य कर रही है तथा तरह–तरह का शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण, स्वास्थवर्द्धक व्यंजन बनाकर आत्मनिर्भर बन रही है।

गैर कृषि के क्षेत्र में अबतक **2 लाख 63 हजार 6 सौ 2 परिवारों** को शामिल कर समाज के मुख्य धारा में जोड़कर उनकी पारिवारिक समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है बल्कि समाज को नई रोशनी दी। स्वयं सहायता समूह के दीदीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गये

जिसके प्रमुख अंग आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ –

अध्यक्ष महोदय,

1. मत्स्य पालन हेतु रोजगार – **7 सौ 54**
2. मुर्गी पालन हेतु रोजगार – **2 लाख 7 हजार**
3. बकरी पालन हेतु रोजगार – **6 लाख 29 हजार**
4. छात्रावास, मेडिकल कॉलेज में दीदी की रसोई से रोजगार – **4 हजार 4 सौ 68**
5. दुग्ध उत्पादन से रोजगार – **1 लाख 42 हजार**
6. पशुपालन से रोजगार – **9 लाख 78 हजार**
7. मधुमक्खी पालन से रोजगार – **11 हजार 288**
8. गैर कृषि कार्यों से रोजगार – **2 लाख 63 हजार**
9. कृषि कार्यों से रोजगार – **38 लाख 12 हजार**
10. सिलाई–कटाई से रोजगार – **1 हजार 445**
11. जॉब मेला से प्राप्त युवाओं को रोजगार – **62 हजार 553**
12. RSETI के माध्यम से रोजगार – **2 लाख 40 हजार**
13. सतत् जीविकोपार्जन योजना से रोजगार – **2 लाख एक हजार**

अध्यक्ष महोदय,

14. बैंक सखी से रोजगार – **6 हजार 109**

15. पशु सखी से रोजगार – **एक हजार**

16. ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास योजना से प्राप्त रोजगार की संख्या – **4 लाख 10 हजार 145**

कुल रोजगार की संख्या– 69 लाख 69 हजार 617

अध्यक्ष महोदय,

बिहार में हर जिला के प्रत्येक प्रखंड में **जॉब फेयर** लगाकर राज्य के बेरोजगार नौजवानों एवं युवतियों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया। राज्य में वित्तीय वर्ष 2024–25 में **121** तथा अब तक कुल मिलाकर **8 सौ 83 जॉब फेयर** लगाई गयी जिसमें ग्रामीण युवाओं एवं युवतियों को **62 हजार 553 से ज्यादा लोगों को विभिन्न तरह के कार्यों** में अवसर प्रदान की गयी है।

पटना जिला अंर्तगत फतुहा प्रखंड के पंचायत मानसिंहपुर के ग्राम– इनिओ की **सुश्री सृष्टि कुमारी** को गोवा में गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में केबिन क्रू का

कार्य कर रही है एवं पटना जिला अंर्तगत ही प्रखंड दुल्हिन बाजार की **ईशा कुमारी सिंह को दुबई में इमिरेट्स फ्लाईट में एयरलाईन केबिन क्रू** का कार्य कर रही है, आज उनके माता–पिता को बहुत अच्छा लग रहा है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज–2

अध्यक्ष महोदय,

स्वच्छता काम बहुत आसान नहीं है। समाज के सभी लोगों को इसमें मदद की आवश्यकता है। जबतक समाज के सभी तपके के लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तबतक इसमें सफलता नहीं मिल सकती है। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप स्वच्छता को बढ़ाने में सरकार और जनमान में लोगों को सहयोग करने की मदद करेंगे।

अध्यक्ष महोदय,

ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबन्धन का कार्य राज्य के हर पंचायत में शुरू की गयी है। **"स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव"** के संकल्प के साथ 8 हजार 53 ग्राम पंचायतों को ओ0डी0एफ0 प्लस बनाया जाना है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में 6 हजार 735 WPU का निर्माण करायागया है, शेष में तेजी से काम चल रहा है। घर–घर से कचरा उठाकर WPU तक लाकर अलग–अलग कर उसे खाद्य निर्माण और प्लास्टिक को प्रोसिंग कर समान निर्माण कार्य कराने के साथ–साथ छोटे खिलौने, गुलदस्ता एवं उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य में 1 लाख 57 समुदायिक शोकपीट का निर्माण कराया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

कृषि एवं पशु अवशिष्ट से निपटारे हेतु 2022–23 में 31 गोवर्धन इकाई निर्माण की दिशा में कार्य चल रहा है, शेष में स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय,

जिस परिवार के पास निजी शौचालय के लिए जमीन नहीं उनके लिए राज्य में अबतक 9 हजार 7 सौ समुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया तथा और भी जगह चिन्हित कर समुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय,

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 2012–13 से अबतक 1 करोड़ 44 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया तथा दूसरे फेज में 5 लाख 92 हजार शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है तथा इनके घरों में शौचालय निर्माण की कार्रवाई चल रही है।

सतत जीविकोपार्जन योजना।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार में जो परिवार ताड़ी, दारू, बेचकर अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे थे एवं जो परिवार हासिये पर खड़ा था तथा जिस परिवार में कमाने वाला व्यक्ति किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, जिस परिवार में दो–तीन बच्चे हैं, पत्नी है दो जून की रोटी बच्चों की पढ़ाई, दवाई की समस्या है, उन्हें बिहार के **लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी** के दिशा–निदेश में 2 लाख 1 हजार से ज्यादा परिवारों को चिन्हित किया गया और राज्य के खजाने से दो–दो लाख रूपया देकर वैकल्पिक रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इन परिवारों को आज दो टाईम की रोटी, बच्चों की पढ़ाई और दवाई के लिए किसी महाजन का सहारा नहीं लेना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय,

साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन परिवारों को दी जा रही है तथा सिर्फ दो लाख रूपया ही नहीं देते बल्कि उन्हें टेक्नीकल सपोर्ट के साथ–साथ समय–समय पर लोन देने की भी व्यवस्था करते हैं ताकि चिन्हित परिवारों का काम ठीक से चल सके। इन परिवार को

हर प्रकार से सहयोग सरकार के तरफ से देते हैं। इन परिवारों को नये सिरे से नई जिन्दगी की शुरूआत कर समाज में नया संदेश दिया है।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार में जीविका का काम देखने के लिए विदेशों से भी टीमें आ रही है। जीविका का काम देखकर वे अपने देश में भी इसे चलाने का संकल्प लेकर जा रहे हैं, बिहार रॉल मॉडल प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है। इसकी चर्चा सिर्फ अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है, जिसका जीता–जागता उदाहरण इस प्रकार है :–

1. **इंडोनेशिया से मिस्टर महेल्दी, गवर्नर, पश्चिमी सुमात्रा, इंडोनेशिया की टीम** ने गया जिला का भ्रमण किया और वहाँ सत्त जीविकोपार्जन योजना के लाभान्वित परिवारों से मिलकर उनके कार्यो को देखा।

2. **फिलीपींस सरकार के श्रम कल्याण मंत्रालय के मंत्री, मिस्टर रायेसा, असिसटेंट सेक्रेटरी, श्रम कल्याण मंत्रालय, फिलीपींस एवं एडवाईजर सिमटर सिन्टायेउ के** की टीम भी बिहार आकर समुदाय कैडर की भूमिकाओं और लाभार्थी से संबंध पर विशेष ध्यान दिया ।

3. **इथोपिया सरकार के कृषि मंत्री, मिस्टर गिरिमा बकेले वाकजीर एवं एडवाईजर सिमटर सिन्टायेउ के प्रतिनिधि** बिहार के वैशाली जिला आकर अत्यन्त गरीब परिवारों का सहयोग प्रदान करने में मास्टर रिर्सोस पर्सन की भूमिका की सराहना किया ।

4. **दक्षिण अफ्रीकी सरकार की समाज कल्याण मंत्री डॉ0 मबुलाहनी एवं मिस्टर मौरीन मोगओटसी उप मंत्री, समाज कल्याण मंत्रालय, दक्षिण अफ्रीका के टीम** ने वैशाली जिला का भ्रमण किया और लोगों से मिलकर समस्याओं के निराकरण और समाधान देखकर काफी प्रसन्नता जाहिर किया ।

5. **रंवाडा सरकार के डायरेक्टर जनरल, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटिटीज डेवलपमेंट एजेंसी एवं मिस्टर गोडफ्रे, डायरेक्टर जनरल, लोडा की टीम** आकर एस0जे0 वार्ड में लक्षित रणनीतियों, संपति, स्थानांतरण, दक्षता निर्माण और निगरानी पर ध्यान केन्द्रीत किया तथा सरकारी योजनाओं के अभिसरण कर प्रक्रिया को समझने में विशेष रूचि दिखायी ।

अध्यक्ष महोदय,

विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों ने बिहार में पॉच देश से आकर सतत् जीविकोपार्जन के योजना के कार्यो को देखा और सराहना किया तथा अपने देश में इस

तरह के गरीबों के उत्थान के लिए अपने देश के सरकार को सुझाव दे और ऐसी महत्वपूर्ण कार्य से अपने देशों को लाभान्वित होने का अवसर लोगो को मिले।

जीविका दीदीयों को रोजगार के क्षेत्र में अव्वल बनाने तथा हर क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने की दिशा में हमारी सरकार ने पहल किया।

अध्यक्ष महोदय,

विपक्ष के लोग सिर्फ गरीब का नाम लेते हैं, और गरीब के हक के लिए काम नहीं करते, जब से बिहार की जनता ने श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया तब से अब तक गरीबों का भरोसा बढ़ा है, इन गरीबों को मालूम है कि गाँव के गरीब के घरों में बिजली मिली, शौचालय मिला, पक्की नली–गली मिली, हर घर में पीने का शुद्ध पानी मिला, जब–जब काम मांगा काम मिला, हर राशन कार्डधारी को 5 किलोग्राम अनाज मिला, हर गरीब को पक्का मकान मिला, छात्र युवाओं को रोजगार मिला, लाल झंडा उठाते हैं और नारा देते हैं ।

धन और धरती बटके रहेगा, कम्यूनिष्ट नेताओं को छोड़ के । यह इनकी नीति है ।

o

अध्यक्ष महोदय,

विपक्ष के लोग सिर्फ गरीब का नाम लेते हैं, और गरीब के हक के लिए काम नहीं करते, जब से बिहार की जनता ने श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया तब से अब तक गरीबों का भरोसा बढ़ा है, इन गरीबों को मालूम है कि गाँव के गरीब के घरों में बिजली मिली, शौचालय मिला, पक्की नली–गली मिली, हर घर में पीने का शुद्ध पानी मिला, जब–जब काम मांगा काम मिला, हर राशन कार्डधारी को 5 किलोग्राम अनाज मिला, हर गरीब को पक्का मकान मिला, छात्र युवाओं को रोजगार मिला, लाल झंडा उठाते हैं और नारा देते हैं ।

धन और धरती बटके रहेगा, कम्यूनिष्ट नेताओं को छोड़ के । यह इनकी नीति है ।

प्रखंड सह–अंचल कार्यालय भवन का निर्माण के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में अब तक कुल 82 प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 71 प्रखंडों में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 11 प्रखंडों में कार्य प्रगति पर है ।

राज्य में कुल 99 प्रखंडों में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 97 प्रखंडों में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 02 प्रखंडों में कार्य प्रगति पर है ।

राज्य के कुल 241 (दो सौ एकतालिस) जर्जर अथवा गैर मरम्मति योग्य कार्यालय भवन के कारण नये प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण एवं 62 (बासठ) भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

इस प्रकार राज्य में कुल 484 प्रखंडों में अपना प्रखंड कार्यालय भवन होगा। शेष जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां पर भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे–जैसे भूमि उपलब्ध होगा वैसे–वैसे भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

आधार पंजीकरण

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में 2020 की अनुमानित जनसंख्या लगभग 12 करोड़ 47 लाख के विरूद्ध अबतक 11 करोड़ 93 लाख आधार सृजित किया जा चुका है। लगभग 95.62 प्रतिशत है। 18 वर्ष से उपर के उम्र वाले सतप्रतिशत 5 से 18 वर्ष वाले 77.91 प्रतिशत आधार सृजित है। 0 से 5 वर्ष वाले 14.27 प्रतिशत तथा कल्याण विभाग के तरफ से सहयोग प्रदान की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में आधार केन्द्र खोले गये हैं। जिला के अनुमंडल/प्रखंड के साथ–साथ नगरनिगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में 1 हजार 10 केन्द्र की स्थापना की गयी है।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पहल पर विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गयी है। उक्त संस्थान के माध्यम से राज्य में उच्च ज्ञानप्रदायी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में निर्माण कराया जा रहा है।

. ʼ ○

<u>ग्रामीण विकास विभाग में सरकारी नौकरी</u>

आर0डी0ओ0 की बहाली–

वर्ष 2013 में– 533

वर्ष 2018 में– 22

वर्ष 2019 में– 13

वर्ष 2021 में– 130

वर्ष 2022 में– 126

वर्ष 2023 में– 133

वर्ष 2024 में– 07

<u>वर्ष 2025 में– 393 अधियाचना भेजी गयी</u>

कुल :– 1 हजार 357

2024–25 में संविदा पर 22 नियोजन किया गया एवं 42 प्रक्रियाधीन है।

2025–26 में 03 हजार 943 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का वर्ष 2025 तक 12 लाख नौकरी तथा 38 लाख रोजगार देने का संकल्प है।

- **बिहार में नौकरी एवं रोजगार की बहार है।**
- **बिहार के मुख्यमंत्री नीतीशे कुमार हैं।**
- **बिहार और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है।**
- **2025 में फिर से नीतीश ।**

अतः कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य वापस लें।

सदन से अनुरोध करता हूँ कि ग्रामीण विकास के द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या–42 को गाँव और गाँव के गरीब लोगों के हित में पारित करने की कृपा की जाय।

जय बिहार **जय भारत**

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगें कि ''ग्रामीण विकास विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 16093,45,98,000/- (सोलह हजार तिरानवे करोड़ पैंतालीस लाख अंठानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

<u>राज्य में किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्य–</u>

1. बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा–निर्देशन में एक साथ 6 हजार 7 सौ 14 ग्रामीण बच्चों के प्रतिभा को विशेष अवसर प्रदान कर खेल मैदान का शुभारम्भ किया गया।
2. देश का पहला राज्य बिहार जहाँ जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गयी और जल–जीवन–हरियाली योजना चलाई गयी इसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए तथा 18 हजार किलोमीटर लम्बी कतार लगी ।
3. देश का पहला राज्य बिहार जहाँ 10 लाख 63 हजार स्वयं सहायता समूह बनायी गयी जिसमें 01 करोड़ 35 लाख महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया गया है।
4. देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ आवास के हकदार भूमिहीन हैं उन्हें राज्य के संसाधन से 01 लाख रूपया जमीन खरीदने के लिए दी जाती है।

5. राज्य में एक साथ 303 प्रखण्ड –सह– अंचल कार्यालय को भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।
6. बिहार के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एक साथ योजनाओं का मॉनिटरिंग के लिए नई गाड़ी विभाग के तरफ से दी गयी।
7. बिहार में गरीबों की चिन्ता करते हुए ग्रामीण विकास विभाग में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों 3 लाख गरीब परिवारों को 40–40 हजार रूपये उनके खाते में आवास निर्माण के कुल राशी भेजी गयी।
8. देश का पहला राज्य है जहाँ दो लाख 01 हजार परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत दो–दो लाख रूपया रोजगार के लिए दी गयी।
9. माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा–निर्देशन में बिहार के युवाओं को नौकरी एवं रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

   12 लाख नौकरी तथा 34 लाख युवा–युवतियों को रोजगार का बड़ा अवसर वर्ष 2025 में देने का लक्ष्य है।